राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ३४ वां दिवस [संख्या १५

सोमवार,

दिनांक ५ जून, १९६७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(खाद्य, यातायात, समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, वन, कृषि, पंचायत, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, सहकारिता, जन-स्वास्थ्य विभाग)

पाली नगर में अनाज के राशन में वृद्धि

२१६. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली नगर में नागरिकों को राशन कितना किलो प्रति मास किस हिसाब से दिया जाता है ?

(२) क्या यह सत्य है कि पाली में महाराजा श्री उम्मेद मिल्स में तीन हजार मजदूर काम करते हैं ? यदि हां, तो उनको और उनके कुटुम्ब को कितना राशन दिया जाता है ?

(३) क्या यह सत्य है कि जोधपुर शहर में राशन प्रति व्यक्ति पाली शहर से अधिक मिलता है ? यदि हां, तो कितना ?

(४) क्या नगरपालिका पाली ने इस राशन की बढ़ोत्तरी बाबत कलेक्टर, पाली को प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो कलेक्टर ने उन पर क्या कदम उठाये ?

(५) क्या राज्य सरकार पाली शहर में और विशेषकर मजदूरों में राशन कम मिलने के कारण फैले इस असंतोष को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) पाली नगर में नागरिकों को ४ किलो अनाज (२ किलो गेहूँ व २ किलो माईलो) प्रति व्यक्ति प्रति मास दिया जाता है।

(२) पाली में महाराजा श्री उम्मेद मिल्स में लगभग ४,००० मजदूर काम करते हैं। मजदूरों एवं उनके कुटुम्बों को ४ किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति मास दिया जाता है।

(३) जी हां। जोधपुर शहर में राशन ५ किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है।

(४) नगरपालिका पाली की बैठक के प्रस्ताव सस्ते धान की बढ़ोत्तरी बाबत

Page No.2

(श्री परसराम मदेरणा)
दिनांक ४-५-६७ को जिलाधीश महोदय द्वारा प्राप्त हुआ जो विचाराधीन है।

(५) राज्य सरकार की नीति हमेशा अधिक से अधिक सुविधा देने की रही है। इस समय जितना अनाज भारत सरकार से आवंटित होता है, उसमें से प्रति व्यक्ति प्रति माह अधिक अनाज उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पाली शहरों में गिना जायेगा तो जयपुर और जोधपुर क्या कस्बों में गिने जायेंगे?
Pali is a town not a city.

श्री परसराम मदेरणा : जिनकी पॉपुलेशन ५० हजार से १ लाख के बीच में है उन कस्बों में रहने वाले लोगों को ४ किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जायेगा और ऐसे शहर राजस्थान में दो ही हैं—पाली और ब्यावर। इसलिए ब्यावर और पाली को ४ किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज दिया जाता है जब कि जोधपुर को ५ किलो दिया जाता है।

प्रश्न संख्या २१७

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नैक्स्ट, श्री नन्दलाल!

तहसील शाहबाद, किशनगंज में पिछड़े वर्ग पर खर्च

२१८. श्री नन्दलाल (किशनगंज) श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) द्वारा पूछा गया : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील शाहबाद किशनगंज में समाज-कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्गों पर कितनी धनराशि सालाना खर्च की जा रही है, और कितने वर्षों से की जा रही है?

(२) किस-किस माध्यम से यह धनराशि खर्च की जा रही है?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूचना सूची में अंकित है।
(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या यह सत्य है कि जिस काम के लिए रकम दी गई वह काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कई जगह काम पूरे भी हुए हैं और कई जगह अधूरे भी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जितनी राशि खर्च की गयी है उसके अगेन्स्ट सरकार को कितनी रकम के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स प्राप्त हो चुके हैं?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अलग-अलग कॉलोनीज़ बनाई गईं जिसमें १ लाख ४५ हजार ५०० रुपये १९५४-५५ में दिए गये थे। यह अधूरी है क्योंकि प्लान से बड़े घर बनाये गये और रकम कम पड़ गयी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरे प्रश्न का उत्तर यह नहीं है। मैंने पूछा है कि जो रकम दी गई है उसके अगेन्स्ट में सरकार को यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट्स कितने के प्राप्त हो चुके हैं ? (विराम) उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस राशि के सम्बन्ध में सरकार को कितनी रकम के प्राप्त हो चुके हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : काम अधूरा है मैंने निवेदन किया १ लाख ४५ हजार रुपया दिया गया था........(अश्रव्य)

कुछ माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जिसमें छात्रावास भी शामिल हैं और शुरू में मैंने निवेदन किया कि कुछ काम अधूरे हैं इसलिए सारे यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट्स प्राप्त नहीं हुए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि विभाग ने कॉलानीज़ बनाने के लिए और मकान बनाने के लिए व्यक्तिगत आदमियों को भी रुपया एडवान्स किया है और रुपया एडवान्स दिया जाता है वह किश्तों में वापिस किया जाता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : व्यक्तिगत ही एडवान्स दिया जाता है लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वह अपनी सहूलियत के लिए कुछ कमेटी वगैरह जैसी बना लेते हैं और उसकी मार्फत बैंक में रुपया रखकर खर्च करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो १९५६-५७ से इस स्कीम में शहरों में बसाने के लिए रुपया दिया गया है और आज १९६६-६७ तक इन रुपयों के यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट्स प्राप्त नहीं हुए क्या ऐसा माना जाय ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि जो कुछ मकान बनाये गये वह प्लान से बड़े बना लिए गए और ५४ से ५८ तक कलेक्टर की मार्फत यह काम किया जाता था। इसके बाद में माध्यम पंचायत समिति का रहा और उसके बाद में पैसे डिपार्टमेन्टली दिये जाते रहे। तो जिस समय का यह प्लान है उस समय पैसे कलेक्टर की मार्फत दिये गये और उस समय जहां तक मेरे पास सूचना है उसके अनुसार जो इस प्रकार का प्लान था उससे अधिक बड़ा बना लिया और इस कारण वह काम अपूर्ण रहे और उनके यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट्स की कार्यवाही नहीं हो सकी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो आपने मकानों की स्थिति बताई और कुओं के लिए रुपया दिया गया है क्या उनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स प्राप्त हो चुके हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कई मकानों के ही प्राप्त हुए हैं विस्तृत जानकारी मैं इस समय नहीं दे सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं कुओं के संबन्धं में पूछ रहा हूँ ? जो कुओं के लिए रुपया दिया गया क्या वह कुए तैयार हो गए? कितना रुपया दिया गया था और वह काम में आ चुका है. इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स प्राप्त हो गये हैं क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कुछ हुए हैं और कुछ अधूरे हैं।

Page No.4

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूँगा कि आपने इस विभाग को अभी संभाला है। यह वही शाहबाद क्षेत्र हैं जो चर्चा का विषय रहा है। लाखों रुपया एडवान्स के रूप में दिया गया है, लेकिन जो रुपया दिया गया है न तो वह शहरियों के पास पहुँचा है और न आपको उसके एचीवमेन्ट्स ही दिखाई देंगे। वहां पर कुएं एक एक हाथ गड्ढे के हैं और मकान वहां तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र शाहबाद और किशनगंज के अन्दर विभिन्न २ कार्यों के लिए रुपया दिया गया है उसका उपयोग हुआ या नहीं उसके बारे में जांच कर लें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मै खुद महसूस करता हूँ कि यह अपूर्ण कार्य रहना ठीक नहीं है यह नहीं रहना चाहिए और इसे बिल्कुल नियमित भी नहीं कहा जा सकता। और इसलिए मैं आपको यह निवेदन कर सकता हूँ कि I will have it fully enquired into and fix the responsibility.

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं आपको अर्ज करूं ....

श्री अध्यक्ष : श्री ललितसिंह !

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपको निवेदन कर दूं कि पुराने कलेक्टर कोटा ने स्वयं ने इसकी जांच की थी और सरकार को रिपोर्ट भी दी थी लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, आप इस सम्बन्ध में स्वयं जांच करें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय में मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ललितसिंह !

बान्सी-बड़ी सादड़ी सड़क का निर्माण

२१९. **श्री ललितसिंह** (बड़ी सादड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बान्सी से बड़ी सादड़ी तक की सड़क का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

(२) बान्सी और बड़ी सादड़ी के बीच कितनी कलवर्ट्स व पुलिया हैं और इनके कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

(३) इस सारी योजना की मन्जूरी कब हुई थी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : बान्सी से बोहेड़ा का हिस्सा पूरा हो चुका है और बोहेड़ा से बड़ी सादड़ी का हिस्सा चौथी योजना में पूरा होगा।

(२) बान्सी से बड़ी सादड़ी तक १ पुलियां और ५ कलवर्ट बनवाने बाकी हैं।

(३) बोहेड़ा से बड़ी सादड़ी के हिस्से की मंजूरी १९६६ में दी गई थी।

प्रश्न संख्या २२०

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२१

श्री अमीलाल यादव !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२२

श्री भगवानदास !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२३

श्री मजलिस खां !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुल हादी !

बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर जिले में सस्ते अनाज की व्यवस्था

२२४. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाड़मेर, जालौर व जैसलमेर जिलों में सस्ते धान की दुकानों पर अनाज पहुंचाने का क्या तरीका है? सरकारी वाहनों से पहुंचाया जाता है या दुकानदार स्वयं अपने साधन से ले जाने का प्रबन्ध करते हैं? जिलेवार अलग अलग बताया जाय।

(२) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सरकारी धान के दुकानदारों का अनाज बाड़मेर के सरकारी गोदाम पर ही दिया जाता है और दुकानदार स्वयं साधन जुटा कर अपनी दुकानों पर गांवों में ले जाते हैं जिससे उसे यातायात का किराया अधिक देना पड़ता है और सरकार निर्धारित दर से किराये की राशि दुकानदार को देती है इससे दुकानदार का घाटा पड़ता है और वह जनता से अनाज का पैसा अधिक वसूल करता है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने का विचार रखती है?

(३) क्या यह सही है कि दुकानदार अनाज ले जाने के बाद जो किराये के बिल पेश करता है उसका भुगतान समय पर नहीं होता है जिससे दुकानदारों व सहकारी समितियों को परेशान होना पड़ता है? यदि हां, तो दिनांक २१-३-६७ को ऐसे यातायात बिलों का भुगतान जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के पास कितने रुपयों का करना बकाया था?

(४) क्या यह सही है कि बाड़मेर के सरकारी गोदाम से सस्ता अनाज रिटेलरों को तोल कर नहीं दिया जाता है और पुराने तोल के आधार पर दिया जाता है जिससे रिटेलरों को बहुत नुकसान होता है और गोदाम कीपर झूठी तकपटियें बनाकर रिटेलर के हस्ताक्षर करवा लेता है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी जांच कराने का इरादा रखती है?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर वायरलेस मसेज देने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि वहां के कलेक्टर यहां मीटिंग में व्यस्त थे।

श्री अध्यक्ष: यस, प्रश्न स्थगित किया गया।

Page No.6

प्रश्न संख्या २२५

श्री देवीलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२६

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री परसराम !

परबतसर में अनुसूचित जाति का छात्रावास

२२७. श्री परसराम (परबतसर) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) परबतसर, जिला नागौर में क्या कोई अनुसूचित जाति का बोर्डिंग हाउस है ? यदि हां, तो क्या उसकी निजी इमारत है ?

(२) इस बोर्डिंग हाउस के लिए सरकारी अनुदान की कितनी राशि हर वर्ष प्राप्त होती है और उसका खर्च क्या किसी कमेटी द्वारा होता है ? अगर संचालन कमेटी है तो किन-किन व्यक्तियों की ?

(३) इस बोर्डिंग हाउस में किन-किन जातियों के कितने लड़कें हैं ?

(४) क्या इस बोर्डिंग हाउस में कोई सुपरिन्टेन्डेन्ट है ? अगर हां, तो क्या वह निर्धारित योग्यता प्राप्त हैं ?

(५) क्या इस बोर्डिंग हाउस के हिंसाब का कभी ऑडिट हुआ है ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) परबतसर में महात्मा गांधी अनुदानित छात्रावास चलाया जा रहा है। छात्रावास का भवन संस्थान का निजी नहीं होने से छात्रावास भवन किराये के मकान में चलाया जा रहा है।

(२) इस छात्रावास को दी जाने वाली अनुदान की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है। छात्रावास का संचालन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसके सदस्यों की सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) इस छात्रावास के सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री नन्दराम हैं जिनकी कक्षा ६ की योग्यता है। छात्रावास अधीक्षक की निर्धारित योग्यता मैट्रिक है किन्तु वे छात्रावास के प्रारम्भ काल से ही कार्य कर रहे हैं।

(५) अनुदानित छात्रावासों के नियमानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा दिनांक २७-११-६६ को इस वर्ष का २२ जून, ६६ का ऑडिट हुआ हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री **खेतसिंह** (शेरगढ़) : इस छात्रावास में कितने लड़के हैं, साहब ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस छात्रावास में ४० लड़के हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

Page No.7

श्री परसराम (परबतसर) : परबतसर शहर का छात्रावास में कोई लड़का है क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : क्या ?

श्री अध्यक्ष : परबतसर शहर का भी छात्रावास में कोई लड़का है क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

प्रश्न संख्या २२८

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२९

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३०

श्री देवीदत्त गाड़िया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २३१

श्री मूलचन्द कटेवा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बनवारीलाल !

पुरानी छावनी-सरानीखेड़ा सड़क को पक्का बनानें का कार्य

२३२. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पुरानी छावनी (धौलपुर) से सरानीखेड़ा ग्राम तक वहां के स्थानीय निवासियों ने श्रमदान से कोई सड़क बनाई है, अगर हां, तो कब और उसकी लम्बाई कितनी है ?

(२) क्या राज्य सरकार इस सड़क को पक्का करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (१) जी हां, १ मील में मिट्टी का काम १९६२ में किया था ।

(२) यह सड़क योजना में मंजूर नहीं है ।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़): यह सड़क १९६२ में बन चुकी थी तो इसको योजना में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह सड़क किसी प्लान में मंजूर नहीं थी, बल्कि गांव वालों ने अपने आप मिट्टी डाल ली थी ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): जो लोग श्रमदान करके सड़क बनाते हैं तो सरकार उनको प्रोत्साहन क्यों नहीं देती है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर कोई कार्य सरकारी मन्जूरी से बनाया जाता है तो उसको प्रोत्साहन दिया ही जाता है और उसमें सरकार मदद करती है ।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली): जब यह सड़क गांव वालों ने बनाली तो फिर इसको आगामी योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तो सन् १९६२ में बनाई गई थी, अब तो ६७ आ गया। पांच साल का समय निकल गया है ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : गवर्नमेंट थोड़े ही बदल गई है ।

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा !

मनोहरथाना में वाटर सप्लाई स्कीम

२३३. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मनोहर थाना कस्बे में वाटर सप्लाई (जल-प्रदाय योजना) कब से प्रारम्भ की गई है एवं वर्तमान में वह किस स्थिति में है ?

(२) उक्त योजना कब तक पूर्ण हो सकेगी ?

उपमंत्री, जन स्वास्थ्य (राव श्री धीर सिंह :(१) मनोहर थाना कस्बे में जल प्रदाय योजना का निर्माण कार्य स्कीम को तकनीकी स्वीकृति जो दिनांक २४-८-६० को की गई थी के तत्पश्चात् हाथ में लिया गया। वर्तमान में कुओं की खुदाई व बिजली की लाइन के अलावा समस्त कार्य पूरे किये जा चुके हैं।

(२) शीघ्र ही पूर्ण करदी जावेगी ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: इस योजना पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है, जिसमें से जनता की तरफ से कितना किया गया और सरकार की तरफ से कितना किया गया ?

राव श्री धीरसिंह : अब तक कुल १लाख २४ हजार रुपया खर्च हुआ है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): जब कुए का काम बाकी है और बिजली सप्लाई का काम भी बाकी है तो फिर कौन सा कार्य पूरा हो गया है ?

राव श्री धीरसिंह : सिर्फ बिजली लगाना और कुए की खुदाई का काम बाकी है। बाकी सब कार्य हो चुका है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: सब कार्यों में क्या-क्या काम हो चुके हैं ।

राव श्री धीरसिंह : जैसे नल लगाना, रिज़र्वायर बनाना आदि काम पूरे हो चुके हैं। वहां पर कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा है । पहले जिसको ठेका दिया गया वह भी तीन साल तक कामयाब नहीं हुआ। दूसरे ठेकेदार को काम दिया गया, वह भी छोड़ कर भाग गया। ठेकेदार के उपलब्ध नहीं होने से अब हम डिपार्टमेंट की तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। और अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के मार्फत भी यह काम पूरा कराने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : पिछले एक साल से वहां पर कितना खर्चा हो रहा है ?

राव श्री धीरसिंह: दुबारा पूछिए, सुना नहीं ।

Page No.9

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : जो वहां पर स्टाफ है, एक चौकीदार, गोदाम पर कार्य करने वाले आदमी वगैरा उन पर माहवारी कितना खर्च हो रहा है ?

रांव श्री धीरसिंह : यह आपने प्रश्न में पूछा नहीं था । आगे पूछेंगे तो बता दूंगा ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि इस छोटी सी योजना को सात साल हो गए हैं और अभी तक काम कम्पलीट नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष : इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है ।

राव श्री धीरसिंह : महसूस तो कर रहे हैं लेकिन क्या करें, ठेकेदार नहीं मिल रहा है आप ठेकेदार बता दें तो उससे काम पूरा करा लें ।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : दूसरी जगहों पर भी ठेकेदार काम छोड़ कर भाग जाता है तो उस के लिए आपकी क्या व्यवस्था है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): सरकार की दिक्कत से तो मेरी एक हद तक सहानुभूति है, लेकिन क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह काम छः महीने में परिपूर्ण कर दिया जायगा ?

रांव श्री धीरसिंह: इसमें अर्ज यह है कि कुए का काम बारिश में तो नहीं हो सकता । बारिश के बाद काम शुरू होकर दिसम्बर के अन्त तक पूर्ण कर देंगे यह मैं कह सकता हूं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: मैं निवेदन करता हूं कि मनोहरथाना कस्बा एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर सैकड़ों आदमी नाहरू और बालों की बीमारी से पीड़ित हैं और वे नदी का पानी पीते हैं । सरकार इस योजना को पूर्ण करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब करती जा रही है । इसलिए मैं आप के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय कम से कम यह तो बता दें कि इसे कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : बता दिया है । नेक्स्ट, श्री रामचन्द्र आर्य !

नोहर से सिरसा सड़क के निर्माण कार्य की प्रगति

२३४. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नोहर से सिरसा (हरियाणा) जाने वाली रोड बन कर तैयार हो चुकी है ?

(२) यदि नहीं, तो कितने अर्से में बन कर तैयार हो सकेगी ?

(३) क्या यह सही है कि इस रोड का ठेकेदार गांव केकाना का रहने वाला है और आर्थिक कमजोरी के कारण रोड का काम रुका हुआ है ?

(४) यदि नहीं, तो इस रोड का ठेका कब हुआ और रोड का कार्य पूर्ण करने की कितनी अवधि दी गई थी ?

(५) क्या यह सही है कि यह रोड केकाना से आगे बिल्कुल नहीं बनी है ?

(६) यदि हां, तो यह रोड कब तक बन कर तैयार हो सकेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (१) जी नहीं।

(२) आशा है काम अगले साल पूरा हो जायेगा।

(३) जी हां काम भूमि अवाप्ति के समय से रुका हुआ है।

(४) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी हां।

(६) आशा है अगले साल काम पूरा हो जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तीन मील के टुकड़े को इतने साल से क्यों रोक रखा है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह टुकड़ा जो है इस वक्त इसलिए पड़ा हुआ है कि जमीन का पूरे तरीके से फैसला नहीं हुआ है और उसकी कार्यवाही चालू है और जल्दी ही पूरी हो जायगी, मगर उसकी प्रोग्रेस चालू है। अभी उसके लिए काम चालू जरूर रख रखा है इस तीन मील के बीच के टुकड़े का।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस ठेकेदार को गंगानगर में सबसे ऊंची और हाई रेट पर ठेका दिया गया था और वह जानबूझ कर काम नहीं कर रहा है और लोगों को लड़ा रहा है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह इस समय नहीं कहा जा सकता कि सब से ऊंची रेट पर ठेका था या कैसे था। वह मालूम करके बता दूंगा, लेकिन यह बात मालूम जरूर कर लूंगा कि क्या ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार है कि वह जमीदारों को और किसानों को लड़ा रहा है। इसकी उस पर जिम्मेदारी है या वाकई में जमींदार आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों में यह सड़क पूरी हो जायगी, क्योंकि यह हरियाणा से मिलाने वाली सड़क है और इसके कारण बसों के जाने में रुकावट पैदा हो रही है और लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने अर्ज किया कि अगले साल तक कतई पूरी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पृथ्वीसिंह !

पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा बीज-वितरण

२३५. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुमेरपुर, जिला पाली में गत रवी की फसल का बीज, समिति के गोदाम में से गायब हो गया ?

(२) अगर हां, तो बीज की जिन्स एवं मात्रा क्या थी ?

(३) उसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम भी बताने की कृपा करें ?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी हां।

(२) गेहूँ १४८ क्विन्टल, ४१ किलो, ३०० ग्राम, जौ १६ क्विन्टल, २३ किलो, ३०० ग्राम।

(३) श्री मदनलाल जैन, ग्रामसेवक व श्री कंचनलाल जैन, कृषि लेखा लिपिक प्राइमा-फेसी उत्तरदायी हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस में तफतीश और विभागीय जांच की जारही है।

श्री पृथ्वीसिंह: इतनी बड़ी गेहूँ की मात्रा है और जौ की मात्रा है। उसको गबन करने में सिर्फ इन कर्मचारियों का ही हाथ था या और भी किसी अधिकारी का हाथ था?

श्री परसराम मदेरणा: पुलिस ने अभी हाल ही में ग्रामसेवक को गिरफ्तार किया है मदनलाल जैन को जो अभी तक फरार था। पुलिस की जांच जेर तफतीश है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि और कौन हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स किस की थी?

श्री परसराम मदेरणा: पंचायत समिति का जो गोदाम था उसमें ये रखे हुए थे। इसकी सुपरवाइजरी ड्यूटी तो बी० डी० ओ० की थी, लेकिन बी० डी० ओ० उस वक्त वहां पर नहीं थे, छुट्टी पर थे।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या यह सही है कि ट्रक में जो लदान कराने वाले लोग थे उन्होंने यह बयान दिया है कि हमने लाद दिया है और ड्राइवर ने यह बयान दिये हैं कि मै ले गया हूं और फलां जगह डाला है।

श्री परसराम मदेरणा: पुलिस की तफतीश की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री माधो सिंह!

श्री पृथ्वीसिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह धान गया कहां है और कहां बेचा गया है?

श्री परसराम मदेरणा: पुलिस जांच कर रही है।

प्रश्न संख्या २३६

श्री अध्यक्ष: श्री माधोसिंह!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लाभचन्द बैद!

रतनगढ़ में बिजली सप्लाई

२३७. **श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका रतनगढ़ में प्रशासक कब से कार्य कर रहा है?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका रतनगढ़ और विद्युत् विभाग में जमीन के किराये व बिजली के पैसों के प्रश्न पर झगड़ा चल रहा है?

(३) क्या यह सही है कि इस झगड़े के कारण शहर में अधिकांश स्थानों पर अंधेरा रहता है? यदि हां, तो सरकार इस

Page No.12

(श्री लाभचन्द बैद)
झगड़े के निपटाने के लिए क्या करना चाहती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) दिनांक २४-१-६७ ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । झगड़े का निपटारा हो गया है ।

श्री लाभचन्द बैद : कितने अर्से से झगड़ा चल रहा था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : झगड़ा काफी अर्से से चल रहा है ।

श्री रावतराम (छापर) : क्या यह सही है कि नगरपालिका और बिजली विभाग के बीच झगड़े का निपटारा होने के बाद बिजली की सप्लाई अच्छी तरह से हो रही है ? क्या नगरपालिका को अब बिजली अच्छी तरह से सप्लाई कर रहे हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : बिजली की सप्लाई झगड़ा समाप्त होने के बाद नगर एरिया में ठीक हो रही है ।

नगरपालिका ने सूचित किया है कि दिनांक २७-५-६७ से विद्युत् विभाग ने उन बत्तियों को बदलना शुरू कर दिया है और दिनांक २७-५-६७ के बाद जैसा कि विभाग के अधिकारियों ने बताया है १० बत्तियों को बदला जा चुका है ।

श्री लाभचन्द बैद : यह झगड़ा कितने अर्से से चल रहा है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : काफी अर्से से ।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : काफी अर्से से क्या तात्पर्य है ? उसका क्या माप-दण्ड है ?

श्री लाभचन्द बैद : यह झगड़ा ६ साल से चल रहा है और इसका खमियाजा पब्लिक को उठाना पड़ता है । तीन महीने तक स्ट्रीट लाइट्स बन्द रहीं और तीन महीने तक कितने लोगों को कुत्तों ने खाया है अन्धेरे के कारण । इसके कारण से पब्लिक को नुकसान उठाना पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हंसराज आर्य !

भाखरा क्षेत्र में अन्न की पैदावार

२३८. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पिछले तीन सालों में भाखरा क्षेत्र के किसानों को अन्न की उपज कम हुई या अधिक ?

(२) यदि कम हुई, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) व (२) भाखरा क्षेत्र के लिए उपज के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं इसलिए उपज के कम होने या बढ़ने के बारे में कहना कठिन है ।

श्री हंसराज आर्य : जब मेरा प्रश्न स्पष्ट है फिर आंकड़े अलग से क्यों नहीं आये ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय,

Page No.13

(श्री परसराम मदेरणा)
मैं निवेदन कर चुका हूँ कि भाखरा नहर द्वारा सिंचित इलाके की उपज के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। डिस्ट्रिक्टवाइज आंकड़े होते हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि जो भाखरा से इरिगेटेड एरिया है उसमें खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है या कितना बढ़ा है। यह कहना मुश्किल चीज है। ये अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) **:** ऐसी बड़ी स्कीम ......

श्री अध्यक्ष : श्री प्रश्नकर्ता।

श्री हंसराज आर्य : भाखरा में उत्पादन कम हुआ है क्या उसको छिपाने के लिए सारे आंकड़े शामिल किए गये हैं?

श्री परसराम मदेरणा : यह सही नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फिर अलग क्यों नहीं रखे गये?

श्री हंसराज आर्य : अलग से जब आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो कैसे कह सकते हैं कि सही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह एलीगेशन लगाया है कि डिक्रीज हुए हैं या इन्क्रीज हुए हैं इस फेक्ट को छिपाने के लिए अलग नहीं रखे हैं। यह बात नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट के अलग-अलग आंकड़े होते हैं। उसी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में गंग कैनाल है, राजस्थान कैनाल है और भाखरा कैनाल है। इनसे सिंचाई होती है तो पूरे जिले के मेरे पास आंकड़े हैं कि इस वर्ष में जो जमीन सिंचित हुई है या इरिगेशन के नीचे आई है उससे पैदावार कितनी बढ़ी है, लेकिन यह मैं नहीं कह सकता कि भाखरा एरिया में कितनी पैदावार बढ़ी है या वहां पर घटी है।

श्री फूलचन्द बाफना : मन्त्री महोदय........

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हंसराज आर्य : इस भाखरा पर जब २९ करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो क्या इसके अलग से आंकड़े तैयार नहीं किये जा सकते?

श्री परसराम मदेरणा : कितना रुपया खर्च हुआ है यह बात नहीं पूछी गई है। यह प्रश्न इरिगेशन से सम्बन्ध रखता है। आपने उपज के बारे में पूछा है कि पैदावार बढ़ी है या नहीं बढ़ी है तो जहां तक पैदावार के बढ़ने या घटने का प्रश्न है वह मेरे महकमे से सम्बन्ध रखता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) **:** इतना खर्चा हुआ....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री दौलतराम सारण : गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल और भाखरा कैनाल इन तीनों क्षेत्रों में सिंचित भूमि पर पैदावार बढ़ी है या घटी है?

श्री परसराम मदेरणा : इसका अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री कृष्णकुमार गोयल!

श्री दौलतराम सारण : मैंने जिले का प्रश्न पूछा है। अलग से प्रश्न पूछने का

Page No.14

(श्री दौलतराम सारण)
सवाल नहीं है। आपने भाखरा का बताया नहीं और कहा कि उसमें शामिल है।

श्री परसराम मदेरणा : सारे प्रश्न की चीज सप्लीमेंट्री में नहीं पूछी जा सकती है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है तो यह भाखरा क्षेत्र के लिए पूछा गया है जिसके लिए मैंने कहा है कि अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपने कहा कि जिले भर का बता दूं.......

श्री हंसराज आर्य : भाखरा का पूछा था तो आपने फरमाया कि जिले के हैं तो आप जिले के बता दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री दौलतराम सारण : यह गम्भीर मामला है।

कोटा नगर परिषद् द्वारा उद्योगों को चुंगी से छूट

२३६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने कोटा नगरपालिका क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को चुंगी से छूट दी है ?

(२) अगर हां, तो किन-किन उद्योगों को कब-कब कितने समय के लिए छूट दी है, व क्यों ?

(३) क्या सरकार ने इस छूट के कारण नगर परिषद् की होने वाली क्षति को आंका है ? अगर हां, तो किस २ उद्योग से कितना-कितना ?

(४) क्या सरकार ने नगर परिषद् को इस क्षति-पूर्ति के लिए कुछ सहायता दी है ? अगर हां, तो कब २ कितनी-कितनी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी हां।

(२) कतिपय उद्योगों को छूट दी है। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु चुंगी की छूट दी गई है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट संख्या ४ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार ने इन छः उद्योगों को चुंगी की छूट दी उसके पहले सम्बन्धित नगरपालिका, कोटा से उनके विचारों को नहीं मांगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसी कानूनी कोई जरूरत नहीं है म्युनिसिपल एक्ट १०७ (५) के अन्तर्गत।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि नगरपालिका, कोटा ने इस चुंगी की छूट के खिलाफ रिप्रेजेन्टेशन किया है कि चुंगी की छूट कर देने के कारण कोटा नगरपालिका को लगभग ५ लाख सालाना का नुकसान हो रहा है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कोटा नगर को इन इन्डस्ट्रीज के लगने से जितना फायदा हो रहा है वह आपके ध्यानान्तर्गत है। वहां पर जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है कोटा नगर की, चम्बल नदी बहती है, राणा प्रताप सागर आदि हैं, बड़ी लाइन है उसके हिसाब से इन्डस्ट्रीज वहां पर आती हैं। वे केवल नगरपालिका से आती हों ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगह भी बड़ी लाइन है वहां पर भी वे जा सकती हैं। बम्बई भी जा सकती हैं। इण्डस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेन्ट हमारा राजस्थान सरकार का यह है, जहां तक मैं जानता हूं और यह सारे राजस्थान भर के लिए है केवल कोटा के लिए ही नहीं है कि मशीनरी के ऊपर और इस प्रकार से रॉ-मेटीरियल आदि के ऊपर ऑक्ट्राय इत्यादि नहीं लगेगी ताकि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो एक तरफ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट का तकाजा है और एक तरफ दूसरी बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिन उद्योगों को सरकार ने चुंगी की छूट दी है उन्होंने उसके तीन या चार साल पहले से ही प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया था ? स्थिति यह नहीं है कि जिस रोज चुंगी में उनको छूट दी है, उन्होंने तभी से अपनी इन्डस्ट्री में उत्पादन आरम्भ किया है। इस चुंगी की छूट देने से तीन वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष पहले से इन उद्योगों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इससे आपका तात्पर्य क्या है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यानी आपने इन इण्डस्ट्रीज को लाभ पहुंचाने का दृष्टिकोण अपनाया है। आपके इस समाजवादी दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण को अपनाने का क्या कारण था ? ऐसा कौनसा कहर इन इन्डस्ट्रीज पर पड़ रहा था जिसके कारण सरकार को उदार होकर सोचना पड़ा और ऑक्ट्राय से इन्हें एकजेम्प्ट करना पड़ा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यदि कोई इन्डस्ट्रीज लग गई है और उनके चालू रहने में, उनकी प्रगति होने में ऐसी बात की आवश्यकता है तो वह बाद में भी की जाय तो उसमें हानि नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार के पास में, जिस समय इन इन्डस्ट्रीज ने रिप्रेजेन्टेशन किया, ऐसी कोई जानकारी थी कि इन छः इन्डस्ट्रीज में से एक भी इन्डस्ट्री नुकसान में चल रही है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : नुकसान में चलने की बात नहीं है। इन्डस्ट्रीज आगे बढ़ें, यह देखने की बात थी। यदि यह इन्डस्ट्रीज कोटा नगर को छोड़ कर चली जातीं तो आप कहते कि सरकार ने उदासीनता बरती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब तक चम्बल है तब तक यह नहीं जायेंगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्या सरकार जितना नुकसान म्युनिसिपैलिटी को आक्ट्राय एक्जेम्प्ट करके कर रही है, उसके कुछ पर्सेन्टेज की पूर्ति करने को तैयार है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं पहले कह चुका हूँ कि अन्यत्र कहीं ऑक्ट्राय के सामान्यीकरण का प्रश्न भी चल रहा है और एक कमेटी ग्रोन ऑक्ट्राय कन्सेशन्स इन्डस्ट्रीज़

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
डिपार्टमेंट की तरफ से भी नियुक्त हुई है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उसके सामने यह सब स्थिति अभी विचाराधीन है कि किस प्रकार से ऑक्ट्राय का सामान्यीकरण किया जाय और इन्डस्ट्रीज को किस तरह से छूट दी जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह माना जाय कि जो छूट दी गई है वह छूट इन फैक्ट्रीज के रिप्रजेन्टेशन पर दी गई है या सरकार ने अपनी तरफ से छूट दी है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो यह छूट दी जा रही है वह इन इन्डस्ट्रीज को ही मिलेगी या राजस्थान के अन्य भागों में और भी जो ऐसी इन्डस्ट्रीज हैं उनको भी छूट चुंगी कर में दी जाने की सरकार की नीति है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: सरकार की नीति है तभी तो यह कमेटी ग्रोन ऑक्ट्राय कन्सेशन्स की नियुक्ति की गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही नीति कार्यान्वित होगी।

श्री भैरोंसिंह: नीति क्या है ? क्या इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज को चुंगी कर में छूट देने की नीति है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: इन्डस्ट्रियल पॉलिसी का स्टेटमेंन्ट यही था कि सब मशीनरी को छूट दी जाय।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री हीरा !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कोटा में छः उद्योगों को चुंगी कर में छूट क्यों दी गई है, राजस्थान की बाकी इन्डस्ट्रीज को क्यों नहीं दी गई है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): जयपुर में दी हुई है।

श्री नारायणसिंह मसूदा: इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, कोटा की डी. सी. एम., नॉयलोन फैक्ट्री आदि बड़े बड़े करोड़पति-उद्योगपतियों के उद्योगों को चुंगी कर में एक्जेम्प्शन दिया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने कोटा नगर परिषद् की आज यह स्थिति कर रखी है कि लगभग पचास प्रतिशत आय स्रोत सरकार ने ले लिये हैं। जमीन को सेल करने के बारे में अधिकार ले लिये हैं। मण्डी कमेटी और कॉलोनाइजेशन कमेटी के अधिकार अपने पास ले रखे हैं। आज कोटा नगर परिषद् की स्थिति यहां तक है कि म्युनिसिपैलिटी अपने क्षेत्र के अन्दर नजूल लैण्ड तक नहीं बेच सकती है, डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैण्ड नहीं कर सकती है। आपने डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर का नारा दे रखा है लेकिन कोटा नगर परिषद् की स्थिति १९६१ से अब तक यह चल रही है कि नगर परिषद् के आय के स्रोत को कट करने के लिए सरकार तुली हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में सरकार द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाया जाय। इस मामले में कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाय और नगर परिषद् कोटा का गला न घोटा जाय। आप इस पर विचार करें कि म्युनिसिपैलिटी की आय के स्रोत कम नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
हों और वह बढ़ सकें। इस दृष्टिकोण से आप इस मामले पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरा !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अध्यक्ष महोदय, जो चुंगी में छूट दी गई है अमुक अमुक इन्डस्ट्रीज़ को, इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि क्या इसको सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझती ? एक दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब आपने छूट दी उस समय आपके मन में यह आशंका थी या नहीं कि नगर परिषद् को इससे अनुचित हानि होगी ? उस हानि की पूर्ति करने के लिए आपने कोई व्यवस्था करने का विचार किया या नहीं किया ? कृपा करके मंत्री महोदय इसका उत्तर यदि दे सकें तो दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा: यह जो दूसरी बात है कि उस नगरपालिका के प्रति क्या बर्ताव है इत्यादि—यह अलग से प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अध्यक्ष महोदय, अलग क्वेश्चन नहीं है। यह कन्सेशन का क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।

श्री नारायणसिंह मसूदा: इस विषय में यदि....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कन्सेशन का क्वेश्चन है, यह सरकार की नीति से सम्बन्ध रखता है। अनुचित रूप से नगर परिषद् कोटा को हानि पहुँचाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यह स्वस्थ तरीका नहीं है। आपकी नीति निर्धारित होनी चाहिए। उस नीति के अनुसरण में या नीति के अन्तर्गत जो भी व्यवस्था आप करें तो वह बड़ी शोभनीय और अच्छी बात है लेकिन उसके विपरीत हेपहेजर्ड वे में और हिदर-दिदर किसी को कन्सेशन दिया किसी को नहीं दिया, नॉयलोन फेक्ट्री को कन्सेशन दे दिया गया और किसी को नहीं दिया गया—तो यह मेरे ख्याल से नीति पर आधारित चीज नहीं है। आपकी व्यवस्था बड़ी असंतोषजनक है और यह नगर परिषद कोटा के लिए अनुचित रूप से हानिकर है। सरकार को चाहिए कि वह कोई पॉलिसी निर्धारित करे और उसके अन्तर्गत वह जो भी व्यवस्था करे वह ठीक होगी वरना यह व्यवस्था तो बिल्कुल खराब है।

प्रश्न संख्या २४०

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २४१

श्री हरलाल सिंह !

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि दूसरी इन्डस्ट्रीज़, जो भी शहरों में हैं, के लिए पहिले से ऐसी व्यवस्था है कन्सेशन की ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री हरलाल सिंह !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनरल पॉलिसी का प्रश्न है, यह अध्यक्ष महोदय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा भी पॉलिसी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल सिंह !

सीकर जिले की ग्रामीण जल-वितरण योजनायें

२४१. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रींगस, अजीतगढ़ के अलावा पंचायत समिति श्री माधोपुर, जिला सीकर में किन २ ग्रामों की जल वितरण योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं और उनकी स्वीकृति कब तक हो जावेगी व कार्य कब तक चालू होगा ?

(२) क्या यह सही है कि मऊ ग्राम की जल-योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू होगा ?

(३) क्या यह सही है कि किन्हीं सज्जन द्वारा मऊ ग्राम की जल-योजना के लिये ग्राम सहायता के हिस्से की रकम का चैक सम्बन्धित विभाग को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या चैक का भुगतान हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

उपमंत्री, जनस्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह) : (१) रींगस, अजीतगढ़ के अलावा पंचायत समिति श्री माधोपुर, जिला सीकर में (१) मऊ (२) महरोली ग्राम के लिए ग्रामीण जल-योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की जा चुकी है। बजट की स्वीकृति अभी नहीं हुई है। इन ग्रामों की योजनाओं की तकनीकी जांच मुख्य अभियन्ता के द्वारा होने के बाद संशोधित रूप में फिर से एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सीकर द्वारा तैयार जा रही है । इन योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हो जाने के बाद ही आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर कार्य हाथ में लिया जायगा ।

(२) मऊ ग्राम की प्रशासनिक स्वीकृति राजस्थान सरकार द्वारा की जा चुकी है, किन्तु तकनीकी जांच के अनुसार योजना को फिर से संशोधित रूप में तैयार किया जा रहा है । संशोधित रूप में योजना तैयार होने के बाद इसकी तकनीकी स्वीकृति की जायगी और तत्पश्चात धनराशि की उपलब्धिता पर तथा जन सहयोग की धनराशि प्राप्त होने पर कार्य हाथ में लिया जायगा ।

(३) जी हां, चैक श्री ख्यालीराम पार्टनर शंकर ऑइल इण्डस्ट्रीज, श्री माधोपुर द्वारा एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर वाटर वर्क्स सीकर के नाम दिया गया था । किन्तु चैक का भुगतान नहीं हुआ । क्योंकि बैंक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के नाम रकम जमा नहीं होने से चैक लौटा दिया गया । इस सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत मऊ को धनराशि जमा कराने के लिए सूचित कर दिया गया था । धनराशि अभी जमा नहीं हुई है ।

प्रश्न संख्या २४२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री मुवालाल चौधरी

श्री मुन्नालाल चौधरी : प्रश्न संख्या २४४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, २४३ रह गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

Page No.19

छापर, चाडवास और बीदासर की वाटर सप्लाई स्कीम

२४३. श्री रावतराम (छापर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चूरू जिले के कस्बा छापर, चाडवास व बीदासर के लिए वाटर सप्लाई योजना सरकार ने स्वीकृत की है ? यदि हां, तो उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है तथा इन कस्बों को पानी कहां से दिया जायगा ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कस्बों के नागरिकों की ओर से सम्बन्धित योजना के लिए जन सहयोग देने की बात है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि ली गई है या ली जायगी ?

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित योजना के लिए एग्रीमेंट तैयार हो गया है ? यदि हां, तो एग्रीमेंट की एक प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(४) उक्त योजना पर कार्य कब चालू हुआ और अब क्या प्रगति है तथा सम्बन्धित कस्बों को पीने का पानी कब तक मिलना शुरु हो जायगा ?

(५) क्या यह सही है कि इन कस्बों में गर्मियों के दिनों में पीने के पानी की बड़ी समस्या है ? यदि हां, तो सरकार चालू साल में इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

उपमंत्री, जन-स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह) : (१) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। कस्बों को पानी देने के लिए जल स्रोत की खोज जारी है।

(२) जी हां, बीदासर के लिए २,५०,००० ओसवाल सभा बीदासर ने व छापर के लिए २,००,००० महेश्वरी जलप्रदाय समिति, छापर ने एवं चाडवास पंचायत ने भी प्रस्ताव भेजे हैं।

(३) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) योजना पर अभी कार्य चालू नहीं हुआ है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) जी हां योजना बनाए जाने के लिए उपयुक्त जल-स्रोत की तलाश की जा रही है।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न संख्या ३ में यह बताया कि 'जी नहीं'। जब उन कस्बों के लोग, बीदासर और मऊ के लोग रकम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को एग्रीमेंट करने में क्या दिक्कत है ?

राव श्री धीरसिंह : जल-स्रोत को तलाश करने के बाद यदि काम चलेगा तब करेंगे। अभी तो जल-स्रोत की तलाश कर रहे हैं। आठ हजार गेलन प्रति घंटे की केपेसिटी का ट्यूब वैल नहीं मिलता। जब तक ऐसे तीन ट्यूब वैल्स नहीं मिलते तब तक योजना में जितना पानी दिया जाना चाहिए उतना नहीं दे सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि परजान्सर में इस प्रकार का जल-स्रोत उपलब्ध हो गया था ?

राव श्री धीरसिंह : कौन सा ?

श्री दौलतराम सारण : परजान्सर।

राव श्री धीरसिंह : नहीं।

Page No.20

श्री दौलतराम सारण : वहां पर बोरिंग करवाया गया था और वहां जल-स्रोत उपलब्ध हो गया था।

राव श्री धीरसिंह : वह जल-स्रोत तीन हजार गैलन का था जब कि हमको आठ हजार गैलन का चाहिए।

श्री रावतराम : क्या जल-व्यवस्था को ठीक करने के लिये कोई सरकार प्रबन्ध कर रही है?

राव श्री धीरसिंह : बजरंगसर में एक स्रोत मिला है और अभी दो स्रोत ८, ८ हजार के ढूंढ रहे हैं।

श्री रावत राम : क्या जो रकम दे रहे हैं वह जमा नहीं करेंगे?

राव श्री धीरसिंह : पहले ही पैसा ले कर क्या करेंगे?

श्री रावत राम : अब सरकार पानी के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है?

राव श्री धीरसिंह : बजरंगसर में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तलाश किया जा रहा है और इसकी मीटिंग १५ तारीख को होने वाली है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रावत राम : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। बीदासर कस्बे में पानी की बड़ी दिक्कत है। जहां सैकड़ों औरतें पानी के लिये कतार में खड़ी रहती हैं और बहुतसे लोग पानी बाहर से, बहुत दूर से लाकर पीते हैं। जब तक यहां पर कोई दूसरा प्रबन्ध सरकार के द्वारा नहीं हो तब तक के लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी?

राव श्री धीरसिंह : यह अलग से प्रश्न है। अगर आप अलग से पूछेंगे तो इसका जवाब दे दिया जायगा।

श्री रावत राम : कोई व्यवस्था आपके दिमाग में है क्या?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सूवालाल!

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : क्या जवाब देंगे कोई जवाब दिमाग में है ही नहीं तब।

पंचायत समिति दूदू के बोराज, बिचूण आदि ढाणियों में सहकारी समिति

२४४. श्री सूवालाल चौधरी (दूदू) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पंचायत समिति दूदू के अन्तर्गत बोराज, बिचूण, सेवा ढाणी बोराज, साखून में कोई सहकारी समितियां हैं? यदि हां, तो इनका गठन कब हुआ और आज तक इनको कितना लोन दिया गया, और कितना बकाया है? इनका कब-कब ऑडिट हुआ व विभाग की ओर से किसने निरीक्षण किया? क्या क्या दोष पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

सहकारी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : पंचायत समिति, दूदू के अन्तर्गत बोराज, बिचूण, सेवा ढाणी, बोराज, साखून में निम्नलिखित १० सहकारी समितियां हैं जिनका गठन (रजिस्ट्रेशन) इनके सामने

(श्री परसराम मदेरणा)
अंकित तिथियों में किया गया है।

नाम सहकारी समिति	दिनांक गठन (रजिस्ट्रेशन)
बोराज ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	२८-४-६०
ढाणी बोराज ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	६-११-६१
बिचून ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	५-३-६०
साखून ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	३०-३-६३
सेवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	२-३-६२
बोराज चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	१८-४-५७
बिचूण जनता सहकारी भण्डार	२२-११-५१
साखून कोआॅपरेटिव विलेज बैंक लि०	४-१२-४७
बिचूण चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	१६-३-६४
साखून चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	१७-२-६१

इन समितियों को दिये गए ऋण व बकाया की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इन समितियों का ऑडिट किसने और कब किया व क्या दोष पाये गये तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

इन समितियों का निरीक्षण किसने व कब किया और क्या क्या आक्षेप पाये गये इनके बारे में क्या क्या कार्यवाही की गई इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

(सूची 'ख' व 'ग' विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सुवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बोराज और सेवा ग्राम सेवा समिति हैं उनका ऑडिट नहीं हुआ है। उनके ऑडिट कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : बोराज का ५९-६०, ६०-६१, ६१-६२, ६२-६३, ६३-६४ में हुआ है।

सेवा ग्राम सेवा समिति का लेटेस्ट ६२-६३ का हुआ है, ६३-६४ का हुआ है। आप देख लें।

श्री सुवालाल चौधरी : चर्म उद्योग ग्राम सेवा सहकारी समिति, बोराज और सेवा के लिये कहता हूँ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने ईयर-वाइज स्टेटमेंट दे रखा है। वह बोराज ग्राम सेवा समिति का दे रखा है। मैंने जो सूचना दी है उसमें विस्तृत विवरण दे दिया है कि अलग अलग सोसाइटीज़ का ऑडिट कब-कब हुआ। बकाया के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूं कि २ जयपुर के हैं। ६ में से ४ का लोन ओवर ड्यू नहीं हुआ है और एक का लोन अल्पकालीन था उसको अकाल की वजह से मध्यकालीन कर दिया।

(श्री परसराम मदेरणा)
एक का ऋण बाकी है उसकी कार्यवाही की जारही है।

श्री जसराज (भिनाय): प्रति वर्ष सहकारी समिति का ऑडिट हो जाना चाहिये यह नियम है। अब तक उनका ऑडिट नहीं हुआ है उसके लिये क्या यह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि हर साल ऑडिट हो।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि प्रतिवर्ष हर सोसाइटी का ऑडिट होना चाहिये। इसके लिये इन्सपेक्टरों द्वारा यह होना चाहिये और नहीं हुआ है इसके लिये उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिये रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटी को लिख दिया गया है कि उन्होंने समय पर ऑडिट नहीं किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मदनसिंह दांता !

श्री जसराज: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न २४५ बाकी रह गया।

श्री अध्यक्ष: श्री जसराज !

अजमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा गृह निर्माण हेतु धन राशि वितरण

२४५. श्रीजसराज (भिनाय): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर जिले में समाज-कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में सन १९५६-५७ से १९६६-६७ तक गृह-निर्माण हेतु कितनी धनराशि प्रत्येक वर्ष दी गई ?

(२) उपरोक्त धनराशि अनुदान प्राप्त कर्ताओं को सीधी दी गई अथवा किन्हीं संस्थाओं के मार्फत दी गई ?

(३) क्या उपरोक्त धनराशि उसी कार्य में उपयोग की गई है जिसके लिये दी गई तथा क्या उपयोग-प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है ?

(४) यदि नहीं, तो उपरोक्त धनराशि जो अभी तक उपयोग में नहीं ली गई है किसके पास है और विभाग द्वारा इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जारही है ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा: (१) सूची अ और ब सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, सहायता की रकम प्राप्त-कर्ताओं को सीधी दी गई।

(३) जी हां, अधिकांश उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं। कुछ के बाकी हैं।

(४) विभाग में सीधी धनराशि प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त कर्ता उनके चुने हुये प्रतिनिधियों की समिति बनाते हैं। जिनके द्वारा प्राप्त धनराशि बैंक में जमा कराई गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री जसराज : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि कितनी धनराशि के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं और कितनों के नहीं हुए हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: मैंने निवेदन किया है कि अधिकांश उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं।

Page No.23

श्री जसराज : कितने अमाउन्ट के प्राप्त हो गये हैं यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह मैं स्पष्ट तो नहीं बतला सकता हूँ... ....

श्री जसराज : कितने अमाउन्ट ... ...

श्री नारायणसिंह मसूदा : आपका भय मैं समझ गया। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जिनको धनराशि दी जाती है वे लोग उसके पश्चात् चुने हुए प्रतिनिधियों की समिति बना लेते हैं और वह रकम बैंक में जमा करा दी जाती है। आगे के लिये भी ५० हजार की राशि रखी गई है।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ये अलग २ पंचायतों से आये हैं। इसकी सूचना अभी ....बाद में .... (सुनाई नहीं दिया)

कई माननीय सदस्य : कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जरा जोर से बोलें।

श्री अध्यक्ष : कृपया माइक पर।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अनुसूचित जनजाति और उनके............

एक माननीय सदस्य : कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : इसमें अस्पष्ट है उनको स्पष्ट कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है।

श्री जसराज : मंत्री महोदय ने जो भी कहा वह मैं तो सुन नहीं सका फिर भी मैं उनसे प्रश्न पूछ लेता हूँ। क्या यह सच है कि अजमेर शहर में हरिजनों के कुछ मकान बनाने हेतु वहां भी रावण की बगीची के लिये रकम दी गई है वह कितनी दी गई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : रावण की बगीची के लिये हरिजनों को (अश्रव्य)

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय सुना नहीं जाता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मूलराम चौधरी है उनके द्वारा बैंक में जमा ...

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ४-५ साल हो गये हैं उनको जमीन दे दी गई है। आज चार पांच साल बाद भी उनको पैसे नहीं मिले हैं। इसमें पुरुषोत्तमदासजी कुदाल इन्वॉल्वड हैं और इस कारण उनको पैसा उपलब्ध नहीं हुआ है। उन्होंने हरिजनों के नाम पर पैसे का दुरुपयोग किया है और ब्याज के पैसे उठाये हैं। हरिजनों के नाम पर पैसा लिया जाता है और अपने काम में लिया जा रहा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : दुरुपयोग कहां हो पाया है यह तो मैं नहीं समझ पाया पर अजमेर मे १०० कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया गया है जिनको जमीन का एलॉटमेंट नहीं हुआ है, पट्टे आदि जारी नहीं किये गये हैं ..

श्री जसराज : जमीन एलॉट हो गई है, यू. आई. टी. के द्वारा सब कुछ एप्रूव हो चुका है. पर पुरुषोत्तमदासजी कुदाल पैसों पर बैठे हुए हैं और इस पैसे का सदुपयोग

(श्री जसराज)
नहीं हो रहा है, बल्कि पैसे का दुरुपयोग हुआ है, सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक में पैसा जमा है। ब्याज का पैसा वहां से उठाया गया और उसका दुरुपयोग हुआ है।

श्री नारायणसिंह मसूदा: इसकी मुझे विशिष्ट जानकारी करवानी पड़ेगी।

श्री जसराज: क्या इसकी जांच के आदेश देंगे?

श्री नारायणसिंह मसूदा: जरूर।

एक माननीय सदस्य: सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट से प्रति परिवार कितनी हाउस सब्सिडी मिलती है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बाजार, जयपुर): उनके बिना कहे ही मैं बताये देता हूं ७५०)।

श्री नारायणसिंह मसूदा: पहले ७५० मिलती थी अब १००० मिलती है।

श्री जसराज: क्या यह सही है कि ७५० से बढ़ा कर १०००) कर दी गई है?

श्री नारायणसिंह मसूदा: जी हां।

श्री जसराज: मन्त्री महोदय, स्वयं सोशियल वेल फेयर बोर्ड के अध्यक्ष हैं आपको यह भी पता है कि अभी उसका गठन पूरा नहीं किया गया है?

श्री नरायणसिंह मसूदा: उसका गठन किया जाना है।

श्री जसराज: कब तक हो जायगा?

श्री नारायणसिंह मसूदा: मैं आपकी भी सलाह ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

नागौर-मेड़ता डामर सड़क बनाने की योजना

२४६. **श्री मदन सिंह दांता** (दाता रामगढ़) श्री रामसिंह कुडी (जायल) द्वारा पूछा गया: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नागौर से मेड़ता की सड़क को डामर की बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो उस पर अमल कब तक किया जायगा?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना को सिर्फ इसलिये अधर में लटकाया गया है कि इस रूट को वाया कुचेरा निकाला जाय जबकि खजवाना रूण आदि ग्राम सीधे रूट में आते हैं?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (१) नागौर से मेड़ता रोड को डामर किये जाने की मंजूरी दे दी गई है। धन की कमी के सबब से निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(२) यह सड़क कुचेरा हो कर जाने को है।

श्री रामसिंह कुडी: सड़क पहले से बनी हुई है फिर इसे क्यों जोड़ा गया है?

श्री अमीनुद्दीन: दोनों सड़कें पेरेलल हैं, एक साथ चलती हैं, थोड़े फासले पर। एक ही माइलेज है और भी गुंजायश बढ़ जाय इसलिये जोड़ी गई है।

श्री रामसिंह कुडी: उधर बड़े-बड़े गांव ज्यादा हैं, फिर यह कुचेरा हो कर क्यों बनाई जा रही है।

Page No.25

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इधर भी बड़-बड़े गांव हैं इधर से यदि बदला जायगा तो उस तरफ वालों को भी यही शिकायत होगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत !

नसीराबाद में जल वितरण व्यवस्था

२४७. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नसीराबाद में मिलिट्री छावनी होने के कारण जल संकट एवं नगर के उत्थान की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों पर है ?

(२) अगर राज्य सरकार पर ही है तो मिलिट्री छावनी को व नगर नागरिकों को किस अनुपात में पानी-वितरण किया जाता है ?

उपमंत्री जन-स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह) : (१) बनास नदी से नसीराबाद में पानी दिये जाने की जो योजना है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । इस समय जो वहां चालू जल-संधारण केन्टोनमेंट एवं नसीराबाद कस्बे के हैं उनको केन्टोनमेंट द्वारा कन्ट्रोल किया जाता है जो केन्द्र सरकार के अधीनस्थ हैं । नसीराबाद केन्टोनमेन्ट है वहां केन्टोनमेंट बोर्ड है जिसका कि सीधा सम्बन्ध मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स, भारत सरकार से है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पानी की स्कीम अभी बतला रहे हैं अगर राज्य सरकार के नीचे आती है तो यह पानी कब तक मिलेगा ?

राव श्री धीरसिंह : यह पानी बेराज पर पाइप लाइन बन रही है, वह कम्पलीट होते ही, दिया जायगा । इसे कम्पलीट करने के लिये २४०० फुट पाइप चाहिये । १४०० फुट पाइप पहुंच गये हैं, १००० फुट पाइप और आने रहे हैं । इनके आने पर पूरा होते ही पानी दिया जायगा ।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा प्रश्न यह था कि नसीराबाद कस्बे के लिये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं क्या ? अगर दोनों जिम्मेदार हैं तो पिछले २० वर्षों में राज्य सरकार ने नसीराबाद कस्बे का क्या उत्थान किया है ?

राव श्री धीरसिंह : राजस्थान सरकार केवल बनास नदी से वाटर लाइन लारही है उसको बनाने की जिम्मेदार है । तमाम विकास कार्य केन्टोनमेंट बोर्ड के अन्डर में हैं, इसके लिये राजस्थान सरकार जिम्मेदार नहीं है ।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा दूसरा प्रश्न है, नसीराबाद के उत्थान के बारे में, मन्त्री महोदय, उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

राव श्री धीरसिंह : उत्थान के बारे में केन्टोनमेंट बोर्ड जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है ।

श्री विजयसिंह रावत : अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे कार नसीराबाद कस्बे से राज्य सरकार द्वारा

(श्री विजयसिंह रावत)

उगाये जाते हैं, वे कर केन्टोनमेंट बोर्ड को नहीं जाते हैं, तो कैसे हो सकता है कि राज्य सरकार उस कस्बे के उत्थान के लिये जिम्मेदार नहीं है ?

राव श्री धीरसिंह : जहां तक करों का सम्बन्ध है, इसका दूसरे विभागों से सम्बन्ध है, उनसे पूछिये, करों के मामले में दूसरे विभाग जवाब देंगे कि कैसे कर वसूल करते हैं, कितने कर वसूल करते हैं। जहां तक वाटर सप्लाई का डेवलपमेंट का सवाल है वह बोर्ड के नीचे है, बोर्ड भारत सरकार के नीचे है। उसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री विजयसिंह रावत : मन्त्री महोदय टालमटोल कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से बतायें कि राज्य सरकार नसीराबाद कस्बे के उत्थान के लिये जिम्मेदार है या नहीं ? अगर जिम्मेदार है, तो उत्थान करने में राज्य सरकार का कहां तक हिस्सा रहता है ? ताकि हम आपसे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। नसीराबाद केन्टोनमेंट बोर्ड अगर इसके लिये जिम्मेदार है तो केन्द्रीय सरकार से इसके उत्थान के लिये कार्यवाही करें।

समाज कल्याण मंत्री : (श्री नारायण सिंह मसूदा) : जल-वितरण के कार्य की जिम्मेदारी केन्टोनमेंट बोर्ड के पास है। इस विषय में परिवर्तन के सुझाव देंगे तो अलग से बात भी जा सकती है, मगर इस समय जल वितरण का कार्य केन्टोनमेंट बोर्ड के पास है। बनास से जल-सप्लाई योजना के अन्तर्गत पानी आ रहा है, वह पानी कब तक दिया जा सकेगा, इस सम्बन्ध में मैं पहले स्टेटमेंट दे चुका हूं, उसके अनुसार ही नसीराबाद में सारा कार्य होगा।

श्री विजयसिंह रावत : आपने प्रश्न संख्या २ का उत्तर ठीक से नहीं दिया है कि किस अनुपात से पानी का वितरण होता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मौजूदा जो जल का वितरण हो रहा है वह तो बोर्ड के अन्डर में है। बनास से पानी आयेगा, उसके बारे में हम बता सकेंगे।

श्री विजयसिंह रावत : यह आपको मालूम नहीं है कि वहां सिविलियन्स पानी के बिना मर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री विजयसिंह रावत : नसीराबाद में दूसरा ब्रिगेड आने वाला है मिलिट्री का क्या आपको मालूम है कि अभी जितना पानी वहां देते है वह कॉन्ट्रेक्टर्स को मकान बनाने के लिये दिया जाता है, सिविलियन्स प्यासे मर रहे हैं ?

राव श्री धीरसिंह : राज्य सरकार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है.... ... .

श्री विजयसिंह रावत: कैसे जिम्मेदारी नहीं है सिविलियन्स प्यासे मर रहे हैं। राज्य सरकार सब प्रकार के टैक्सेज वहां के लोगों से वसूल करती है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

Page No.27

श्री जसराज : क्या यह नहीं है कि उस समय वित्त मंत्री जी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि २६ जनवरी तक नसीराबाद में पानी आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री जसराज: उसकी व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न पूछ लीजियें।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : जो सिविलियन्स की आबादी नसीराबाद में है उनके लिये पानी की कमी है तो राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और केन्टोनमेंट बोर्ड से, हमारे सिविलियन भाइयों को पानी देने के लिये बात-चीत करे।

राव श्री धीरसिंह : राजस्थान सरकार का कर्तव्य है इसीलिये तो बनास से पानी ला रहे हैं।

(१२ मध्याह्न)

महरावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मेरे खयाल से मंत्री महोदय प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न को ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। यह पानी के बटवारे का प्रश्न है। पानी के बंटवारे का प्रश्न वहां के लोकल बोर्ड से सम्बन्धित नहीं है। केन्टोनमेंट और सिविल पॉपुलेशन के बीच पानी का क्या डिवीजन हो, क्या रेश्यो हो, यह बोर्ड कैसे डिसाइड कर सकता है। सरकार को चाहिए कि वह इस बारे में फैसला करे और यदि सरकार को जानकारी नहीं है, तो जानकारी प्राप्त करके उचित कार्यवाही करे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं पहिले ही निवेदन कर चुका हूँ कि इस विषय में अगर कोई खामियां हैं, तो जानकारी की जा सकती है।

महरावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो ब्राड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न है। अगर आप वहां के लोगों पर टैक्स लगाते हैं, टैक्स की प्रोसीड्स वसूल करते हैं तो सरकार का आटोमेटिकली उत्तरदायित्व है कि वह विकास के काम भी करे हर तरह का प्रबन्ध करे। जब आप फायदा उठाते हैं तो लोगों को कोरेसपोंडिंग गेन भी देना चाहिए। It is a matter of taxation. टैक्सेशन का सिद्धांत गिव एण्ड टेक पर बेस्ड है।

राव श्री धीरसिंह : बनास नदी से जब पानी आएगा तो मिल जायगा।

श्री नारायणसिंह मसूदा: केन्टोनमेन्ट के अन्दर समय से विवाद चला आ रहा है। उसकी अवहेलना एक दम की जाय तो ऐसा नहीं हो सकता और यह मामला केन्द्र से भी सम्बन्ध रखता है, उसका भी उतना ही महत्व है। मिलिट्री स्टेशन का सवाल है। उनको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब बातें आ जाती हैं।

श्री जसराज: मंत्री महोदय केवल प्रश्न के उत्तर को टाल रहे हैं। सिविलियन्स को पानी की सुविधा हो और सुविधा....

श्री अध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क।

लाडनूं जसवन्तगढ़ और सुजानगढ़ की वाटर सप्लाई स्कीम

२४८. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा

Page No.28

(श्री हरजीराम बुरड़क)

करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वाटर सप्लाई स्कीम लाडनूं, जसवन्तगढ़, सुजानगढ़ के लिए पानी लाडनू से जाता है फिर भी बहुत से कुंए अभी तक चालू नहीं किए हैं ? यदि हां, तो क्या इन कुओं को चालू करके पानी खेती के लिए दिया जा सकता है ?

(२) यदि हां, तो कितना पानी किन शर्तों पर दिया जा सकेगा ?

उपमंत्री जन-स्वास्थ्य (राव श्री धीर सिंह, (१) जी हां। लाडनूं से जाता है। कुल ६ नल कूप खोदे गए है। इनमें ३ नल कूपों से पानी वितरण चालू है। ३ नल कूपों के पम्प नहीं लगे हुए हैं। आर्डर्स दे दिए गए हैं। सिर्फ जल-प्रदाय योजना के लिए ही बनवाए गए हैं। इन कुओं से खेती के लिए पानी नहीं दिया जा सकता।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या यह सही है कि जसवन्तगढ़ की आबादी को ४ साल से खेती के लिए पानी दिया जा रहा है ?

राव श्री धीरसिंह: यह गलत है।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल): जिन कुओं में १० हजार से ५० हजार गैलन तक की पानी की केपेसिटी है और २० या ३० फुट पर मिल रहा है, वह सारा जल-प्रदाय के लिए और खेती बाड़ी के लिए काम में नहीं लें ?

राव श्री धीरसिंह: खेती के लिए तो देने का तो सवाल नहीं आता। हमको ६ कुओं की जरूरत है।

श्री आईदानसिंह: राज्य में कई ऐसे कुऐ हैं जिनसे १० से ५० हजार गलन पर ओवर पानी मिलता है। मेरे खयाल से मंत्री महोदय को जानकारी नहीं होगी।

श्री रामसिंह: मंत्री महोदय ने जो कहा कि खेती के काम के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है, यह गलत है। यह दिया जा रहा है। यह सदन की मान हानि है।

राव श्री धीरसिंह: आपके पास में कोई जानकारी है तो बता दें मेरी जानकारी में तो नहीं है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा में रोडवेज स्टेशन हेतु खरीदी गई जमीन

२१७. **श्री बी. एन. जोशी** (बांदी कुई): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दौसा में रोडवेज का स्टेशन बनाने के लिये जमीन क्या राज्य परिवहन निगम ने किसी प्राइवेट व्यक्ति से खरीदी है ? यदि हां, तो कितनी भूमि खरीदी है ?

(२) क्या खरीदी हुई भूमि पर राज्य परिवहन निगम ने आधिपत्य कर लिया है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त खरीदी हुई भूमि में करीब दस पन्द्रह दुकानें भी बनी हुई है ?

(४) क्या राज्य परिवहन निगम उक्त खरीदी हुई भूमि में कोई अहाता निर्माण

(श्री बी० एन० जोशी)
करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि स्थानीय अधिकारी उक्त भूमि के स्वामी को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से खरीदी हुई भूमि में से १० फीट छोड़ कर उस ग्राहते की तामीर करवा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, ३१० वर्ग गज जमीन श्री **मौरीलाल पतड़ा** (ब्राह्मन) निवासी दौसा से खरीद की है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं।

पीपलखूंट क्षेत्र में किसानों को लकड़ी के पास

२२०. **श्री विट्ठल भाई** (पीपलखूंट): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में पीपलखूंट क्षेत्र में वन विभाग की ओर से वहां के किसानों को किसी प्रकार के कार्य के लिये लकड़ी के पास नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

१. जी नहीं।

माजरी कलां-रेवाणा सड़क का निर्माण

२२१. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील बहरोड़ में माजरी कलां से रेवाणा तक की सड़क बनाई जा रही थी ? यदि हां, तो क्या इसका कार्य अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, धन की कमी तथा भूमि अवाप्ति के सबब से काम बन्द है ?

अजमेर में राशन का चावल

२२२. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार अजमेर के नागरिकों को राशन में चावल देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

जी नहीं।

कांमा पहाड़ी-सड़क पर पुलिया का निर्माण

२२३. **श्री मजलिस खां** (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि कांमा से १।। मील पहाड़ी रोड पर अग्रावली (चरण पहाड़ी) मोड़ पर जो सार्वजनिक रास्ता सड़क को क्रॉस करता है वहां पर एक पुख्ता दीवार सड़क पर खड़ी करदी गई है जिससे वह रास्ता रोक दिया गया है, और सड़क की मरम्मत के लिए एक साइड से मिट्टी इतनी उठाई गई है कि पैदल व्यक्ति भी नहीं उतर सकता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रास्ते पर एक पुलिया का निर्माण कराके

Page No.30

(श्री मजलिस खां)

जनता की असुविधा को दूर करने का विचार रखती है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चावन्ड सराडा-सेमारी रेलवे स्टेशन-कल्याणपुर सड़क को पक्का बनाना

२२५. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में चावण्ड गांव से सराड़ा-सेमारी रेलवे स्टेशन कुण्डा और कल्याणपुर तक जाने वाली सड़क पक्की बनाने की योजना है?

(२) क्या यह सड़क सहायता कार्यों के अन्तर्गत बनाई जा रही है ?

(३) क्या सरकार ने सहायता कार्यों की राशि से इसे पक्की सड़क बनाने का निर्णय लिया है ?

उत्तर

(१) पलोदरा से सराड़ा तक पक्की सड़क बनाने की योजना है बाकी कार्य योजना में शामिल नहीं है ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

मन्डी समितियों के कार्यों के स्थगन सम्बन्धी आदेश

२२६. श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी, सन् ६७ में कृषि-उपज विपणी अधिनियम के अन्तर्गत मण्डी समिति के कार्यों को स्थगित करने का आदेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि यह आदेश वापिस ले लिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं। स्थगन आदेश २० जनवरी, १९६७ को दिये गये थे: क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कृषि उपज विपणी नियम, १९६३ के कुछ नियमों को अवैधानिक बताया तथा उनके प्रभाव की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक समिति नियुक्त की तथा उस समय तक के लिये जब तक कि समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार फैसला नहीं ले ले विपणी समितियों का कार्य स्थगित रखा गया । स्थगित करने के आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां, दिनांक २८ मार्च, १९६७ को यह स्थगन आदेश वापिस ले लिया गया, क्योंकि उस समिति की सिफारिशों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई खामियों को दूर कर दिया गया था ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

रायपुर तहसील में अनाज व शक्कर की वितरण व्यवस्था

•२२८. श्री शंकरलाल (जैतारण)— क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के गावों के लिए अनाज व शक्कर वितरण की दुकानें अधिकतर व्यक्तिगत दुकानदारों को दी गई हैं और सहकारी समितियों को नहीं ?

(२) क्या यह भी सही है कि कई गांवों की दुकानें ऐसे व्यापारियों को दी गई हैं जो उन गांवों के रहने वाले नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसमें कौन २ से गांवों की दुकानें किन २ व्यापारियों को दी गई हैं, दर्शाया गया हो ?

(३) क्या यह सही है कि इन व्यापारियों द्वारा गांवों में फर्जी वितरण बताकर अनाज और चीनी काले बाजार में बेची जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठायेगी ?

उत्तर

(१)जी नहीं । सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(२)सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(३)जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

गोगुन्दा कोटड़ा में लकड़ी का कोयला बनाने का ठेका

२२९. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गोगुन्दा-कोटड़ा में कितने कूप लकड़ी के कोयले बनाने हेतु दिए हुए हैं ? तथा किन २ ठेकेदारों को कौन २ सा जंगल दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि कोटड़ा रेन्ज के अन्दर जितना जंगल कोयला बनाने हेतु दिया गया है उससे अधिक क्षेत्र का जंगली काटा गया है ? यदि हां, तो वन विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) कोटड़ा रेन्ज के अन्दर कोयले बनाने के कितने कूप हैं ? कृपया उनके नम्बर बतायें तथा ठेकेदारों के नामों की सूची भी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) गोगुन्दा रेंज में १९६६-६७ में कोई कूप लकड़ी के कोयले बनाने हेतु नहीं दिया गया लेकिन कोटड़ा रेंज में १२ कूप लकड़ी के कोयले बनाने के लिए दिए गये हैं। जिन २ ठेकेदारों को जो जंगल दिया गया है उसकी सूची संलग्न है ।

(२) जी नहीं, कोई सामूहिक रूप से अधिक क्षेत्र नहीं काटा गया वरन कुछ ठेकेदारों द्वारा निर्धारित कूप क्षेत्र के बाहर म मूली अवैधानिक कटाईयां की गई हैं जिनके विरुद्ध खिलाफ वर्जी के मामले बनाये

Page No.32

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(३) कोटड़ा रेंज के अन्दर कोयला बनाने के लिए १२ कूप हैं। इन कूपों के नम्बर व ठेकेदारों के नाम संलग्न सूची में बता दिए गए हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

सीसवाली से ठींपरी (तहसील मांगरोल) सड़क का निर्माण

२३०. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सीसवाली से ठींपरी (मांगरोल तहसील) जाने वाले कच्चे मार्ग पर सड़क बनाने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी थी?

(२) यदि हां, तो कितने रुपयों की लागत से इस सड़क निर्माण के लिए किस समय स्वीकृति दी गई थी?

(३) क्या यह सही है कि यह सड़क अभी तक बननी प्रारम्भ नहीं हुई है? यदि हां, तो किन कारणों से नहीं बन सकी और अब कब तक बनना प्रारम्भ हो जायेगी?

उत्तर

(१) नहीं।

(२) ६०००) रु० की मंजूरी सन १९६७ में दी गई थी।

(३) जी हां। धन की कमी के सबब से निश्चित नहीं कहा जा सकता।

पंचायत समिति चिड़ावा के पी०डी० खाते में धनराशि

२३१. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति चिड़ावा के पी० डी० खाते में तारीख ५-५-६७ को कितनी धनराशि बची हुई थी?

(२) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा ४५,०००) रुपयों की धनराशि पंचायत समिति चिड़ावा को नेहरू नगर बसाने के लिए दी गई थी तथा ६००० रु० की धनराशि बख्तावरपुरा ग्राम में पक्की सड़क बनाने हेतु पंचायत समिति के पी० डी० खाते में ता० ५-५-६७ के पूर्व जमा हो चुकी थी लेकिन अभी तक खर्च नहीं की गई है?

(३) क्या यह सच है कि उपरोक्त ५१०००) रु० की धनराशि पंचायत समिति के पी०डी० खाते के नियम विरुद्ध निकालकर दूसरे कार्यों में खर्च करली गई है तथा ५१०००) रु० की धनराशि पंचायत समिति के पी० डी० खाते में बची हुई नहीं थी?

(४) अगर हाँ, तो राज्य सरकार इसमें किसे दोषी समझती है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) ११८४) रु० १७ पैसे

(२) नेहरू नगर बसाने को कोई धनराशि नहीं दी गई। बख्तावरपुरा की सड़क के लिए ५०००) रु०

Page No.33

(श्री मूलचन्द कटेवा)

जिलाधीश की स्वीकृति द्वारा प्राप्त हुआ जो खर्च नहीं हुआ ।

(३) धनराशि अन्य कार्यों में खर्च की गई, पर यह नियम विरुद्ध नहीं था ।

(४) कोई दोषी नहीं है ।

गांव बांकली से उम्मेदपुर सड़क की मरम्मत

२३६. श्री माधोसिंह (आहोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गांव बांकली से पावटा, सेदरीय बालोतान होती हुई जो ग्रेवल रोड उम्मेदपुर (त० आहोर) आती है उसकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती है ?

उत्तर

यह सड़क इस विभाग की मरम्मत लिस्ट पर नहीं है ।

जिला बांसवाड़ा में सहकारी चावल उद्योग मिल

२४०. श्री हीरा भाई (कुशालगढ़ सु.): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में तहसील स्तर पर सहकारी चावल उद्योग मिल खोलने के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों ने १९६५-६६ में कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो प्रत्येक तहसील में कितने-कितने सदस्य बने थे ?

(२) क्या इन सदस्यों की हिस्सा पूंजी किन्हीं बैंकों में जमा है? यदि हां, तो किस-किस बैंक में कितनी-कितनी रकम किस-किस के नाम से जमा है ?

उत्तर

(१) जी हां, कुशलगढ़ एवं गढ़ी की तहसीलों में क्रमशः १०६ व २३ सदस्य थे ।

(२) जी हां, इन सदस्यों की एकत्रित हिस्सा राशि १६४०) रु० एवं ११५०)रु० क्रमशः बांसवाड़ा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि०, में बांसवाड़ा की कुशलगढ़ एवं परतापुर शाखाओं में कुशलगढ़ एवं गढ़ी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के बचत खाते में जमा है ।

जिन्होंने यह राशि इन शाखाओं में व्यक्तिगत सदस्यों एवं अन्य सरकारी समितियों में एकत्रित कर जमा करवाया है ।

नीम का थाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति में तेल की छीजत

२४२. श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नीमका थाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा ६० ड्रम किरोसिन तेल की छीजत बताई गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी हां, समिति के अध्यक्ष व व्यवस्थापक का इस सम्बन्ध में जवाब मांगा गया है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये ।

(११.०५ म० प०)

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अध्यक्षीय निर्णय

श्री अध्यक्ष: जैसलमेर जिले की ६५० वर्गमील भूमि फील्ड फाइरिंग रेंज घोषित करने के फलस्वरूप १२००० नगरवासियों के विस्थापित होने जाने संबंधी विषय पर श्री बाल सिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । चूंकि

Page No.34

(श्री अध्यक्ष)

इस मामले का सीधा सम्बन्ध भारत सरकार से है अतः मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता। किन्तु सम्बन्धित मंत्री महोदय स्पष्टीकिरण के तौर पर एक वक्तव्य यदि जानकारी हो तो दें।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी करें। यह रिहेबिलिटेशन का सवाल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जरूर है।

श्री अध्यक्ष: धौलपुर सब डिविजन में डाकुओं के आतंक संबंधी विषय पर चूंकि ३१-५-६७ को वक्तव्य दिया जा चुका है जिसमें माननीय श्री राम किशन द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव में प्रस्तुत स्थिति का पूर्णतया स्पष्टीकरण कर दिया गया इसलिए मामला बहुतांश में वही है। इसलिए फिर वक्तव्य देने कि स्थिति पैदा नहीं होती। जन-स्वास्थ्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

श्री भैरोंसिंह : फील्ड फाइरिंग के काम संबंधी आपने व्यवस्था दी है कि यह केन्द्रीय सरकार का काम है लेकिन जिनको अफेक्ट किया जा रहा है उनका रिहेबिलिटेशन का काम है, वह राज्य सरकार के हाथ में है। उसी प्रश्न को लेकर स्थगन-प्रस्ताव दिया गया है। हमारा स्थगन-प्रस्ताव फील्ड फायरिंग हटाने के लिए नहीं है, वहां के निवासियों के रिहेबिलिटेशन के बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मैंने स्वयं ने स्थगन प्रस्ताव के इसके दो हिस्से समझे हैं। पहला हिस्सा तो केन्द्रीय सरकार से संबंधित हो सकता है लेकिन दूसरा जो रिहेबिलिटेशन से संबंध रखता है उसकी जानकारी राज्य सरकार को हो सकती है, इसलिए मैंने वक्तव्य देने के लिए कहा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने तो ऐसा फरमाया है कि यदि जानकारी हो तो वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : जनकारी होना तो आवश्यक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस साइट का केन्द्र द्वारा सिलेक्शन हुआ है, उसमें राज्य सरकार की अनुमति ली गई है या नहीं ? एक क्षेत्र के अन्दर यदि १२,००० आदमी विस्थापित हों, वहां का पॉपुलेशन का रेश्यो मेरे खयाल से ३-४ पर स्क्वायर मील होगा और उसमें १२ हजार आदमियों का विस्थापित होना, इस साइट सिलेक्शन में कोई न कोई घोटाला है, साइट सिलेक्शन फॉल्टी है। साइट सिलेक्शन के अन्दर अगर राज्य सरकार की अनुमति नहीं ली गई है तो राज्य सरकार को उस संबंध में आपत्ति उठानी चाहिए यह तो कार्ट बिफोर दी हॉर्स है। विस्थापितों का संबंध राज्य सरकार से है ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय नेता महोदय। मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे।

(१२.०८ म० प०)

नगरपालिका, छाबर के कर्मचारियों की हड़ताल पर शासकीय वक्तव्य

श्री नारायण सिंह मसूदा (स्वायत्त शासन मंत्री) : नगरपालिका, छापर के कर्मचारीगण दिनांक १३-३-६७ से हड़ताल पर हैं

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

कर्मचारियों की मांगे निम्न प्रकार हैं:—

(१) कर्मचारियों को दि० १-६-६६ से वेतन दिलाया जावे।

(२) वर्दियां दिलाई जावें।

(३) वार्षिक वेतन वृद्धियों के एरियर का भुगतान किया जावे।

(४) मेडिकल एलाउन्स दिया जावे।

(५) कर्मचारियों की सर्विस बुकें तैयार की जावें।

पालिका के ३२ कर्मचारी हड़ताल पर हैं जिनमें २७ हरिजन, १ पम्प ड्राइवर, २ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं १ ऑक्ट्राय मोहर्रिर है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को वर्दियां देने एवं मेडिकल एलाउन्स का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम व आदेश प्रसारित कर दिये हैं, परन्तु पालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से कर्मचारियों को वेतन (जिसमें वार्षिक वृद्धियां शामिल हैं) व मेडिकल अलाउन्स का भुगतान नहीं कर सकी है। निर्वाचित बोर्ड ने भी गृह कर नहीं लगाया इससे वर्ष १९६६-६७ में मिलने वाली राजकीय सहायता भी पालिका प्राप्त नहीं कर सकी। यह भी एक कारण पालिका को कम आय का होना है। विभाग में श्रम विभाग के मार्फत हड़ताल तोड़ने के प्रयत्न किये परन्तु सफलता नहीं मिली और यह जारी है। कर्मचारी यूनियन की ओर से हड़ताल के सम्बन्ध में तार प्राप्त होने पर पालिका के अधिशासी अधिकारी को बुलाया गया है और ज्ञात हुआ कि पालिका के पास इस समय ३५००) रुपये वेतन देने को उपलब्ध हैं। हड़ताल के प्रश्न को हल करने के निम्न पहलू हैं:

(१) प्रशासक नगरपालिका से कहा जावे कि वह गृह कर की वसूली नियमानुसार शीघ्र शुरू कर दे। जिससे भविष्य में नगरपालिका की आय में वृद्धि हो।

(२) जब तक कर्मचारियों को पूरा वेतन न दे दिया जावे कोई अन्य व्यय न किया जावे।

(३) वर्तमान कर्मचारियों को वेतन देने के बाद उनकी संख्या में कमी करने पर बोर्ड विचार करे।

इस विभाग के बजट में नगरपालिकाओं को कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के लिये ऋण देने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है। सहायता भी उसी स्थिति में मिल सकती है जबकि नगरपालिका गृह कर लगावे।

ऐसी स्थिति में प्रशासक, नगरपालिका को आदेश उपरोक्त के अनुसार दिये जा रहे हैं जिससे कि कर्मचारियों को वेतन शीघ्र से शीघ्र मिल सके।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, धन की कमी के कारण आप फरमा रहे हैं कि वेतन नहीं चुका पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पर २२ हजार रुपया आगे जो कर लगे हुए हैं उन्हीं का बाकी पड़ा हुआ है। नये कर लगाने से क्या फायदा? ११ महीने तक आप वेतन नहीं चुकायें तो यह तो भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा है। वहां पर तीन महीने से सफाई नहीं हो रही है। सफाई नहीं होने से वहां पर हैजा और अन्य महामारी फैल सकती है। विभाग को अभी तक इसकी जानकारी ही नहीं है। यह बात शोचनीय है और इस तरह की स्थिति नहीं होने देनी चाहिये।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था कर सकती है कि नगरपालिका को मिलने वाली ग्रान्ट-इन-एड में से उन हरिजनों की तनख्वाह चुकवा दें ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि उन्होंने हाउस टैक्स नहीं लगाया और उनके पास ३ हजार से अधिक रुपया है इस लिए ग्रान्ट-इन-एड आदि की व्यवस्था नहीं हो सकती। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है तो यह निर्णय ही हो सकता है कि १५०० और ऑक्ट्राय आदि की जो इनकम आवेगी उनसे शनैः शनैः चुकारा किया जाय इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।

श्री लाभचन्द बैद : २०-२२ हजार रुपया लोगों में रेवेन्यू, ऑक्ट्राय आदि के बाकी पड़े है उसको क्यों नहीं वसूल किये जा सकते हैं ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : वह वसूल किये जाने चाहिये थे। एकदम वसूल नहीं किये जा सकते हैं।

श्री लाभचन्द बैद : वसूल क्यों नहीं किये।

श्री नारायण सिंह मसूदा : म्युनिसिपल बोर्ड था।

श्री लाभचन्द बैद : वहां पर प्रशासक है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : अब है। चार महीने से है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : प्रशासक के जरिये हाउस टैक्स लगाया जाय तब तक के लिये तनख्वाह के चुकारे के लिये सरकार लोन दे दे और हाउस टैक्स की रकम से वापिस वसूल कर ले।

श्री नारायण सिंह मसूदा : जो काम किया जाना है उसके लिये मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्री मूलचन्द डागा : फिलहाल लोन दे कर समस्या को सुलझाया जाय।

श्री अध्यक्ष : आल हाइपोथेटिकल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : चार पांच साल से प्रशासक मौजूद है। हाउस टैक्स ओब्लीगेटरी है। एडमिनिस्ट्रेटर ने हाउस टैक्स नहीं लगाया तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : हाउस टैक्स ओब्लीगेटरी है इसके लिये तो कोटा नगरपालिका को विदित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): कोटा नगरपालिका में ११ महीने तक तनख्वाह नहीं मिली है यह तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर के कारण हुआ है। हड़ताल करते रहें और आपको मालूम नहीं हो इससे अधिक क्या आपके लिये शर्म की बात हो सकती है।

श्री रावतराम (छापर) : पिछले ११ महीने से क्यों नहीं तनख्वाह मिली है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : स्वायत्त शासन पद्धति का रूप है और अपनी जिम्मेदारी को वहन करते हुए सारे टैक्स वसूल करलें और चुकारा भी कर दें तो फिर ऐसी स्थितियां आ नहीं सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तो अभी मुकर्रर हुआ है और यह सारा चिट्ठा उसके सामने आया है। हम

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
यह प्रयत्न कर रहे हैं कि बकाया जितना हो वह शीघ्र चुकाया जा सके।

श्री लाभचन्द वैद : तीन महीने तक हड़ताल जारी रहने पर भी मंत्री-मंडल को मालूम नहीं। क्या यह जिम्मेदारी वहन करने के लक्षण हैं ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : हैं क्या ये लक्षण ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : तीन महीने की हड़ताल की तो मुझे सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी जानकारी में यह कब आया कि हड़ताल चल रही है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : सूचना आना अवशेष है।

(विराम)

आय व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद विवाद।

श्री भैरोंसिंह।

(१२.१७ म०प०)

आय व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल,जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य का बजट इस बार राजस्थान के एक नये मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है और यह स्वाभाविक है कि नया व्यक्ति जब किसी विभाग को नये रूप से सम्हालता है तो उसमें कुछ नवीनता लाने की चेष्टा करता है। वर्तमान वित्त मंत्री महोदय ने इसमें कोई विशेष नवीनता लाने का कष्ट किया हो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है लेकिन एक नवीनता प्रकट रूप से लगी है कि भविष्य में बजट सदन में प्रस्तुत करना यह निरर्थक और एक माने में कहा जाय तो केवल मात्र एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्मेलिटी है जिसको पूरा करने के लिये ही इस बजट को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, न तो बजट की कोई सेंक्टीटी है, कितना खर्चा होगा, कितनी आमदनी होगी, उसके अनुमान के उपरान्त खर्चा और आमदनी के आंकड़े कितने होंगे उसकी कोई सीमा नहीं है और इसीलिये कहना चाहता हूं कि इस सेशन से यह बजट केवल मात्र एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करने की गरज से ही माननीय मंत्री महोदय ने यह कष्ट किया है। यदि आप मोटे रूप में ध्यान देकर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि यह बजट अपने आप में बहुत बड़ा स्कैन्डल है। स्कैन्डल इस सेन्स में कि जितना खर्चे का अनुमान रखा था, ९७ करोड़ के खर्चे का, उसके विरुद्ध ११५ करोड़ रुपया खर्च किया। इसी तरह से केपिटल अकाउन्ट में १७ करोड़ खर्च करना था उसकी जगह २८ करोड़ रुपया खर्च किया। दोनों को मिला कर, अध्यक्ष महोदय, २९ करोड़ रुपयों का अतिरिक्त खर्चा किया। यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार खर्च पर कन्ट्रोल नहीं कर सकती और दूसरी ओर यदि खर्च बढ़ता जाय और उसके साथ आय भी बढ़ती जाय तो कुछ अंशों में बात समझ में आ सकती है कि हमने आय के अनुसार खर्चा किया। लेकिन इस वर्ष जहां ९८ करोड़ की आय का अनुमान था वहां केवल ९९

(श्री भैरोंसिंह)

करोड़ की आय हुई है । २ करोड़ की उसमें कमी हुई और खर्चे में २९ करोड़ का आधिक्य हुआ । यह सब मोटे उसूल का है । इस वर्ष बजट की सैंक्टीटी समाप्त करके, लेजिस्लेचर की इम्पोर्टेन्स को समाप्त करके हमने यह अतिरिक्त खर्चा किया और इस अतिरिक्त खर्चे के कारण मैं आगे बताना चाहूँगा । लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है चुनाव का वर्ष था और चुनाव जीतने के कारण यह सारा खर्चा किया ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, इसमें देखना चाहें तो स्केण्डल और सामने आता है । आज हमारा रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर इतना बढ़ता जा रहा है कि जो इस सरकार के लिए आज अनकन्ट्रोलेबल है । यह सरकार उसे कन्ट्रोल नहीं कर सकती । वह मजबूर है । इसी कारण इस सरकार ने अगले वर्ष का जो बजट बनाया वह बिल्कुल असन्तुलित है । इसके लिये हमने १२७ करोड़ के खर्चे का प्रावधान रक्खा, जब कि हमारी आय ११५ करोड़ की होगी । इस प्रकार १३ करोड़ के घाटे का बजट हमारा यह है । हम चाहें आंकड़ों में उतार-चढ़ाव करके उसे तीन करोड़ के घाटे में ले आवें या आगे चलकर ८ लाख का सरप्लस कर दें । पर वास्तविकता से दूर नहीं जा सकते कि १५ करोड़ का घाटा है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि राजस्थान की यह सरकार नये रूप से यह स्वीकार करके चल रही है कि हम कैपिटल एक्सपेन्डीचर में बचत करें । पूंजी खाते में, आय में १२ करोड़ रुपये रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में बढ़ाकर खर्चे को मीट करने की व्यवस्था कर रहे है । इससे यह स्पष्ट है कि अब इस शासन ने अपनी जमा पूंजी असैट्स को खाना शुरू कर दिया है । जैसे किसी को भोजन न मिले तो एक स्टेज यह आती है कि भूख के कारण अपने शरीर के तत्व को ही खाना शुरू करता है । एक दिन खाते खाते ये तत्व भी समाप्त होते हैं और शरीर भी समाप्त होता है तो राजस्थान की सरकार ने भी रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर के घाटे की पूर्ति के लिये कैपिटल से १२ करोड़ ट्रान्सफर कर ३ करोड़ के घाटे पर लाने की कोशिश की है ।

तीसरा स्केण्डल और बताऊं । विधान सभा में कई बार जब हमने इस सरकार को दिवालिया बताया था, आर्थिक दृष्टि से बिलकुल एक गलत रास्ते पर चलने वाली सरकार बताया था तो हमारे मुख्यमन्त्री ने कई बार सदन में खड़े होकर बार बार यह दोहराया कि हमारी लाइबिलिटीज कम हैं असैट्स ज्यादा हैं । पर इस वर्ष हमारे वित्त मन्त्रीजी ने जो चित्र प्रस्तुत किया तो लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई, असैट्स कम हो गये और ११ करोड़ का डिफरेन्स आ गया ।

इसका मतलब यह होता है कि इस वर्ष से लाइबिलिटी के अगेन्स्ट में असैट्स को खाना शुरू करते हैं । इसको खाते खाते हम किस स्टेज पर पहुँचेंगे इससे साबित होगा अध्यक्ष महोदय कि पिछली बार राजस्थान सरकार ने पांच करोड़ रुपयों का पब्लिक लोन फ्लोट किया था । इस सदन को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि चाहे मुख्यमन्त्री महोदय या सरकारी पक्ष यह कभी भी बताने को तैयार नहीं होंगे कि जो लोन फ्लोट किया जाता है तो आज तक ता इस

Page No.39

(श्री भैरोंसिंह)

आशा से किया जाता था कि पब्लिक उसमें सब्सक्राइब करेगी पर इस वर्ष आपको यह सुनकर सदमा पहुंचेगा कि वह ५ करोड़ का लोन फ्लोट किया तो पब्लिक ने नहीं भरा उसे, बल्कि राजस्थान सरकार ने अपनी शान को बनाये रखने के लिए १४० लाख रुपया कन्सोलिडेटेड फण्ड से सब्सक्राइब करके इसे पूरा डिक्लेयर किया है। यह इस सदन के साथ बहुत बड़ा धोखा है। राजस्थान की जनता के साथ धोखा है और यह साबित होगया है इससे कि इस सरकार की इज्जत दो कौड़ी की रह गई है। इस सरकार को जनता का कोई व्यक्ति १४० लाख का कर्जा देने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में यह राजस्थान की सरकार पहुंच चुकी है।

अब अध्यक्ष महोदय इसका परिणाम क्या निकलता है। मैं मोटे मोटे परिणाम इस सदन के सामने रखना चाहूंगा।

राजस्थान कैनाल का प्रश्न आता है। इसके ऊपर हमने फर्स्ट स्टेज में ७५ करोड़ का खर्च करने के लिये रखा था और दूसरी योजना तक हमने इस पर ४२ करोड़ का खर्चा कर दिया। ३३ करोड़ शेष रहते हैं। अब सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसके हिसाब से प्रत्येक वर्ष के लिये फाइनेन्शियल एलोकेशन की बात कही गई। इसके हिसाब से हमें इस वर्ष ९ करोड़ रुपया इस पर खर्च करना चाहिये था। पर दुर्भाग्य यह है कि हम इस ६ करोड़ की व्यवस्था इस साल नहीं कर सके और इस बजट में केवल ३ करोड़ की व्यवस्था की है।

इससे स्पष्ट है कि आज जिस राजस्थान कैनाल पर हम फर्स्ट स्टेज में ७५ करोड़ खर्च करना चाहते थे और दूसरी स्टेज में साठ करोड़ जो इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट है, सारा संसार जिसकी इम्पोर्टेन्स मानकर चलता है उसको फीड करने के लिये इस साल हमने केवल तीन करोड़ की धन राशि की व्यवस्था इस बजट में की है। एलोकेशन करते वक्त हमने कहा था कि प्रथम वर्ष हम इतना खर्च करेंगे। अगले वर्ष इतना करेंगे। पर इस वर्ष आपने तीन करोड़ की धन राशि निर्धारित की है। अब कोई भारत सरकार से कर्जा भी नहीं मिलता। यह कर्जे की स्थिति तो मैं आगे बताऊंगा कि सरकार यह कर्जा किस प्रकार चुकावेगी, या चुका भी पावेगी या नहीं।

इस स्थिति में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह असर जो हमारा फाइनेन्शियल डिसिप्लिन पर हुआ उसका असर राजस्थान कैनाल के साथ साथ हमारी चौथी योजना पर भी पड़ा। प्लान के फर्स्ट ईयर में जहां हमने ४८ करोड़ खर्च किया वहां पूरे प्लान की हिस्ट्री उठा कर आप देख लें कि पहली दूसरी और तीसरी प्लान में प्रत्येक वर्ष में प्लान का खर्चा बढ़ता जा रहा है पर यह पहला साल है चौथी प्लान का जहां बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। जहां पहले हम बढ़ाते बढ़ाते ४८ करोड़ तक पहुँच गये थे वहां हमने इसमें दूसरे वर्ष के लिये ४४ करोड़ का ही निर्धारण किया है। यह हमारी स्थिति है। हमारी फाइनेन्शियल स्थिति बिलकुल वीक होती जा रही है। फाइनेन्शियल डिसिप्लिन हमारा बिगड़ चुका है। किसी प्रकार से इस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं रह गया है।

अब इन खर्चों को मीट करने के लिये इस बजट में ४.५५ करोड़ के टैक्सों का प्रोवीजन किया है।

(श्री मैरोंसिंह)

माननीय सदस्य यह न समझें कि ४५५ लाख का प्रोवीजन रखा है। माननीय सदस्य यह न समझें कि यहां पर हमारी सरकार के वित्त मन्त्रीजी ने जो यह कहा है कि हम केवल २॥ करोड़ के टैक्स लगाना चाहते हैं। बल्कि हमारे वित्त मन्त्रीजी ने तो इस सदन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। टैक्स भी लगे और सदन को पता न लगे। पर वास्तविकता यह है कि सारे घाटे की पूर्ति के लिये हमने ४.५५ लाख के नये टैक्स लगाये हैं। इसके बाद भी अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कहती है कि हम १२० लाख रुपया प्रशासनिक हेरफेर से और हासिल कर लेंगे और इससे हमारी आय बढ़ जावेगी।

यह समझ में नहीं आता कि प्रशासनिक हेर फेर इनका इस वर्ष से ही शुरू होगा। इनको राज्य करते करते १५ वर्ष हो गये। अबतक ये प्रशासनिक हेरफेर नहीं कर सके। अब ये नये वित्त मन्त्रीजी आये हैं जो दम भरते हैं कि वे अब प्रशासनिक हेरफेर से १२० लाख रुपया वसूल कर लेंगे। १३५ लाख की मितव्ययता और ये करेंगे, जो आज तक नहीं कर पाये पन्द्रह वर्षों में वह ये अब करेंगे, तीन लाख राजाओं को दी हुई सुविधाओं को समाप्त करके प्राप्त करना चाहते हैं। ५ लाख सोडियम सल्फेट डीडवाना से पैदा करना चाहते हैं, कुछ अल्प बचतों से, कुछ भारत सरकार से, कुछ कनवर्सन चार्जेज से इस तरह १२७ करोड़ का बजट और १५ करोड़ का घाटा और इसकी पूर्ति के लिये यह मैंने अभी आपके सामने जो प्रस्तुत किये उन उपायों से पूर्ति करेंगे।

इसे मोटे रूप में देखें तो ताज्जुब होगा कि ११२ करोड़ के बजट में ३० करोड़ तो भारत सरकार से जो ऋण लिया था उसकी अदायगी में चला जावेगा, चार करोड़ का पेमेन्ट पुराने पिछले साल के ओवरड्राफ्ट में चला जावेगा। २७ करोड़ का राज्य सरकार लोगों को उधार देगी, २० करोड़ का ब्याज चुकावेगी। १२७ करोड़ के बजट में से से इस तरह ८१ करोड़ तो ऊपर का ऊपर चला गया। बाकी ४५ करोड़ बचे हैं जिनसे हम राजस्थान के दो करोड़ और २८ लाख व्यक्तियों का इन्तजाम करना चाहते हैं। इसी में से लाखों कर्मचारियों को वेतन देना चाहते हैं और इसी से अपने अनाप शनाप शाही ठाठ बाठ और खर्चों की पूर्ति करना चाहते हैं।

इसलिये सरकार की इन हरकतों से मुझे भय है कि कुछ समय बाद राजस्थान सरकार का जो बजट आवेगा, वह जनता का नहीं होगा। जनता के हितों का, जनता की भलाई के कामों का नहीं होगा बल्कि केवल एक बात का होगा कि हमने अमुक कर्जा लिया था उसका चुकारा इस सारे के सारे बजट से करना है। ब्याज चुकाना है अमुक कर्जे के अगेन्स्ट में हमें अपनी सिक्योरिटियां बेचनी हैं। तो इस तरह से अगले साल का बजट हमारा ब्याज चुकाऊ बजट होगा। ऐसी स्थिति इस राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार ने अपने १५ साल के शासन में करदी है। अपने फाइनेन्स की यह हालत इसने कर डाली है।

मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, यह खर्चा किन किन मदों में बढ़ा है। सरकार यह जवाब देगी कि पिछले साल अकाल के लिए ३८० लाख रुपया खर्च करना था पर

(श्री भैरोंसिंह)

उसके विरुद्ध ११ करोड़ खर्च कर दिया। पी. डब्लू. डी. के लिए ६४१ लाख का प्रोवीजन था उसके अगेन्स्ट में ८६६ लाख का खर्चा कर दिया, इसी प्रकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में २६५ की जगह ३२६ लाख का खर्चा होगया, एजूकेशन में १६२ की जगह २१६ लाख का खर्चा होगया। ये मोटे मोटे आईटम्स हैं जिनके अन्दर राज्य सरकार का खर्चा बढ़ा है।

मैं सबसे पहले फेमीन का खर्चा लेना चाहूंगा। यह अभी तक नहीं समझ पाया कि सन ५१ से लेकर ६७ तक लगातार अकाल पड़ते आ रहे हैं। सारे अकाल के वर्षों का योग किया जावे तो अब तक अकाल के राहत के नाम पर ३६ करोड़ रुपया सरकार खर्च कर चुकी है। इसके बाद भी हमारे ये वित्त मन्त्री जी यह पहला एश्योरेन्स देते हैं कि मानसून अच्छा आगया तो राहत देने का, पूरी रोटी देने का प्रबन्ध कर सकेंगे। यह समझ में नहीं आता कि १५ वर्षों से ये राज कर रहे हैं। इस ३६ करोड़ को यदि योजनाबद्ध तरीके से परमानेन्ट आइटम्स पर कन्स्ट्रक्शन के नाम पर वर्क करते तो मानसून का उनको इन्तजार नहीं करना पड़ता। मानसून की महरबानी के भरोसे नहीं रहना पड़ता। इन्द्र भगवान के आगे उनको घुटने नहीं टेकने पड़ते। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इन्द्र भगवान के सामने घुटने टेक दिए। वितमन्त्री जी मानसून की कृपा पर जीवित हैं। अकाल राहत पर अब तक ३६ करोड़ खर्च कर दिया। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने अकाल के कामों में कोई परमानेन्ट काम नहीं किया है।

अकाल के काम पर अपने लोगों को लगाकर उनको ओबलाइज करने की कोशिश की। आज जिस गन्दे तरीके से इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और किस तरह से अकाल घोषित किए जाते हैं उसके बारे में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन दिन पहले इस सदन में बताया था कि उनके क्षेत्र के कुछ गांवों को किस तरह से अकाल ग्रसित घोषित किया गया था हालांकि वहां अकाल नहीं था। क्योंकि वहां से खड़े होने वाले भूतपूर्व वित्त-मन्त्री श्री बालकृष्ण कौल को राज्य सरकार द्वारा कुछ खर्च करवाना था। जिस प्रकार का प्रोसीजर फेमीन होने के लिए आवश्यक है फेमीन कोड के अन्तर्गत जो बात लिखी हुई है उन सबको ताक में रखकर वहां पर फेमीन के काम चालू करवा दिये। जब वे काम शुरू होगये, वहां पर सरकार की तरफ से अतिरिक्त धनराशि की कोई गुंजाइश नहीं थी तो वहां की जिला परिषद् द्वारा एक प्रस्ताव रखवाया गया कि काम पहले चालू होगया तो इन कामों को बदस्तूर चालू रखवाया जाय इसलिए वित्त मन्त्री को काम चालू रखवाने के लिए इसको रेगुलेराइज करवाने के लिए राज्य सरकार को निवेदन करना चाहिए। जब यह कार्यवाही हुई तो राज्य सरकार के वित्त सचिव ने, मुख्य सचिव ने और रिलीफ कमिश्नर ने तीनों ने मिलकर वित्त मन्त्री को ओबलाइज करने के लिए १५४ गांवों को अकाल ग्रसित घोषित करवा दिया। जिसमें न कलेक्टर की सिफारिश थी न एस० डी० ओ० की, न पटवारी और न इन्सपेक्टर की, इनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इनको अकाल ग्रसित घोषित किया है। मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं अकाल के बारे में

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

अजमेर के कलेक्टर ने जो लैटर रिलीफ कमिश्नर को लिखा है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ ताकि सदन को विश्वास हो जाय कि रिलीफ कमिश्नर द्वारा राजनैतिक लाभ उठाने की गरज से किस प्रकार से पैसा खर्च किया गया।

Letter No. DRA/XI (I)/66-67/144 dated 9th February, 1967.

"My dear Shri Jhala,

This is with reference to your D. O. Letter No. 65/PA FC/67, and subsequent letter No. 2996 dated 31st January, 1967 from Assistant Secretary (Relief). I have gone through the zinswar statement of these villages and I find that in many cases even those villages where loss is less than four annas have been declared as scarcity affected villages on the recommendation of Pradhan or Vikas Adhikari. At the time of Girdawari Panchas or Sarpanchas of villages had accompanied the Patwaries. No question of personal inspection arises at this stage as the crops have been removed from the fields as back as November, 1966.

Attestation of the kharaba by village pancha shows that by and large the crop was properly assessed, I fail to understand how Pradhan assesses the kharaba after the removal of crops from the fields. I am enclosing herewith Zinswar statement of these villages along with the names of Persons who remained with the Patwaries throughout crop inspection."

इस पत्र से इस बात का विश्वास होगा कि महारावल साहब ने और सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने जो बात बताई कि अकाल के नाम पर जो पैसा खर्च किया गया वह राजनैतिक आधार पर खर्च किया गया है यह आरोप कितना सत्य है। इस पत्र से यह साफ साबित हो जाता है कि अकाल का पैसा किस तरह से खर्च किया गया इसके अलावा भी और आप सबूत लेना चाहें तो हम दे सकते हैं बशर्ते कि आप इसके लिये इन्डिपेन्डेन्ट इनक्वायरी कमीशन स्थापित करने को तैयार हों तो मैं अन्य कई सबूत प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसी प्रकार का चित्तौड़ के इलाके का उदाहरण है। कलेक्टर ने खराबा नहीं लिखा तो उनको दुबारा लेटर लिखा गया कि फसल कट भी गई है तो दुबारा मौके पर जाकर जांच की जाय इन्सपेक्शन किया जाय। उन को कम्पैल किया गया मिनिस्टर द्वारा और इस तरह से चित्तौड़ की अमुक अमुक तहसीलों में अकाल है इस प्रकार का उल्लेख उनसे करवाया गया। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ ११ करोड़ रुपया जो अकाल के नाम पर खर्च किया गया जिसको सुखाड़िया जी कहते हैं मानवता के नाम पर खर्च किया

Page No.43

(श्री भैरोंसिंह)

गया उनकी यह मानवता कहां तक मानवता है यह उपरोक्त बातों से स्पष्ट हो जाती है। मैं इस बारे में राजस्थान सरकार को चुनौती देकर कह सकता हूँ इस अकाल राहत के नाम पर जो रुपया खर्च किया गया उसके लिये एक इण्डिपेन्डेन्ट आयोग नियुक्त किया जाय मैं सदन को विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जो अकाल के नाम पर ११ करोड़ रुपया खर्च किया गया है उसमें से ५ करोड़ रुपया केवल राजनतिक लाभ उठाने के लिये खर्च किया गया। उसमें अकाल राहत का नाम था राहत कांग्रेस को देनी थी। कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना था। इस अकाल के रुपये का उपयोग खुलकर उनको जिताने के लिये किया गया।

श्री अध्यक्ष : जो पत्र आपने पढ़ा है इसको आप सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर): जब माननीय सदस्य ने पूरा पत्र पढ़ दिया है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जैसी आपकी आज्ञा हो।

श्री अध्यक्ष : आज्ञा यही है कि सदन की मेज पर रख दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : आज्ञा यही है तो सदन की मेज पर रख दूंगा। अभी कहें तो अभी या भाषण के बाद में?

श्री अध्यक्ष : बाद में रख दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल एक प्रश्न आया था फेमीन का खर्चा किस प्रकार हुआ एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बाड़मेर जिले की पॉपुलेशन अफेक्टेड थी, जालौर जिला अफेक्टेड था, सिरोही अफेक्टेड था। बाड़मेर की जनसंख्या ५.७० हजार थी। जालौर की ३.१७ हजार, सिरोही की ३.२७ हजार, बाड़मेर में रुपया खर्च किया गया ३७ लाख, जालौर में पांच लाख और सिरोही में ११ लाख उसके विपरीत डूंगरपुर में जहां पॉपुलेशन अफेक्टेड थी ५ लाख, वहां पर खर्च किया गया १७४ लाख। जालौर में जहां जनसंख्या ३.७० हजार थी वहां पर ५ लाख १९ हजार खर्च किया गया। बांसवाड़ा जहां पॉपुलेशन ४.७४ लाख थी वहां खर्च किया १३३ लाख। उदयपुर जहां पॉपुलेशन ५ लाख ४० हजार थी वहां फमीन के नाम पर १९० लाख का खर्चा किया गया।

इससे यह साफ प्रकट होता है कि जोधपुर डिवीजन में, बीकानेर डिवीजन में जहां अकाल पड़ा करते हैं, सारा नागौर जिला जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में जहां पर अकाल पड़ता रहता है वहां पर रिलीफ के काम चलते हैं तो माना भी जा सकता है। लेकिन जब से मुख्य मंत्री राजस्थान के श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया हुए हैं तब से वे उदयपुर के डिवीजन के लिये अकाल के नाम से प्रकट हुए हैं, या उदयपुर डिवीजन में अकाल डालने की कोशिश करते हैं। इसका कारण क्या है। आज राजस्थान की सब इलाकों की जनता राज्य सरकार को टैक्स देती है, लेकिन वह सारा रुपया अधिकतर उदयपुर डिवीजन में खर्च होता है और अकाल के नाम पर भी वहां ज्यादा खर्च किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पंचायत समितियों को देख लीजिये बाबा आदम के

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

जमाने की वहां तहसीलें बनी हुई थीं, छोटी छोटी तहसीलें जिनमें किसी में बीस गांव तो किसी में तीस, किसी में चालीस उन्हीं को पंचायतों का रूप दे दिया गया है। सारे राजस्थान में जहां २३२ पंचायतें हैं वहां केवल उदयपुर डिवीजन में ५२ पंचायत समितियां हैं यह इसलिये कि विकास के नाम पर लाखों रुपया उनको खर्च के लिये मिला करे, और वह सारा उदयपुर डिवीजन में खर्च किया जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर अकाल है तो क्या एक ही डिवीजन में है। आखिर अकाल के नाम पर आपने ११ करोड़ रुपया खर्च कर दिया, १६ करोड़ रुपया ओवर ड्राफ्ट ले लिया, जिस पर ब्याज चुका रहे हैं। इससे ज्यादा भयंकर स्थिति राजस्थान सरकार की और दूसरी नहीं हो सकती। अकाल के नाम पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये कुछ लोगों को लाभ पहुचाने की गरज से, खर्च किया जाता है।

माइनर इरिगेशन को लीजिये, कहा यह गया है कि माइनर इरिगेशन के लिये रुपया खर्च हुआ। पूरे राजस्थान के अन्दर ६६-६७ के अन्दर ४९ लाख रुपया खर्च किया गया उसमें केवल उदयपुर डिवीजन पर ४१ लाख रुपया खर्च किया गया।

और इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय नेक्स्ट ईयर का जो बजट प्रोवीजन है उसके लिए उदयपुर डिवीजन के लिए २० लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान है जबकि सारे राजस्थान में माईनर इरिगेशन के मातहत १९ लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं। यह है राजस्थान के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेन्डीचर का नमूना जिसको हमारी सरकार कहती है कि हमारे अन्दर किसी प्रकार का कोई रीजनेलिज्म नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि शिक्षण संस्थाओं के लिए हमारी सरकार कहती है कि हमने अनुदान ज्यादा दिये, नए स्कूल ज्यादा खोले। यह हमारी सरकार की कहने की आदत सी बन गयी है। यह तो सौभाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिल कर कांग्रेस किस प्रकार से जीत सके इसके मातहत इलेक्शन के पहले साल प्लान खत्म होता है और उसी साल से अगला प्लान शुरू होता हैं। ४ वर्ष का पैसा एक वर्ष में खर्च करके वोटर्स को किस प्रकार से अट्रेक्ट किया जाये यह योजना बनती है। वित्त मंत्री जी तो हैं नहीं लेकिन जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने पिछली बार वोट्स लेने की गरज से नये स्कूल खोल दिये और उनकी लाईबिलिटी ३० लाख रुपये की ले ली और यह पैसा प्लान में कहीं निर्धारित नहीं है। लेकिन आप देखते थे कि स्कूल खुलें या नहीं हमें इस बात की चिन्ता नहीं हमने तो इस बार स्कूल खोल कर ६७-६८ में वोट्स ले लिये। इसलिए यह ३० लाख रुपए की लाइबिलिटी ले ली। अब सरकार कहती है कि हम तो एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को कन्सोलिडेट करेंगे। यह कन्सोलिडेशन की बात तो चुनावों से पहले भी कही थी, प्लान बना उससे पहले भी कन्सोलिडेशन की बात कही थी और कन्सोलिडेशन की बात को कोठारी कमीशन ने भी कहा। लेकिन आपने कन्सोलिडेशन गत वर्ष नहीं किया और अब चूंकि आगे के

Page No.45

(श्री भैरोंसिंह)

लिए खर्चा नहीं है इसलिए आप कहते हैं कि हम कन्सोलिडेशन करेंगे। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारी राजस्थान की सरकार ने ३६ लाख रुपए की लम्पसम ग्रान्ट ली है। इसलिए हम अनुदान देगें, शिक्षण संस्थाओं में नये अध्यापकों की नियुक्तियां होंगी। यह नियुक्ति नहीं हुई लेकिन ग्रान्ट-इन-एड देंगे और ग्रान्ट इन एड किन को देंगें जिनको देने के लिए कमिटमेंन्ट इस चुनाव से पहले कर लिया। बजट में उनको दिखा नहीं सकते सार्वजनिक डर के कारण परन्तु लम्पसम प्रोवीजन रखकर वह रकम उठाना चाहते हैं और ग्रान्ट-इन-एड भी किस प्रकार से इन इन्स्टीट्यूशन्स को दी जाती हैं मैं कोई लम्बी चौड़ी बहस के लिए नहीं लेकिन उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि राजस्थान में एक राजस्थान महिला विद्यालय है। मशहूर विद्यालय है। राजस्थान में बच्चा बच्चा उसको जानता हैं। अध्यक्ष महोदय आप भी इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस इन्स्टीट्यूशन को ७ वर्षों में ७ लाख २७ हजार रुपया ग्रान्ट-इन-एड का दिया। जो भी हमने ग्रान्ट दी उसका दुरुपयोग किया गया। न केवल राजस्थान की सरकार को धोखा दिया बल्कि भारत सरकार को भी धोखा दिया। यूनीवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन से ज्यादा रुपया ले लिया। आडिट पैरा बना, आडिट पैरा बनने के बाद सेण्ट्रल पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने मामला गया, पी० डब्लू० डी० के इन्जीनियर का झूठा सर्टिफिकेट पेश किया, चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट से झूठा अकाउन्ट पेश कराया, यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमारी सरकार ग्रान्ट-इन-एड किस प्रकार से देती है इस संदर्भ में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट जो कि तीनों बातों से संबंधित है इस सदन में पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"The Committee are perturbed to note that the Executive Engineer, P.W.D. (B. & R.) issued a false valuation certificate about the construction of the women's hostel by the Rajasthan Mahila Vidyalaya. What is worse still is the fact that he issued the certificate without seeing the plans approved by the University Grants Commission or even seeing the building itself. To say the least, the Committee hardly expected such a thing from a responsible officer of the rank of an Executive Engineer."

यह तो इन्जीनियर की करतूत और अब चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट की करतूत सुनिये

"The Committee take a serious view of the issuing of the wrong certificates by the Chartered Accountant in this case. They desire that the Ministry of Education should immediately bring these facts to the

(श्री भैरोंसिंह)

notice of the Institute of Chartered Accountants for suitable action against the party concerned."

अब इसके बाद में यदि आप देखें तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ सदन की मेज पर ही यह किताब प्रस्तुत करना चाहूँगा ताकि सदन इसको अच्छी तरह से देख ले। मैं अंत में एक पैराग्राफ और पढ़ूंगा जो कि इस इन्स्टीट्यूशन के लिए लिखा है:

"The Committee are not convinced with the evidence given by the Principal of the Institution. In the absence of the transfer of the building to the Rajasthan Mahila Vidyalaya, it was improper on the part of the Principal to have evaluated the portion of the old building and show the same as contribution of the Institution. It is strange to note that the first progress report dated 18th January, 1960 showed the amount actually paid out during the quarter as Rs. 36,000 when the total grant received from the U.G.C. was Rs. 30,000 and the Institution had only incurred an expenditure of Rs. 2,067.57 against this. It was, therefore, wrong on the part of the Principal to have shown the balance with the Institution as 'nil' in the progress report. The Committee are unfortunately left with the impression that the Principal of the Institution gave the false progress reports from time to time only to mislead the U. G. C. with a view to getting the release of grant by the University Grants Commission. The Committee deplore such an attitude on the part of the head of the academic institution which is supposed to maintain high standards of ethics from which the students and others should draw inspiration."

इससे इस बात का सबूत हो जायेगा कि आज किस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स को हम सहायता दे रहे हैं। इस इन्स्टीट्यूशन के प्रिन्सिपल श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत हैं। यह दुर्गावतजी हमारी सरकार के मुंह लगे व्यक्तियों में से हैं।

श्री अध्यक्ष : वह प्रिन्सिपल नहीं है। He is not the Principal of the College.

श्री भैरोंसिंह : क्या हैं साहब ? Kindly correct me.

श्री अध्यक्ष : Somebody else other than Mr. Durga Singh.

श्री भैरोंसिंह : But the report concerns with Mr. Durga Singh.

श्री अध्यक्ष : It concerns the Principal.

श्री भैरोंसिंह : He is member of the Managing Committee.

श्री अध्यक्ष : That is correct.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी हालत में हम यह समझकर चलें कि आज इस प्रकार से हम ग्रान्ट-इन-एड दे रहे हैं और उसका कितना उपयोग होता है। यह मैंने एजूकेशन के बारे में अर्ज किया।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में २८५ लाख रुपये की जगह ३२६ लाख रुपये खर्च हुए। यह किस कारण खर्चा आ गया, यह क्यों आया? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नयी नियुक्तियां नहीं हुईं। हां, यह सही है कि २ डिप्टी मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स बन गए लेकिन उसके कारण भी जो बचत हुई उस बचत को खा गये, नये खर्चे को खा गये। इसके पीछे एक कारण है कि मंत्रियों की कारों के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ और माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि १ लाख रुपये का ज्यादा खर्चा इनके ट्रंक काल्स और टेलीफोन्स पर हो गया। यह सरकार जनता को कमर कसने की बात कहती है लेकिन मंत्री महोदयों ने १ लाख रुपये का ज्यादा खर्चा ट्रंक काल्स और टेलीफोन्स पर किया। बिजली और पानी के ऊपर ज्यादा खर्चा किया, कनवेयेन्स के ऊपर किया, टी० ए० और डी० ए० के ऊपर ज्यादा खर्चा किया और यह उसका परिणाम है कि जी०ए०डी० में ज्यादा खर्चा पड़ा। यह कहते हैं कि हमने पी०डब्ल्यू०डी० में ज्यादा खर्चा किया। पहले साल के बजाय इस साल ८६० लाख रुपया का खर्चा पी०डब्ल्यू० डी० में किया। मैं मानता हूँ कि पी०डब्ल्यू०डी० में इस प्रकार का खर्चा हुआ उसमें हमारी राजस्थान की सरकार यह कहकर नहीं चल सकती कि हमने जो बोर्डर रोड्स बनाई उनका खर्चा इसमें शामिल है। वास्तविकता यह है कि बोर्डर रोड्स के लिए हमें खर्चा भारत सरकार से मिलता है। वह इसमें शामिल नहीं है। लेकिन पी० डब्ल्यू०डी० के नाते हमने इन्हीं चुनावों के दिनों में जगह जगह ऐसी सड़कें बनवा दीं जिनका आज के दिन कोई ठिकाना नहीं है। वह रोड्स टिकने वाली नहीं हैं। एक सड़क का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। बाड़मेर में चौहटन से रामसर तक एक सड़क बनी है उसकी सरकार जांच करा ले कि उसमें कितना खर्चा हुवा और क्या वह इस बरसात के बाद टिकने वाली है या नहीं? सड़कों का पता नहीं, पैसों का पता नहीं। पानी की तरह पैसा बहा दिया लेकिन सरकार के खजाने से खर्चा किया और उसकी पूर्ति के लिए टैक्स लगा दिया। इस पी०डब्ल्यू०डी० के नाम पर वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं वर्ना मैं कहना चाहता हूँ कि हम और चीजों को बरदाश्त कर सकते हैं, छोटे मोटे खर्चों को बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने नेशनल क्राइम किया है और इसके लिए न केवल उनकी आलोचना की जाय बल्कि इन्क्वायरी करके उनका प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिये। बोर्डर डिफेन्स के लिए हमारी सरकार ने

(श्री भैरोंसिंह)

५ करोड़ २० लाख रुपया इस बात के लिये दिया था कि हम मशीनरी खरीदकर कान्ट्रे-क्टर्स को उधार दें और उधार देने के बाद जल्दी से जल्दी रोड्स का निर्माण करायें। पिछले वर्ष अध्यक्ष महोदय, हमने ८८ लाख रुपये की मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी में ट्रेक्टर्स थे, उस मशीनरी में बुल्डोजर्स थे, ट्रोलीज थीं और कोंक्रीट मिक्सर्स थे। इस तरह का सामान खरीदा गया। मैंने पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों से जानकारी प्राप्त जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानकारी प्राप्त की और उस जानकारी के आधार पर मैं अर्ज करता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० में जीपें खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन हमारी सरकार ने जीपें भी खरीदीं बाकी का सामान भी खरीदा और सारा सामान, अध्यक्ष महोदय खरीदने पर शर्त यह है कि पी० डब्ल्यू० डी० रूल्स के अनुसार भी कि उस सामान को किराये पर दे सकते हैं लेकिन उस सामान को उधार नहीं दे सकते। हमने उस सामान को उधार पर दिया। हमने अपने राजस्थान सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड में से पैसा दिया और उस पैसे से खरीदा हुआ वह सामान ठेकेदारों को जो कि किराये पर ही ले सकते थे उनको किराये पर नहीं देकर उधार दे दिया। अब सरकार यह कहती है कि पी० डब्ल्यू० डी० कोन्ट्रेक्टर से जो १० प्रतिशत अरनेस्ट मनी जमा होती है उसके अगेन्स्ट में वह सामान दिया गया तो यह बात भी बिल्कुल गलत है। वास्तविकता यह है कि ठेकेदारों को कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाओ, वहां कांग्रेस को चन्दा दो, चन्दे का हमें क्लियरेंस दिखाओ और उसके बाद यह सामान पड़ा है उस सामान को ले लो। जीपें तुम्हारे नाम पर रहेंगी लेकिन इन्हें तुम इलेक्शन के बाद ले जा सकोगे। जीपें लेंगे हम और जब चुनाव हो जायेंगे तब तुम्हें वापिस कर देंगे। ठेकेदारों ने इसी के अनुसार जीपें लीं और उन जीपों का उपयोग कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावों में किया गया। इन ठेकेदारों से पैसा लिया गया। उधर हमारे बोर्डर रोड्स पर जो काम होता था वह काम ठप्प हो गया लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनाव के लिए इस पैसे का दुरुपयोग किया, डिफेंस रोड्स के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जिस अन्याय का पश्चाताप हम भाषणों से नहीं कर सकते हैं बल्कि ऐसा करने वालों का प्रोसीक्यूशन करके ही इसका पश्चाताप कर सकते हैं। यह हालत हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारा खर्चा और कामों में भी हो रहा है। मैं मानता हूं कि खर्चा होता है, लेकिन खर्चे के साथ हमारी आमदनी भी बढ़नी चाहिए। आमदनी होती नहीं, केवल मात्र खर्चा होता है। मैंने राजस्थान के इन्कम के सोर्सेज को देखा और इन्कम के सोर्सेज के साथ जो खर्चे के सोर्स हैं उनको भी देखा। आपकी आमदनी के सोर्स कम होते जा रहे हैं और जिन आइटम्स पर आपने टैक्स लगा रखा है उनमें भी कमी होती जा रही है। सैल्स टैक्स से जो आपको १५५० लाख की आमदनी थी वह १५०० लाख रह गई है। अन्य कर जो ६४ में ३७६ लाख थे वे ३५० लाख रह गये हैं। इसी प्रकार से खनिज के आयात शुल्क और रोयल्टी से जो १७४ लाख की आमदनी होती थी वह केवल १५१ लाख की आमदनी रह गई है। बहुद्देशीय

(श्री भैरोंसिंह)

योजनाओं से ५६ लाख की आमदनी होती वह ५१ लाख की आमदनी रह गई है। गंग नहर एक आमदनी का बहुत अच्छा जरिया था, इससे आपको ५४ लाख की आमदनी होती थी जो घट कर ४२ लाख रुपये पर पहुंच गई है। यह किस प्रकार से हमारे खर्चे बढ़ते जायं और हमारी आमदनी के सोर्स कम हो जायं, पिछले दिनों गंग नहर के बारे में यहां पर सवाल उठाए गए, सदन के सभी लोगों ने यहां आवाज उठाई कि गंग नहर से पानी कम आ रहा है लेकिन सरकार कहती रही कि गंग नहर से पानी कम नहीं आ रहा है। लेकिन यह इसका सीधा प्रमाण है कि गंग नहर से पानी कम आया और पानी की कमी के कारण ही गंग नहर से जो आमदनी होती है वह आमदनी नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, सैल्स टैक्स के बारे में हमारी सरकार कहती है कि केन्द्रीय कानून के अनुसार जो रेट्स बढ़ीं उन्हें यहां पर हम लागू नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? एक साल का समय निकाल दिया, भारत सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया और उन टैक्सों के अनुसार राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए आप एक साल में कोई संशोधन नहीं कर सके इससे बढ़कर अयोग्यता का क्या सबूत हो सकता है। आप कहते हैं कि हम खनिज से और पर्टिक्यूलरली गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के द्वारा निकाली गई खड़िया मिट्टी की रायल्टी लेना चाहते हैं। रायल्टी कलेक्शन से आज तक जो हमें लाखों रुपया मिलता वह मिला नहीं बल्कि हमने उसमें कन्सेशन और कर दिया और उस कन्सेशन के कारण जितनी आमदनी होनी चाहिए थी उतनी आमदनी नहीं हुई।

इसी प्रकार से मेजर, मीडियम और माइनर इर्रिगेशन हैं वह भी बहुत बड़ा घोटाला है। इस सम्बन्ध में आज तक हमने माइनर इर्रिगेशन के कामों पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट की मार्फत ५० लाख रुपया खर्च किया है और इस पचास लाख रुपये के खर्च करने के बाद भी माइनर इर्रिगेशन वर्क्स के रिजल्ट धरती पर नहीं हैं, माइनर इर्रिगेशन से सिंचाई धरती पर नहीं, कागजों पर होती है। इन माइनर और मीडियम इर्रिगेशन वर्क्स से उत्पादन कागजों पर होता है जमीन पर नहीं होता है। इन सबका प्रत्यक्ष प्रमाण यदि आप लेना चाहते हैं तो आडिट रिपोर्ट को देख लीजिए, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को देख लीजिए, लाखों रुपये इन माइनर और मीडियम वर्क्स पर खर्च कर दिए गए हैं। लाखों रुपये हमने मीडियम प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिये, ६७ लाख रुपया खर्च करने के बाद केवल कितनी धरती की सिंचाई होती है ३३०० एकड़ की। ६७ लाख का खर्चा और सिंचाई होती है ३३०० एकड़ पर, इससे बड़ा राजस्थान का दुर्भाग्य नहीं हो सकता और सरकार की अकर्मण्यता और अयोग्यता की मिसाल नहीं हो सकती। आज हमारे वित्त मन्त्रीजी कहते हैं कि धरती की सीलिंग से अधिक पर सरचार्ज बढ़ायेंगे और क्यों बढ़ायेंगे क्योंकि इस सब प्लान वगैरा का फायदा कुछ लोगों को होता है, बाकी लोग उस बर्डन को क्यों उठाएं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह ६७ लाख का खर्चा अनावश्यक रूप से इस राजस्थान की सरकार ने कर दिया तो वह राजस्थान की जनता क्यों भोगे। जो इसके लिए

(श्री भैरोंसिंह)

जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इन्जीनियर हैं, जो सेंक्शनिंग आथोरिटीज़ है, जो एग्ज़ीक्यूटिव आँथोरिटीज़ हैं, जिन लोगों ने ये गल्तियां की हैं उनसे यह रुपया क्यों नहीं वसूल किया जाय, क्यों इस गरीब जनता को टैक्सों से दबाया जाय। लेकिन हमारी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि खर्चा भी बढ़े लेकिन इन खर्चो की मदों में जो प्रोडक्टिव और नोन-प्रोडक्टिव आइटम हैं, इनमें खर्चा बढ़ने के साथ साथ आमदनी भी बढ़नी चाहिए। यह मानी हुई बात है कि नोन डेवलपमेंट वर्क्स पर खर्चा कम हो लेकिन आपका खर्चा नोन डेवलपमेंट वर्क्स पर बढ़ता जा रहा है। आप कोईसा भी बजट एस्टीमेट्स देखें। मैंने ६३-६४ से हिसाब निकाला है। इस हिसाब के अनुसार आपका खर्चा ३४ की जगह ३६, ३५ की जगह ४६, ४२ की जगह ५४ इस प्रकार आपका नोन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर है। आपका नोन डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है और डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर या तो स्ट्रैग्नेंट रहा है या कम हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी आय के बारे में भी सुनले। आय के बारे में जिस दिन बजट पेश किया जाता है यह कहा जाता है कि अमुक विभागों के अन्दर अमुक अमुक प्रकार की कमी करने से इतनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। नमक का उत्पादन बढ़ा कर और नमक की इतनी बिक्री करके इतनी आमदनी बढ़ा लेंगे, अमुक प्रशासनिक खर्चे में इतनी कमी कर लेंगे लेकिन जिस समय एक्चुअल असेसमेंट होता है, रिवाईज्ड-फिगर्स आते हैं और उसके बाद एक्चुअल्स आते हैं उस समय सरकार की पोल खुलती है। अब वह पोल मैं आपको बताता हूँ। सरकार बजट के अन्दर जो टैक्स लगाती है उनसे आमदनी तो कम बताई जाती है लेकिन जो नोन टैक्स रेवेन्यू है उससे आमदनी अधिक बताई जाती है ताकि लोगों को पता चले कि सरकार कितनी एफिशियेन्ट है कि नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रही है और टैक्स रेवेन्यू कम कर रही है, लेकिन अब एक्चुअल फिगर्स आते हैं तो पता लगता है कि टैक्स रेवेन्यू जो बजट में दिखाई थी उससे कहीं अधिक आमदनी हुई है और जो नोन टैक्स रेवेन्यू बताई गई थी वह उससे कम हुई है। टैक्स रेवेन्यू में आप देखेंगे कि जो ३४ करोड़ की आमदनी बताई गई थी उसकी जगह ३६, ३६ की जगह ४१, ४२ की जगह ४४, ४७ की जगह ४८ की आमदनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार नोन टैक्स रेवेन्यू के जो फिगर्स आते हैं उनमें बताई गई आमदनी से कम आमदनी होती है। इस प्रकार यह सरकार इस सदन को धोखा देती है, यह विश्वास के साथ कह सकता हूं, लेकिन यह नहीं जानते कि दो तीन वर्ष पश्चात् जब एक्चुअल फिगर्स आएंगे सदन के सामने उस समय क्या हाल होगा। लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार को इन चीजों की चिन्ता नहीं है। जो मिल जाय उसको किसी तरह से हासिल कर लेने की चिन्ता सरकार को रही है। अब अध्यक्ष महोदय, इस सारे खर्चे को, इस सारी आय को और इस सारे बजट को देखने से, इन सब चीजों के परिणाम क्या निकलते हैं उसको भी देखें। यानी तीन पंचवर्षीय योजनाएं सरकार ने पूरी करदीं और चौथी पंचवर्षीय योजना का

(श्री भैरोंसिंह)

एक वर्ष पूरा कर लिया, इस पर अब तक हम ४३८ करोड़ ७३ लाख रुपया योजनाओं के नाम पर खर्च कर चुके हैं। सरकार इसको मानेगी नहीं लेकिन एक्चुअल्स से सिद्ध करने को तैयार हूं कि आपने जो फूड के टार्गेट रखे, पर कैपिटा इन्कम के टार्गेट रखे वे आपके सब टार्गेट फेल हो गए। इस स्टेट की इन्कम घटती जा रही है। इर्रिगेशन के आपके टार्गेट थे वे फेल हो गए हैं।

(१ म० प०)

बिजली के उत्पादन के जो टार्गेट्स थे, सड़क बनाने के जो टार्गेट्स थे, भूमि को सिंचित करने के जो टार्गेट्स थे, भूमि को फर्टिलाइजर्स से कवर करने के जो टार्गेट्स थे, भूमि के अन्दर बाकी के कन्सोलिडेशन और यूटिलाइजेशन्स के जो आंकड़े दिये थे उन सब टार्गेट्स के अन्दर आप पूर्णतया फेल हुए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल्योर हैं और राजस्थान सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। और यह उसी का परिणाम है कि प्राइसेज़ शूट अप करती जा रही हैं। आप प्राइसेज पर कन्ट्रोल नहीं कर पाते। यह आज उसी कारण है कि राजस्थान में ५७ लाख टन अनाज पैदा होता था वहां आज ३३ लाख टन होता है। कहां राजस्थान में पर कैपिटा इनकम ३५३ रुपये थी आज ३२३ पर पहुँच गई है। कहां हम भावों पर कन्ट्रोल करना चाहते थे और आज सारी चीजें उल्टी हो गईं। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से फेल हो गई। उस फेल्योर के बाद भी सरकार कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं। कुओं के टार्गेट्स हम पूरे नहीं कर पाये, ट्यूब वैल्स के टार्गेट्स हमने पूरे नहीं किये, हम किसी के अन्दर टार्गेट्स पूरे नहीं कर पाये और फिर भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, आज प्राइसेज़ के बारे में क्या जिक्र करूं। प्राइसेज़ किस तरह से बढ़ रही हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में प्राइसेज़ जिस सीमा तक पहुंचती जा रही हैं उनका उल्लेख किया है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि यह सरकार सुने या नहीं सुने, माने या न माने, आपने प्राइसेज़ पर कन्ट्रोल नहीं किया। जिसकी मुझे आशा है कि नहीं कर सकेंगे। आपको केवल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट भी केवल अपनी कुर्सियों का कन्ट्रोल करने की आदत पड़ गई है। आपको जनता के लिए राहत के कामों के करने की ओर इन सारे इविल्स पर कन्ट्रोल करने की आदत नहीं है। इसलिए मैं तो, यह कोई भड़काने की कार्यवाही नहीं है, चेतावनी के रूप में सरकार को कहता हूँ कि आज अनाज के जो भाव बढ़ रहे हैं और दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं उनको या तो कन्ट्रोल करें नहीं तो लोग आपके उपदेशों को ताक में रख कर गली-गली में सरकार से लड़ेंगे। पेट भरने के लिए सरकार के खिलाफ कोई हथियार उठाया जाय वह पाप नहीं होगा। आप ध्यान देकर चलें। आप यह सोचलें या समझ लें कि भाव सस्ते हो जायेंगे, इन्द्र देव ने वर्षा कर दी तो अनाज की पैदावार हो जायगी और नाज के भाव गिर जायेंगे। नाज के भाव मानसून पर निर्भर नहीं करते हैं। मानसून अच्छी भी होगी तो हम उससे यह सोचकर चलें कि नाज के भाव गिर जायेंगे तो यह राजस्थान में सम्भावना नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्राइसेज़ को कन्ट्रोल किया जाय। आप टैक्स लगाने की बात करते हैं, प्राइसेज़ डाउन

(श्री भैरोंसिंह)

करने की बात करते हैं लेकिन आपने नाज पर सैल्स टैक्स लगा रखा है । वह सैल्स टैक्स आप कम नहीं कर सकते है। जिन चीजों से प्राइसेज़ को डाउन लाने की आप कोशिश करेंगे वे आपके दिमाग में नहीं आतीं।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में सरकारी कर्मचारियों, किसानों और मजदूरों और व्यापारियों को क्या क्या दिया है, यह जरा देख लें। वित्त मंत्री जो ने बड़ी चालाकी से अपने भाषण में लिखा है कि जो कुछ अतिरिक्त खर्च हो रहा है वह बहुत सारा मंहगाई भत्ते के कारण है। सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उस वक्त के मंहगाई भत्ते के बराबर करने का कमिटमेंट किया है यह बैक आउट है । सरकार के कमिटमेंट्स हैं सरकार की घोषणा है जिनमें सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर मंहगाई-भत्ता मिलता रहेगा । आज सरकार उससे बैक आउट करके उसमें लिमिट करना चाहती है कि जिस समय हमने समझौता किया उस समय जो मंहगाई भत्ता मिलता था उसके बराबर करेंगे । अब गजेन्द्र गडकर कमीशन ने भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के अनुसार उन कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता बढ़ेगा तो उनको क्या दिया ? ये कमीशन नियुक्त करते हैं लेकिन मंहगाई भत्ते के बारे में जिक्र क्यों किया गया । मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ता रहे, लेकिन आप प्राइसेज़ पर कन्ट्रोल नहीं करपाते, और फैक्टर्स को कन्ट्रोल नहीं कर पाते जिनसे कि मंहगाई भत्ता बढ़ता है । उनको मजबूरी से मांग करनी पड़ती है । उन लोगों के लिए जिनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उन लोगों को राहत मिले इसलिए ज्यों-ज्यों मंहगाई बढ़े उनका भी मंहगाई भत्ता बढ़ना चाहिए । आपने कमीशन नियुक्त किया लेकिन उसका टर्म्स ऑफ रेफ़रेन्स कि वह कमीशन कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा उसका कोई उल्लेख नहीं किया ।

अब, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कहती है कि मितव्ययता कर रहे हैं तो किस बात की मितव्ययता ? एक लाख के बजट में प्रोविजन है कि १ करोड़ अमुक अमुक मदों पर कमी करने वाले हैं । अब बी० डी० ओज० को हटा दिया जायगा, अमुक इन्जीनियर्स को हटा दिया जायगा, अमुक सुप्रिन्टैंडिग इन्जीनियर की पोस्ट कम कर दी गई है । हमने बोर्डर कमिश्नर की पोस्ट कम कर दी है । अच्छी बात है । बी० डी० ओज० को क्यों हटा रहे हैं ? केवल इस लिए कि बी० डी० ओज० का कोई उपयोग नहीं है । पिछले वर्ष हमने कहा था कि बी० डी० ओज० को हटा दो तो आपने कहा था कि बी० डी० ओज० का उपयोग है। एक साल में ऐसा परिवर्तन आया कि बी० डी० ओज० निरर्थक हो गये । अब एक दिन यह राजस्थान सरकार यह कानून लाने वाली है कि जिस दिन राजस्थान सरकार यह कहेगी कि पंचायत समितियों का उपयोग नहीं । इनको खत्म किया जाय । खत्म करदें इस इविल को । इस इविल ने राजस्थान के अन्दर शान्ति को भंग किया है । आप यह न समझें कि पंचायती राज्य के कारण राजस्थान ने विकास किया है । इस पंचायती राज्य ने लोकल लीडर शिप जरूर डेवलप की

(श्री भैरोंसिंह)

है, लेकिन जिस तरह की लीडरशिप डेवलप हुई है उसको देखते हैं तो इस बात का पता लगता है कि उस प्रकार की लीडरशिप ने देश का भला नहीं किया है ।

इस सदन के कई माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि यहां सैक्रेटेरीयेट में २५ लाख के करीब स्पेशल पे दी जाती है राजस्थान में स्पेशल पे को समाप्त कर दें । वह राजस्थान सरकार करने को तैयार नहीं है । छटनी हो रही है । उस छटनी से पहले मैं इस सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि ५५ वर्ष से ऊपर की उम्र वालों को नौकर क्यों रख रखा है । बजट बनाते कौन हैं ? वित्त मंत्रीजी एक चपरासी की हत्या कर सकते हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी की तलवार एल० डी० सी० के गले पर चलती है । मुख्य मंत्री में दम नहीं है कि वे ५५ वर्ष से ऊपर की उम्र वालों को जिनमें राजस्थान के मुख्य सचिव को मिला कर ४०० अधिकारी हैं राजस्थान में उनको नहीं हटा सकते क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा जैसे कल वे मर जायेंगे तो राजस्थान में बंटाढार हो जायगा । आप कहते हैं कि बी०डी०ओज़० को कम कर रहे हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि आप उनको दूसरी जगह लगायेंगे । जिन परमैनेन्ट सर्विसेज में से वे हैं उनमें नियुक्त कर देंगे । उनको दूसरी जगह पर नियुक्त करना पड़ेगा । इसके कारण बचत क्या होगी ? पिछले वर्ष की सरकार की घोषणाओं का मैंने एक चार्ट बनाया है उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे का । उसको आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, तो आपको सुनकर खुशी होगी कि उन्होंने घोषणाएं तो लम्बी-चौड़ी कीं लेकिन केवल ७ प्रतिशत का इम्प्लीमेन्टेशन हुआ है । और इसी प्रकार से आज भी जो घोषणाएं की जा रही हैं वे ७ पर्सेन्ट से ज्यादा इम्प्लीमेंट होने वाली नहीं हैं । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति है उस वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा डर लगता है कि कुछ दिनों में कहीं राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति फिज़ूल आउट न हो जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में ३ पैराग्राफ्स शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर लिखे हैं । तीन पैराग्राफ्स से शायद सदन के माननीय सदस्य यह समझें कि वित्त मंत्रीजी बड़े दयालु हैं । वित्त मंत्रीजी ने दया करके ३ पैराग्राफ्स परिगणित जाति के सम्बन्ध में रखे हैं । इन तीन पैराग्राफ्स का जोड़ अगर लगायें तो ९ लाख होगी । अब आप यह समझ कर चल रहे हो कि सदन में बैठे हुए शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के प्रतिनिधि कि वे इतने भोले और भले हैं कि इन तीन पैराग्राफ्स से खुश किये जा सकते हैं । ९ लाख की गिनती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आज से लगभग ६ वर्ष पहले राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला था और मैं खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बन्धुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ९ लाख के पीछे कितने बड़े जहर की गोली गिटाई जा रही है । उस गोली के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि १९६२ में भगवतसिंहजी मेहता के नाम से एक हुक्म निकला था और राजस्थान में जितनी भी

(श्री भैरोंसिंह)

स्टेट्यूटरी कारपोरेशन है राजस्थान में जितने भी पब्लिक एन्टरप्राईजेज़ हैं, राजस्थान में जितनी भी ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनमें मेजर फाइनेन्शियल एलोकेशन राजस्थान सरकार का होता है, उन सब इन्स्टीट्यूशन्स में जैसा कि साढ़े बारह पर्सेन्ट रिजर्वेशन ऑफ सर्विसेज़ में है उसी प्रकार का रिजर्वेशन इन संस्थाओं में होना चाहिये। सन ६२ से हुक्म चल रहा है और ६२ के हुक्म की आज तक तामील नहीं की गई। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जरा इस सरकार पर दबाव डालो कि इन तीन पैराग्राफ का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है और इस प्रकार का आदेश निकालने की आवश्यकता है कि इस प्रकार नियुक्ति की जाय।

अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही अन्याय नहीं है, सोशियल वैलफेयर के नाम से १२ हजार का खर्चा हाउसिंग स्कीम के नाम से हुआ। हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत २,३७० मकान बने वह सारे के सारे मकान अधूरे पड़े हैं। अधूरे मकानों के लिए तकाजे हो रहे हैं कि पूरा करो। और पूरा करने के लिए लोग जेवर गिरवी रख रहे हैं। लोग जेवर गिरवी रख रहे हैं। क्योंकि मकान पूरे नहीं हुये। आपने साढ़े सात सौ रुपए की तकाबी देकर मकान खड़े करवा दिए लेकिन वह मकान पूरे नहीं हो रहे हैं। अब पूरे नहीं हो रहे हैं तो लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। और उस दबाव से बचने के लिए हरिजन लोग अपने जेवर गिरवी रख रहे हैं। इस प्रकार आपका यह १२ हजार का खर्चा भी व्यर्थ गया।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, विमुक्त जाति सेवा के लिए हमारी सरकार ने एक संघ बनाया। १६५२ से लेकर १६६६ तक इस संघ के द्वारा सात लाख रुपये खर्च कर दिए गए ग्रान्ट-इन-एड के। लेकिन इस सात लाख के खर्चे के बाद भी संघ चला नहीं तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर ने संघ के हिसाब किताब की जांच की और जांच करने के बाद में रिपोर्ट दी कि इस संघ का हिसाब किताब नहीं मिलता, है। क्यों मिलेगा हिसाब किताब क्योंकि इस संघ के अध्यक्ष थे पिछले तीन वर्ष तक राजस्थान के खनिज मन्त्री श्री हरिदेव जोशी। तो इस संघ का हिसाब किताब मिलने का सवाल नहीं है। अब विमुक्त जाति सेवा संघ, जिसमें इतना रुपया चला गया और जिसका हिसाब किताब नहीं मिला, फिर भी हमारी सरकार यह कहकर चलना चाहती है कि हम हरिजनों का भला करके चलना चाहते हैं। मैं कहता हूं, आप उन लोगों का भला नहीं करना चाहते, बल्कि उन गरीबों का शोषण करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार खर्च किस तरह से कर रही है। राजस्थान केनाल से लिफ्ट इर्रिगेशन का सवाल पैदा हुआ। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बार बार इस प्रश्न को इस सदन में उठाते हैं, और इस सवाल को उठाने की वजह है कि बीकानेर में पानी नहीं है, और लूणकरणसर में पानी तो है लेकिन वहां पानी खारा है। उस खारे पानी की समस्या को हल करने के लिए सरकार राजस्थान केनाल से लिफ्ट इर्रिगेशन से पानी लाना चाहती है। लेकिन जब लिफ्ट इर्रिगेशन से लूणकरणसर और

(श्री भैरोंसिंह)

बीकानेर तक पानी लाने का सवाल पैदा हुआ तो हमारे भूतपूर्व कृषि मन्त्रीजी कहने लगे कि नागौर में भी लिफ्ट इर्रिगेशन से पानी लाना चाहिए। नागौर में लिफ्ट इर्रिगेशन से पानी आए, यह राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में शामिल नहीं था। यह किस समय इन्ट्रोड्यूज़ कर दिया गया, इसका भी पता नहीं चलता लेकिन उसकी सर्वे कराने के अन्दर लाखों रुपया खर्च कर दिया गया। चुनाव से पहले उसका उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से वह उद्घाटन तो डूब गया, लेकिन आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इस लिफ्ट इर्रिगेशन के बारे में कि नागौर में लिफ्ट इर्रिगेशन से यदि पानी लाया जाता है तो ६० लाख रुपए का हर साल सरकार को घाटा होगा। आप इतने घाटे की बात करके भी नागौर में पानी लाना चाहते हैं और उस पर यह कहना चाहते हैं कि यह सारा खर्चा राजस्थान केनाल पर डाल दिया जाय ताकि राजस्थान केनाल से पानी लेने वाले किसान उस बढ़े हुए खर्च को भी बर्दाश्त कर बढ़ी हुई रेट्स सरकार को चुकायें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल रीजन्स के आधार पर राजस्थान की सरकार जनता के साथ बड़े से बड़ा अन्याय करने से भी नहीं चूकती है, इसका यह एक उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री कहने लगे कि इर्रिगेशन चार्जेज हमने बढ़ाए हैं वह किस लिए बढाए हैं। किसानों पर जो टक्स लगाया है वह टैक्स क्यों लगाया है। आपने किसानों पर प्रोक्योरमेंट लेवी लगादी है, किसानों पर इर्रिगेशन चार्जेज बढ़ा दिए हैं। मेले के अन्दर बेचे जाने वाले जानवरों के अन्दर घोड़े, बैल, बछड़े आदि भी शामिल कर लिए हैं। इनके अलावा आपकी विशेष कृपा गधे पर क्यों? उसको भी आपने नहीं छोड़ा। उस पर टैक्स लगा दिया। मैं तो कहता हूं कि आपने गधे पर टैक्स लगाया तो अच्छा हुआ। वह और आप दोनों साथ २ चलेंगे। यह सब टैक्स लगाने के बाद भी किसान को आप क्या देंगे? सिर्फ यह कि प्रोक्योरमेंट लेवी के अन्दर आप बाजार के भाव से आधी कीमत पर लेंगे। आपने सिचाई पर टैक्स बढ़ा दिया, जानवरों पर टैक्स लगा दिया, किसानों के काम में आने वाली सीमेन्ट पर टैक्स लगा दिया। सरचार्ज को आपने आगे एक्सटेन्ड कर दिया। इसका मतलब यह है कि आज राजस्थान की सरकार के सामने यदि कोई अन्नदाता है तो वह किसान है। यह बात सही है कि किसान अन्नदाता है लेकिन किसान के पास में यदि पूंजी नहीं रहेगी तो वह अन्नदाता भी नहीं रहेगा। इसलिए किसान के पास सेविंग कराने की जरूरत है। लेकिन इन टैक्सों के बाद उसके पास सेविंग नहीं होने वाली है। आप किसान का कोई भला करने वाले नहीं हैं। आप जो इर्रिगेशन पर खर्च कर रहे हैं उसके लिए आप कहते हैं कि इसका भार वही उठाये जो सिचाई की सुविधा को भोगे। मुख्य मन्त्री जी को याद होगा और वह इस बात को जानते भी हैं क्योंकि उन्होंने इस सदन में कहा है कि यह खर्चा आइटम्स पर नहीं है, यह खर्चा तो सोसायटी पर है। जिस समय डी. सी. एम. का प्रश्न उठा और यह कहा गया कि सस्ती बिजली के कारण वह छः लाख रुपये माहवार का

(श्री भैरोंसिंह)

फायदा उठा रहा है और क्योंकि आपने उसके साथ में दस साल का एग्रीमेंट किया है इसलिए करीब पन्द्रह करोड़ का अतिरिक्त खर्चा डी० सी० एम० के नाम पर राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा आपने फर्टिलाइजर फैक्ट्री को पांच हजार रुपये में सस्ती जमीन दी। आपने जो कोटा के उद्योगों को चुंगी कर से एक्जेम्प्ट कर दिया। इन सब खर्चों की चर्चा जब हम करते हैं तो मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि यह सारा खर्चा तो सोसायटी पर है, कोई इन्डिविजूअल आइटम्स पर नहीं है। इसका राजस्थान को इनडाइरेक्ट बेनीफिट मिलता है। मैं आपको कहता हूँ कि क्या किसान से इनडाइरेक्ट बेनीफिट नहीं मिलता है? आपने उल्टे किसानों पर इरिगेशन चार्जेज बढ़ा दिये। आज दुनियां तो कहती है कि इरिगेशन चार्जेज कम करो लेकिन हमारी राजस्थान की हुकूमत कहती है कि इरिगेशन चार्जेज बढ़ाओ। और इरिगेशन चार्जेज बढ़ा कर आप किसान से अनाज ज्यादा लेना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि किसान अनाज ज्यादा नहीं बोयेंगे। अब तो कुछ लोग कह भी रहे हैं कि हम सीरिअल्स नहीं बोयेंगे। बोयेंगे तो दुनियां भर के खर्च में हम पड़ेंगे।

इसके अलावा आपने गैस टर्बाइन खरीद कर एक सफेद हाथी खड़ा कर दिया है एक करोड़ का, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? राजस्थान सरकार पर है? और वह गैस टर्बाइन आज बन्द पड़ा है, वह चालू नहीं है। इसका खर्चा भी हम पर पड़ेगा।

बिड़ला की जो चित्तौड़ में फर्म खड़ी हो रही है, उसके लिए बिड़ला के रिप्रेजेन्टेटिव मुख्य मन्त्री जी के पास आये और उनसे मिले। उन्होंने मुख्य मन्त्री जी से कहा कि हमें सस्ती बिजली दो। आज किसान को सस्ती बिजली देने के लिए राजस्थान सरकार नहीं झुकेगी लेकिन बिड़ला की फैक्ट्री को सस्ती बिजली देने के लिए भारत सरकार तो शाष्टांग प्रणाम करेगी ही, साथ ही राजस्थान सरकार भी उसके आगे माथा झुका देगी। तो वह खर्चा भी हम पर पड़ेगा।

ऐसी स्थिति में गैस टर्बाइन का खर्चा सरकार हमसे लेना चाहती है, डी० सी० एम० को सस्ती बिजली देने के कारण करोड़ों रुपयों का खर्चा भी हमसे लेना चाहती है। इसके अलावा सरकार ने जो मीडियम और माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट पर लाखों रुपया अनाप शनाप खर्च कर दिया है वह भी हमसे लेना चाहती है। यह सब जो खर्चा सरकार हमसे लेना चाहती है, उसकी सरकार को चिन्ता नहीं है। अगर उसको कुछ चिन्ता है तो वह यह कि किसानों से पैसा कैसे वसूल किया जाय। वह किसानों से टैक्स वसूल करना चाहती है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि यह कोई तरीका चलने वाला नहीं है।

अब सरकार यह कहे कि हमारे इन्कम के यह सोर्स हैं। उनके लिए भी मैं आपको निवेदन कर दूं कि हमारी गंगानगर शुगर फैक्ट्री है, धौलपुर हाइटेक है, राजस्थान स्टेट रोडवेज है, स्टेट होटल कोर्पोरेशन है, पलाना लिगनाइट है, सोडियम सल्फेट है। इनमें से गंगानगर शुगर फैक्ट्री में एक्साइज

(श्री भैरोंसिंह)

को मिलाकर हमें कुछ लाभ है। इसके अलावा धौलपुर हाईटेक में सरकार १३ लाख रुपये के नीचे आई है। राजस्थान होटल कार्पोरेशन के अन्दर सरकार को २ लाख के लगभग घाटा हुआ है। इसी प्रकार स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन में भी ५० लाख रुपये रेल्वे शेअर्स के फंसे हुए हैं, और ६५ हजार के डेप्रिसियेशन चार्जेज लगे हैं। तो इसमें भी करीब ५० लाख रुपये का घाटा हुआ है। तो यह करोड़ों रुपयों की पूंजी लगाने के बाद भी हमें घाटा क्यों हो रहा है। इसका यह कारण नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। इसका कारण खराब एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन फिर भी गंगानगर शुगर फैक्ट्री से, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी १७०० बोतल भर कर ले जाता है। उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद में पकड़ने वाले आदमी को तो सजा मिल गई लेकिन जो आदमी ले जा रहा था वह छूट गया। इसी तरह से धौलपुर हाइटेक फैक्ट्री के लिए मैंने बार बार कहा इसमें घाटा होगा, घाटा होगा। लेकिन हमारे वित्त मन्त्री जी कहते रहे कि जर्मन कोलोबरेशन से जर्मन एक्सपर्ट्स की राय से हम इसमें फायदा करेंगे। मैं कहता हूँ कि यदि इण्डिविजूअल रेस्पान्सिबिलिटी डाली जाय तो हमारे वित्त मन्त्री ने इस धौलपुर हाईटेक फैक्ट्री के नाम से १३ लाख रुपए दुरुपयोग में लिए हैं। अब यह घाटा कौन बर्दाश्त करेगा। कोई भी इस घाटे को बर्दाश्त करे, हम इस घाटे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब इसी तरह से गंगानगर शुगर फैक्ट्री में एक्साइज को मिलाकर कुछ फायदा हो रहा है। अभी पिछली साल जब एक्साइज मिनिस्टर्स की दिल्ली में बैठक हुई तो उसमें यह तय हुआ कि कितना मोलेसेज कहां से खरीदें, कितना रेक्टिफाइड स्प्रिट कहां से खरीदें। लेकिन हमारी सरकार ने तो न मोलेसेज़ मंगाया और न ही रेक्टिफाइड स्प्रिट मंगाई। और न मंगाने के कारण से राजस्थान में जो शराब की तंगी होगी उसके कारण राजस्थान के अगले साल के बजट में घाटा नजर आयेगा। लेकिन इस साल उस घाटे की चिन्ता इस सरकार को नहीं है, लेकिन चिन्ता यह है कि जो मालेसेज राजस्थान सरकार को मिलने वाले थे, उसमें से दस हजार मन तो फलां को दे दिये, जो उदयपुर के हैं और उसको डाइरेक्टर बना कर ले लिया। कम्पनी ला में यह साफ लिखा है कि जो ट्रेड के सीक्रेट हों, कम्पनी के सीक्रेट हों, वह एक ही प्रकार के ट्रेड को करने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम होने चाहिये। लेकिन फलां को, गंगानगर शुगर फैक्ट्री का, जहां शराब बनती है, डाइरेक्टर अपाइन्ट कर दिया है और दस हजार मन मोलेसेज का परमिट भी दे दिया है। केवल उससे राजस्थान सरकार ने यह शर्त करली है जो तीन रुपये प्रति गेलन में शराब बनती है हम उसको ६ रुपये प्रति गेलन के हिसाब से खरीदेंगे। उसमें जो घाटा होगा, वह भी हमारे ऊपर पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहां कहां पर घाटा खायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज कोई भी इन्स्टीट्यूशन ऐसी नहीं है जिससे इस सरकार ने घाटा नहीं खाया हो। धौलपुर हाई टेक में जो घाटा होने का कारण है वह कारण है एक व्यक्ति को वहां का मैनेजर बनाया। उस व्यक्ति के बारे में इस सदन के सदस्यों ने बार बार कहा कि यह व्यक्ति अयोग्य है, इन्कोम्पीटेन्ट है, इस आदमी को मैनेजर की जगह अपाइन्ट मत करो। लेकिन उसी व्यक्ति को अपाइन्ट किया और उसका नतीजा यह है कि उसमें

Page No.58

(श्री भैरोंसिंह)

घाटा हुआ। जब आपने टेक्निकल पर्सन्स की राय ली उसके बाद भी यह घाटे में कैसे पड़ गया ?

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यदि घाटा ही घाटा हुआ तो हम उसे कहां तक बर्दाश्त करेंगे और कहां तक आगे चलेंगे। मैं उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहता हूँ, जयपुर दूध वितरण योजना है, केवल गांव से दूध लें, मैं समझता हूँ कि मामूली से मामूली दूध वाला जो १५ मील से दूध की चरी ले कर आता है वह भी कहेगा कि हम कमाई कर रहे हैं। लेकिन जयपुर दूध वितरण योजना में ४ लाख २५ हजार का अनुमानित घाटा था वह ४ लाख और ८० हजार होगया। और में तो घाटा होता है मगर दूध बेचने पर भी घाटा और आज एक कैशियर पकड़ा गया उसमें एक लाख का घाटा। इसके अलावा दूध में भी शुद्ध दूध नहीं मिलता। दूध में भी पानी मिला रहता है। इसके लिए अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास केमिकल एक्सपर्ट्स की फोटू है जो इसका मेरे पास प्रमाण है।

हमारी सरकार ने ऊन का व्यापार किया। सरकार ने कहा कि हम गडरियों से ऊन लेंगे और मिडिल मेन प्रोफिट नहीं कमाएंगे। इसलिए आपने ट्रेडिंग बनाकर बेचा उसमें भी आपको घाटा हो रहा है और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह घाटा आपको किस लिए हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि आपने पिछले बार ६६-६७ में ६.६० लाख के घाटे का अनुमान किया था और वह आपके रिवाइज्ड एस्टीमेट में ४३.५५ लाख का हो गया। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि यदि ट्रेड एकाउन्ट्स में कन्ट्रोल नहीं किया गया तो अन्न के मामले में थोड़ा सा मुगालता देने की कोशिश की गई उसी तरह से ऊन में भी मुगालता देंगे और कहेंगे कि स्टॉक बैलेन्स में था। नेक्स्ट ईयर ३२ लाख का प्रोफिट बता दें तो वहां पर ४३ और ११ लाख रुपयों का घाटा रहता है। यह घाटा क्यों होता है। मैं इसके डिटेल्स में गया हूं। एडवान्स में रुपया देने के लिए चीजों के पैकिंग के लिए एक करोड़ घाटे में गए और ७५ लाख के अकाउन्ट्स अभी तक नहीं दिए गये हैं। इसके लिए होता क्या है कि चीफ मिनिस्टर उनसे पूछते हैं और वो उनसे पूछते हैं। आप बजट को देखें तो उसे देखने से आपको मालूम होगा कि उसमें कितना हिसाब लिखा है। आप डिपार्टमेंट के हिसाब की किताबें चैक करें ऐसे बिलों का जिनका अकाउन्ट सबमिट होना चाहिए नहीं हुआ। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह घाटा ही घाटा कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। अनाज में घाटा हो जावे, ऊन में घाटा हो जावे, नमक में घाटा हो जावे सभी में घाटा ही घाटा होता रहे और हम बर्दाश्त करते जावें।

इसके अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी मंत्री जी बैठे हैं। शराब की गारन्टी के रुपयों के बारे में मैं कहूंगा कि अबके चुनाव में मैंने देखा कि कोई भी ठेकेदार विरोधी दल के साथ नहीं है। सभी शराब के ठेकेदारों ने कांग्रेस की जय और महात्मा गांधी की जय बोली स्टेशन पर शराब मिले या नहीं मगर जहां कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था वहां पर लाल, पीली और हरी बोतलें प्राप्त थीं। शराब की दुकानों पर कांग्रेस का झंडा

Page No.59

(श्री भैरोंसिंह)

लगा हुआ था। जो भी कान्ट्रेक्टर शराब का था वह कांग्रेस की जय जय कार करता था। एक शराब की दुकान पर मैंने देखा महात्मा गांधी और नेहरू के चित्र थे। हमने महात्मा गांधी को भी शराब के ठेके में पहुंचा दिया। मैंने उससे कहा कि महात्मा गांधी का चित्र तो मुझे दे दो। मैं वह चित्र अपने साथ लाया हूं और जहां से लाया हूं वहां उस पर उससे लिखा कर लाया हूं। उन लोगों में ६८ लाख रुपये की गारन्टी की रकम बकाया है। वे लोग कहते थे कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट हो गई तो उनको यह ६८ लाख की छूट हो जावेगी और हम कहते हैं कि हम आवेंगे और यह ६८ लाख की आपको छूट नहीं होगी। आज आप कहते हैं कि इसकी कलेक्टर जांच करेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उनसे यह रकम क्यों नहीं वसूल करते हैं। अजमेर जिले में २२ लाख पिछले चार वर्षों की बकाया है उसको आप वसूल नहीं कर पाते और बाकी इन पिछले दो सालों की कितनी बकाया उन लोगों में होगी उसको आप वसूल नहीं कर पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि यहां तो हर चीज में घोटाला। कहीं सच्चावट हो तो समझ में आजावे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कई माननीय सदस्य जिस समय हमारे वित्त मन्त्री भाषण दे रहे थे और जिस समय उन्होंने ने यह घोषणा की कि राजा महाराजाओं को पानी बिजली बन्द कर दिया उस समय कांग्रेस की ओर से तालियां बजाई गई। उन्होंने कहा कि ३ लाख की कटौती की गई मैंने देखा कि माथुर साहब की आदत तो नहीं है राजा महाराजाओं का विरोध करने की इसलिये इसके सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये कि वास्तव में ३ लाख की कटौती कर दी गई है या नहीं। मैंने स्पष्टीकारक, स्मृति पत्र आय व्ययक अनुमान में देखा तो मुझे मालूम हुआ कि यह सब बुक एडजस्टमेंट है। जितना पानी आदि का खर्चा आता था उसके एवज में एक लाख रुपया नकद दे दिया और यहां पर कह दिया कि राजाओं का पानी बिजली बन्द। इतने भाषण पर तालिया बजाई और कांग्रेस के लोगों ने तालिया बजा दीं। आप ही अन्दाजा लगा लें कि माथुर साहब ने आपको क्या बना दिया। यह सब इसमें लिखा है। हमारी सरकार बजट में बचत किस तरह लगाती है कि इतनी बचत होगी उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं बजट घोषणा में बताया गया है कि किसी राजा महाराजा की मत्यु हो जाने से सम्भवतः इतने रुपयों की बचत होगी। हमारी सरकार तो ज्योतिष के आधार पर चलती है कि अमुक आदमी मर जावेगा और उसके मरने से उनको इतनी बचत हो जावेगी। और वह शुभ चिन्तक कितनी कि वह चाहती है कि कोई न कोई मर जाए और उनको बचत होगी और कोई मरेगा तो आपको घाटा कम होगा। मैं यह कहूंगा कि आज हमारी सरकार अपने बजट प्रावधानों को किस तरह से कल्पना के आधार पर बनाती है। वह इस बात की कल्पना करती है और इस प्रकार बजट में प्रावधान रख कर कितने रुपयों की बचत करेगी। वाह हमारी राजस्थान सरकार तेरी बुद्धि और बजट बनाने की योग्यता, इसको धन्यवाद देता हूं

Page No.60

(श्री भैरोंसिंह)

अब मैं थोड़ा सा खर्चे पर भी निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी को याद होगा कि पिछले वर्ष कोटा होस्पिटिल के बारे में जो खरीद हुई थी उसके बारे में प्रश्न उठाया गया था और उस समय चिकित्सा मंत्री ने कहा था कि यह बिल्कुल गलत है और बाद में उस प्रश्न को प्रेस किया गया और दबाया गया तो कहा कि देख लेंगे और जांच होने के बाद जुलाई-अगस्त, सन १९६५ में जो पर्चेजेज ८० हजार रुपयों के हुऐ उनकी सारी जांच हुई और उसमें पता लगा कि पर्चेजिंग कमेटी को उसमें बाई पास किया गया और ऐसे आइटमों को सलेक्ट किया जो किसी काम के नहीं थे और डिफेक्टिव थे। और डिफेक्टिव थे और ऐसी फर्म को उनके आर्डर दिये जिसने उनको कम कीमतों पर नहीं ज्यादा कीमतों में सप्लाई किए। एक टाइम सर्जिकल ऐसी फर्म है जो मंत्री तक को उसमें इन्वोल्व्ड करती है। वह एसी फर्म है जो भ्रष्टाचार का डिप्लोमा प्राप्त कर चुकी है.. ....

श्री दामोदर लाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री): आपके कहने का मतलब यह कि उसकी रिकमन्डेशन पर्चेजिंग कमेटी ने नहीं की।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि ऐसे पर्चेजेज हुए हैं जिन पर पर्चेजिंग कमेटी के सदस्य और उनके चेयरमैन का एन्डोर्समेंट नहीं है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं यह जानना चाहता था कि पर्चेजिंग कमेटी के चेयरमैन का एन्डोर्समेंट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : डा० ऋषि ने किए हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : डा० ऋषि तो चेअरमैन थे उस कमेटी के।

श्री भैरोंसिंह : आज के दिन कागजों को चैक कर लें। नहीं देखना चाहें तो मैं बता दूं कि इसकी एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई होगी, नहीं पहुँचे तो मुझे याद कर लेना। उस कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, सच हैं, श्री कृष्णकुमार गोयल ने जो बातें कही थीं वे सब सही निकली हैं। अगर आप गर्दन हिलाय तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं समझ गया, सर्जिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स की परचेज की बात थी, उसकी एन्क्वायरी की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट आपके पास आ गई, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं? पर एक्शन के बजाय प्रोमोशन और री एम्प्लायमेंट की चर्चाएं चल रही हैं। अगर प्रोमोशन और रीएम्प्लायमेंट की राजस्थान सरकार ने यही क्वालिफिकेशन्स बना ली हों कि इतने घोटाले करने के बाद में राजस्थान में प्रोमोशन दिया जायगा, रीएम्प्लायमेंट दिया जायगा इतने घोटाले करने के बाद राजस्थान में वह इसके लिये क्वालिफाइड माना जायगा, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसी पर्चेजेज की गई उस फर्म से, जो लोअर प्राइसेज की थीं उनके आइटम्स की कम खरीद हुई और जिनकी रेट्स ज्यादा थी, ऐसे आइटम्स का खरीद ज्यादा की गई। ऐसे आइटम्स की खरीद की गई जिनमें डिफेक्ट्स थे, यदि उन

(श्री भैरोंसिंह)

फिफेक्ट्स को परचेज कमेटी के नोटिस में लाया जाता तो परचेज कमेटी कभी उनकी परचेज की इजाजत नहीं देती। ६० परसेन्ट ऐसे आइटम्स थे १४० में से जो लोअर क्वालिटी के थे, डिफेक्टिव थे, उनकी खराद की गई। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जो एक्सरे मशीन्स खरीदी गई, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि जो क्वोटेशन्स मांगे गये थे वे स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार नहीं थे, फिर भी खरीद लिये गये। मन्त्री महोदय को याद होगा, एक फर्म के लिये दो बार आदेश दिये थे कि यह स्टेन्डर्ड फर्म है, इसे एप्रूव्ड लिस्ट में शामिल किया जाय, उसको एप्रूव्ड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, इतनी बढ़ा कर कीमतें दी कि उससे राज्य सरकार को बहुत बड़ा घाटा हुआ, जोधपुर मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार के आइटम्स की खरीद की गई।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि एक्सरे मशीन्स की बात बताई उसके लिये तो एन्क्वायरी मुराणा कर रहे हैं। टाइम सर्जिकल की बात आपने बताई, बाकी जो परचेजेज की गई, उनकी लिस्ट दे दें, मैं जांच करा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : सब दे दूंगा आप चिन्ता न करें। अभी ताजा बता रहा हूँ। अभी मेडीकल कॉलेज, अजमेर के लिये आपने एक्स रे मशीन्स खरीदीं।

(१.३२ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उन एक्सरे मशीन्स के खरीदने में आपने टेन्डर्स, पहले वाले में तो टेन्डर्स इन्वाइट किये पर अम्बाला और बम्बई में आपने अपने आदमियों को भेज दिया कि मशीन्स खरीद लाओ। वे लोग मशीन्स खरीद लाये, ७० हजार का पेमेन्ट भी कर दिया, तीन चार लाख का पेमेंट करना था, बाकी खरीद के लिये बोर्डर कमिश्नर, प्रिन्सिपल और डायरेक्टर की इस परचेज कमेटी से परचेजेज़ को एप्रूव कराना था, वह एप्रूव नहीं कराया, तीन चार लाख रुपया आपने ट्रेजरी से ड्रा कर लिया और अपने पास रख लिया और लोगों ने कहा कि स्पेसिफिकेशन्स के माफिक नहीं है तो कम्पनी वालों को कहा कि सामान वापिस ले जाओ, कम्पनी ने कहा कि तुम्हारे आदमी खरीद कर ले गये, हम सामान वापिस नहीं लेंगे। वह कम्पनी हरियाणा में जो रेट्स क्वोट करती है उससे राजस्थान में १३ रुपया ज्यादा क्वोट करती है, पिछले समय में राजस्थान में जो रेट्स क्वोट किये थे उससे २३ ज्यादा क्वोट करती है, यह मामला एडमिनिस्ट्रेटर के सामने गया ता उसने कहा कि यह परचेजेज़ नहीं की जायं, क्योंकि पूरे प्रोसीजर को फोलो नहीं किया गया है, रेट्स क्वोट नहीं की गई हैं, रेट्स क्वोट की जांय और पूरे प्रोसीजर को फोलो किया जायं पर मन्त्री-मण्डल बना था, इसलिये आर्डर हुआ कि खरीद लिया जाय। इस तरह उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा........

श्री दामोदर लाल व्यास : अजमेर के मेडीकल कालेज की परचेजेज़ की कब की बात है?

श्री भैरोंसिंह : इसी साल की है.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : गये साल की है।

श्री भैरोंसिंह : इसी चालू साल की है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मन्त्री महोदय कई बार राजाओं और महाराजाओं के खिलाफ बोलते हैं। मैं दो मामले सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा, इसलिये नहीं कि राजाओं महाराजाओं के खिलाफ बोलने की मैं अपनी आदत डाल रहा हूं बल्कि इसलिये कि कम से कम सदन के कांग्रेस सदस्यों को मालूम हो जाय कि एक तरफ तो राजाओं महाराजाओं के खिलाफ बोलते हैं वे दूसरी तरफ कैसी २ कार्यवाहियां करते हैं। सिरोही महाराजा का मशहूर मामला है, उनकी पर्सनल प्रोपर्टी में आबू में दो बंगले हैं इसके अलावा उनकी पर्सनल प्रोपर्टी में कोई नहीं है। आबू में सिरोही एन्क्लेव है, सिरोही एन्क्लेव में मांझा गांव आता है इसलिए इसे मांझा एन्क्लेव भी कहते हैं। उस एन्क्लेव को सिरोही महाराजा अपनी पर्सनल प्रोपर्टी में शामिल करवाने में लगे हुए हैं, पर्सनल प्रोपर्टी में शामिल करवाने में लगे हुए ही नहीं हैं राजस्थान सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इसे आपकी पर्सनल प्रोपर्टी में शामिल कर लिया जायगा। आश्वासन ही नहीं राजस्थान के भूतपूर्व राजस्व मन्त्री कुम्भाराम जी थे उस समय उस एन्क्लेव में रहने वाले किसानों ने दरख्वास्त दी कि इस इन्क्लेव पर वर्षों से हमारा कब्जा है, हमको हटाया जा रहा है, हमारा ही कब्जा इस पर रखा जाय। कुंभारामजी ने आदेश दिया कि उनको बेदखल नहीं किया जाय पर हमारे वित्त मन्त्री जो उस समय निर्माण मन्त्री थे, उन्होंने राजस्व मन्त्री की फाइल को मंगाया और उस पर लिख दिया कि राजस्व मन्त्री के आदेश के कारण जो स्थगन आदेश जारी हुए हैं, उस आदेश को मंसूख किया जाय। यह समझ में नहीं आया कि राजस्व मन्त्री कहते हैं कि बेदखली को स्थगित किया जाय और निर्माण मन्त्री कहते हैं कि स्थगित नहीं किया जाय। जब मंत्री महोदय इसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो उस समय मैं रखूंगा कि यह सारी कार्यवाही किस लिए हुई। मैंने कहा था कि महाराजा उदयपुर पोलिंग स्टेशन पर वोट देने गए और राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने उनका स्वागत किया। मैं उनके स्थान पर होता तो केवल उनका स्वागत ही नहीं करता उन्हें माला भी पहनाता और आवश्यकता पड़ती तो उनकी जय जयकार भी करता, जिसको वोट लेना हो, सब कुछ करना पड़ता है। पर इसके पीछे राज मालूम होगा। उनके पिताजी को ६४ हजार का भुगतान किया गया है, वह भुगतान इसलिए किया गया कि रेख चाकरी का मामला चल रहा है, डिटेल्स में तो मैं इस समय नहीं जा सकता, महाराजा के पिता प्रतापसिंह जी को ६४ हजार का भुगतान कर दिया कि महाराजा साहब पहले ही पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। राजाओं महाराजाओं की खिलाफत करने वाली हुकूमत उदयपुर के महाराजा की सेवा कर सकती है, सिरोही महाराजा के सामने घुटने टेक सकती है। तो जो, इनके खिलाफ होजायं वे प्रतिक्रियावादी, पूंजीवादी और जो राजा महाराजा इनकी हां में हां मिलाएं वे प्रगतिशील और न मालूम क्या क्या डिक्शनेरी इन्होंने बना रखी है। यह इस तरह की डिक्शनेरी राजस्थान की हुकूमत बनाकर हम सबका एक तरह से अपमान कर रही है।

एक मामला खास तौर से कांग्रेसी

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्यों के लिए यहां रखना चाहता हूं। आप यह सोचें कि लोगों के पैसों से जीत कर कौन आये हैं ? बिड़ला का नाम लेते हैं। मैं एक ताजा उदाहरण रखना चाहूंगा। शाहू जैन जो इन चुनावों में एक्टिव रहे हैं, उनसे कितना पैसा लिया यह तो डिटेल में नहीं बता कर मेरी जानकारी के अनुसार जो आपने उनको माइन्स दी हैं, वह काहे के लिये, पहले वे फलौदी से पत्थर ले जा कर सीमेन्ट बनाते थे, वहां पत्थर खत्म हो गया तो भैरूंपुरा गांव है वहां आपने उनको पत्थर की क्वेरीज दे दी। राजस्थान मिनरल रूल्स के माफिक जो बिल्डिंग स्टोन है उसको बिल्डिंग परपज़ के अलावा दूसरे परपज़ के लिये कोई काम में लेता है तो उस पर रोयल्टी ज्यादा है, पर इनसे बिल्डिंग स्टोन की रोयल्टी ली जा रही है। व जंगलों को बरबाद कर दिया और बरबाद करने की शर्त यह थी कि जितना जंगल का नुकसान होगा उतना मुआवजा देना पड़ेगा। वहां के डी० एफ० ओ० ने मुआवजे का अमाउन्ट तय किया पौने दो लाख और उसके ऊपर चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट्स ने भी पौने दो लाख ही रखे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि राज्य के मंत्री ने कर दिये दस हजार। राज्य के खजाने से पैसा जा रहा है इसकी चिंता नहीं लेकिन शाहू जैन के पास जितना पैसा होगा वह राजस्थान कांग्रेस के खजाने में रहेगा। शाहू जैन से पौने दो लाख के स्थान पर दस हजार रुपये ले लिए। बिल्डिंग स्टोन की रायल्टी जो कामर्सियल बेसिस पर यूज़ करने से अधिक होती है, वह उनको माफ करदें तो इस प्रकार की चीजें राजस्थान में हो रही हैं तो कौन समझ कर चले कि राजस्थान में सब चीजें ठीक प्रकार से चलती जायगी।

इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान का बजट जो कर्ज का बजट है, जो टैक्सेज़ का बजट है, जिस बजट के लिये इन हरिजनों के लिए वित्त मंत्री जी ने, माफ कीजियेगा शिड्यूल्ड कास्टस व शिड्यूल्ड ट्राइब्स् गांधीजी ने इनको हरिजन का नाम दिया इसलिये यह शब्द जल्दी निकलता है, तो वित्त मंत्री ने इनके लिये पैराग्राफ इस भाषण में शामिल किया—चांदी के जेवरों पर टैक्स लगाया। मुझे आज एक परिगणित जाति वाले ने कहा कि चांदी मंहगी होगई। मैंने उनसे कहा, कि तुम चाँदी क्या करोगे ? उसने कहा, जेवर बनायेंगे। तब पता लगा कि सरकार ने इस जातियों का भला करने के लिये यह पैराग्राफ शामिल किया है क्योंकि चांदी के जेवर शिड्यूल्ड कास्ट वाले पहनते हैं, उन पर टैक्स लगेगा तो नाराज हो जायेंगे। इसलिये उनका मुंह बंद करने के लिये तीन पैराग्राफ इसमें जोड़ दीं। (शासक दल से) जरा संभालो, ऊंचा आओ ऊंचे आकर सरकार से कहो कि सरकार इस प्रकार के टैक्सेज लगा रही है उससे बड़ी बरबादी होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मामले बहुत हैं लेकिन सदन का समय कम है। इसलिए मैं ज्यादा न कहकर इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार बजट की सैंक्टिटी खत्म हो गई। बजट के प्रति जो भावना होनी चाहिए वह खत्म हो गई। आय के जो साधन थे ब्लाक हो गए। हमारा खर्चा द्रुतगति से बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि यदि जल्दी से इसको कन्ट्रोल नहीं किया गया तो एक दिन राजस्थान में ऐसा

(श्री भैरोंसिंह)

भी आ सकता है कि आर्थिक ढांचा बिल्कुल कोलैप्स हो जाय। इसलिए इस सदन का मान रखने के लिए, राजस्थान की वित्तीय स्थिति कोलैप्स न हो, इसको रोकने लिए, सरकार को विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जसराज (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत हुआ है और इस लेखे पर पिछले तीन चार दिनों से चर्चा चल रही है। इस चर्चा में विस्तृत रूप से बताया गया है कि किस प्रकार इस राज्य सरकार ने जो यह बजट पेश किया है, वह बजट उनकी नीतियों का द्योतक नहीं है बल्कि उनकी नीतियों के विपरीत है। मैं भी अपने कुछ विचार इस बजट पर पेश करना चाहूँगा। बजट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आय का और दूसरा व्यय का। आय के जो स्रोत हैं। उन पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। मैं केवल अर्थशास्त्री के नाते अपने इस बजट का विवेचन करना चाहूंगा। इस बजट में अर्थशास्त्र के जो सिद्धान्त हैं, जो इस प्रकार के टैक्सेशन के सिद्धान्त होते हैं, नियम होते हैं, सारे के सारे नियमों का इसमें हनन किया गया है। एक सिद्धान्त होता है न्यायोचित और दूसरा है योग्यता दोनों नियमों का इस टैक्सेशन पालिसी से बिल्कुल हनन किया गया है।

जहां तक योग्यता के सिद्धान्त का प्रश्न है, उसका भी इस बजट में हनन किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि प्रति व्यक्ति आय। जिस व्यक्ति की जितनी आय हो उसके अनुसार ही उससे टैक्स लिया जाय। अगर आदमी गरीब है, तो उससे कम पैसा लिया जाय और अधिक पैसे वाले से अधिक टैक्स लिया जाय। इस प्रकार का यह योग्यता का नियम और सिद्धांत होता है। परन्तु सरकार ने इस सिद्धांत की भी अवहेलना की है। राज्य सरकार के इकानामिक और औद्योगिक सर्वे ने एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े पेश किए गए थे कि आज राजस्थान में जो टैक्सेशन है, वह बहुत ज्यादा है। उस में कहा गया है कि:

'Of all the States in India per capita land Revenue burden is perhaps the highest in Rajasthan.'

इस प्रकार जहां जिसकी आमदनी थी, उसको ध्यान में न रखते हुए, हमने ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया। करीब ८० प्रतिशत टैक्स लैंड रेवेन्यू एवं वाणिज्य कर तथा एक्साइज टैक्स द्वारा ही हमने वसूल करने का प्रयास किया है।

इस प्रकार ८० प्रतिशत लोगों की जितनी कैपेसिटी थी, वह समाप्त हो गई। फिर हमने नए टैक्सेज लगाए। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखें तो पुरानी इकोनोमिक्स और इंडस्ट्रियल सर्वे रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं जो दो साल पहले के आंकड़े हैं, वह आंकड़े और आज जो सरकार ने पेश किए हैं, उनमें बहुत कुछ फर्क है। इन आंकड़ों के आधार पर एक व्यक्ति की इन्कम साढे चार आने या ५ आने एक आदमी की प्रतिदिन आय है और आज आंकड़ों में १० आने प्रति व्यक्ति आय है। अगर मान लें कि आज के आंकड़े सही हैं तो १० आना एक व्यक्ति की आय है। इस

(श्री जसराज)

दस आने में जिस आदमी को दो समय का भोजन भी नहीं मिल सकता है, उस पर इस प्रकार का टैक्स लिया जावे यह कहां तक न्यायोचित है ?

इकोनोमिक्स और इण्डस्ट्रियल सर्वे की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अजमेर के अंदर १२:७६) रु० प्रति व्यक्ति आय थी और ज्यादा से ज्यादा झुंझुनू में १७:२१ रु० प्रति व्यक्ति आय बैठती है और हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें इन्कम बतलाई है प्रति व्यक्ति २३९) । पिछले वर्षों की सारी रिपोर्टें स्पष्ट जाहिर करती हैं, कि अकाल पड़ा है, भुखमरी पड़ी है । उसके बाद आपके आंकड़े कहते हैं कि हमारी इन्कम बढ़ गई है । एक तरफ आपका विभाग यह कहे और दूसरी तरफ आपकी रिपोर्ट यह कहे, यह कहां तक उचित है ? १९६३-६४ में जो यह रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट में आपके टैक्सों का जो राजस्थान में भार है, वे दे दिए गए हैं । उस रिपोर्ट से जाहिर हो गया था कि टैक्सेशन की योग्यता पूरी हो चुकी है, राज्य सरकार केवल इन टैक्सों को मेन्टेन रखे । उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब तो केवल जहां लोगों की इन्कम बढ़ेगी, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी । इसलिए स्वतः ही टैक्सेज की आय में वृद्धि हो जायगी ।

उसके बाद न्याय का सिद्धान्त आता है । उसका भी हनन हुआ है । उसमें जैसा मैं अर्ज कर रहा था गरीब से कम टैक्स लिया जाय और अमीर से ज्यादा । गरीब पर जो टैक्स लगा है वह सारे का सारा पिछले दिनों की चर्चा में आया है । उसमें बताया गया कि किसान पर सिंचाई का २५ प्रतिशत टैक्स लगाया है । किसान पर हम टैक्स लगाते हैं जो किसान धर्ती जोतता है, आंधी, बरसात, सर्दी और गर्मी से लड़ता है, धर्ती के सीने को चीरता है । एक तरफ कहते हैं कि ५ या तीन एकड़ को रेवेन्यू फ्री कर देंगे, लैंड रेवेन्यू नहीं लेंगे । दूसरी तरफ आपने ये टैक्सेज किसान पर लगाए, यह कहां तक न्यायोचित है ? हम कहते हैं कि किसान की सरकार है, किसान के लिये भला करने वाली है और दूसरा तरफ यह सरकार उन पर टैक्स लगाये यह कहां तक न्यायोचित है ? हम कहते हैं कि किसान को सब प्रकार की सहूलियत मोहय्या करो । लेकिन सहूलियत उनको देते नहीं । सहकारी समितियों का ही हाल ले लीजिये । समय पर खाद नहीं देतीं, बीज समय पर नहीं देतीं और जिस व्यक्ति को उचित समझते हैं जो हमारी खाना पूर्ति कर सकते हैं उनको पैसा दे देते हैं, फिर हम चाहें कि समाज का निर्माण हो और किसान का स्तर ऊंचा हो यह कैसे हो सकता है आप स्वयम् ही इसको सोचें ।

देशी शराब पर आपने अधिक टैक्स बढ़ाया और दूसरी तरफ बीयर, जिसको बड़े बड़े पैसे वाले पीते हैं, उस पर दो परसेन्ट ही बढ़ाया । शायद उस तरफ बैठने वाले व्यक्ति बीयर का उपयोग करते हों, बीयर का अधिक उपयोग हो इसलिये २ परसेन्ट ही बढ़ाया और हरी, लाल रंग की शराब पीते हैं उस पर अधिक लगाया । इस तरह से गरीब पर आपने अधिक कर भार बढ़ाया और अमीर पर कम । यह कहां तक न्यायोचित है ? क्या यह सिद्धान्तों का हनन नहीं है ?

(श्री जसराज)

आपने मेलों पर टैक्स लगाया। गरीब जो साल भर तक कड़ी मेहनत करता है और कुछ एन्टरटेन करने के लिये वह मेलों में जाता है। आय का स्रोत भी मेला होता है उसके लिये। मवेशी का आदान प्रदान होता है। नयी खरीदता है और पुरानी बेचता है। क्या यहां पर आपके सिद्धान्तों का हनन नहीं होता है? सरकार इस पर पुनः सोचे। गरीब पर टैक्स लगाने से आप गरीब की सरकार होने का दावा कैसे कर सकते हैं?

मैं यह शार्ट में इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि मुझे बहुत शोर्ट टाइम ही बोलने के लिये मिला है। रिपीटिशन भी मैं उन बातों का नहीं करना चाहता जो अन्य माननीय सदस्यों ने कह दी हैं।

ट्यूब टायर और मोटर मशीनरी आदि पर आपने टैक्स लगाया। पूंजीपति इतने चुस्त हैं कि वे टैक्स का स्वयम् पर भार न पटक कर कन्ज्यूमर पर पटकेंगे और किराया बढ़ावेंगे। ५ परसेन्ट टैक्स आप बढ़ाते हैं तो दस परसेन्ट कीमतें बढ़ जावेंगी। एक तरफ तो हम सोचते हैं कि कीमतों को बढ़ने से रोकेंगे। आप समाजवाद की व्याख्या करते हैं कि गरीब भी अच्छी तरह रह सकें और दूसरी तरफ हम व्यापार करते हैं। इन्दिराजी ने कहा कि हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, सुखाड़िया जी ने कहा कि हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। आप आंकड़े उठा कर देखिये। इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्य इसको अच्छी तरह से जानते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं। ट्रान्सपोर्ट आपकी स्वयम् की इन्डस्ट्री है, रोडवेज़ में आपने २० परसेन्ट की दरें बढ़ायी हैं। क्या यह उचित थीं? आप स्वयम् व्यापार करें। एक तरफ कहते हैं कि कीमतें नहीं बढ़ने देंगे और दूसरी तरफ आप स्वयम् इतनी कीमतें बढ़ाते हैं। क्या इस प्रकार की सारी आपकी टैक्सेशन पॉलिसी उचित है?

इतना ही कह कर मैं एक्स्पेन्डीचर साइड में आता हूं। आपका खर्चा कहां तक न्यायोचित है यह मैं आपको अर्ज करूंगा और तीन उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। आपने बी. डी. ओ. की पोस्टें समाप्त कीं। बहुत धन्यवाद। यह तो हमारी पोलिसी थी। पांच साल से हम चिल्लाते आये थे कि यह फिजूल खर्चा है इसको बन्द करो। पंचायतों का जो आज खर्चा है वह भी बेकार है और इससे जो जनता पर आप टैक्सों का भार पटक रहे हैं इसलिये इसको भी खत्म करो। पांच साल बाद भी आप माने। लेकिन आज तक जिस प्रकार से जनता का फालतू रूप से जो रुपया आपने बरबाद किया है उसके लिये कौन जिम्मेदार है यह सरकारी बैंच प्रोसीक्यूट करने लायक है। इस प्रकार क्यों फिजूल खर्च किया गया? मैं यह सरकार पर चार्ज लगाता हूं। आपने यह कहा कि इतने परसेन्ट कमी करेंगे। आपने गरीबों की पोस्टों को तोड़ा। २३२ प्रोग्रेस असिस्टेन्ट्स की पोस्ट्स को तोड़ा। मैं निवेदन करूं कि २३२ प्रोग्रेस असिस्टेन्ट, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट का यह छोटे से छोटा केडर है उसको आपने तोड़ा है। २६ डिस्ट्रिक्ट में ५० स्टेटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं। उनका कार्यभार आपको कम नहीं लगा? जो प्रोग्रेस असिस्टेन्ट्स आंकड़े कलेक्ट करते थे, और डिस्ट्रिक्ट को भेजते थे इकोनोमिक सर्वे करते थे, रूरल एम्प्लोयमेन्ट का सर्वे करते थे, उनकी पोस्ट्स को तोड़ दिया और डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिशियन्स को रखने की क्यों आवश्यकता पड़ गयी? इस डिपार्टमेंन्ट में

(श्री जसराज)
अपने केवल रिश्तेदारों को लगा रखा है । जिनसे उनको आर्थिक फायदा या वोट का फायदा हो वही सोचने की कोशिश की । मैं अर्ज करूं कि मि० सेहगल जो डाइरेक्टर इवेल्युएशन हैं उनको यहां पर किस प्रकार रखने की कोशिश की । कट मोशन मैंने इसके लिये दे रखा है । उसके लिये मैं बाद में कहूंगा । इसी प्रकार सावित्री गुप्ता हैं । श्री आर. एन. शर्मा चाहे फोरेन ट्रेनिंग लेकर आए उनको रखते नहीं । केवल मात्र मुख्य मन्त्री के रिलेशन में होने के कारण सावित्री गुप्ता को रखा गया । मेजर गुप्ता मुख्य मन्त्री जी के रिश्तेदार हैं उनके कारण सावित्री गुप्ता को रखा गया । इसके साथ ही उनको १५०) अधिक पे में रखा । आर० एन० शर्मा फौरिन से ट्रेनिंग लेकर आए लेकिन उनको नहीं रखा गया । सावित्री गुप्ता को मेजर गुप्ता के रिलेशन में होने के कारण मुख्य मन्त्री ने रखा । आगे इस पर जब कट मोशन मेरा आवेगा तब बताऊंगा ।

एक माननीय सदस्य : मैं एक जानकारी दे दूं कि के० के० सेहगल इस वक्त डाइरेक्टर नहीं हैं ।

श्री जसराज : वे डाइरेक्टर इवेल्युएशन हैं । समाज कल्याण की बात बताऊं । सरकार ने किस प्रकार हमारे नाम पर यह दुकान चलायी है । हमारे नाम पर चन्द आदमियों को उनकी रोजी चलाने के लिए रखा गया है । यह हम एक सीमा तक बर्दाश्त कर सकते हैं । उस जाति का मैं भी एक प्रतिनिधि हूं । मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे नाम पर अपनी यह दुकान लगाना बन्द करें । खादी संस्थाएं चल रही हैं । किस प्रकार माणिकलाल वर्मा साहब जो उदयपुर में हैं, उनके रिश्तेदारों ने कितना पैसा लिया, चमड़े और अन्य चीजों के नाम से पैसा लिया, उनके दामाद हैं उन्होंने भीलवाड़ा में पैसा लिया ।

(२ म० प०)

इसके अलावा और भी कितने ही हैं । पुरुषोत्तमदास जी कुदाल हैं । जिनका हरिजनों से कोई सम्बन्ध नहीं । सात पीढ़ियों में उनकी हरिजनों के साथ कभी हमदर्दी नहीं रही । पर यह केवल पैसा कमाने के दष्टिकोण से हरिजनों के हितैषी बन्धु बन जाते हैं ।

मैं निवेदन कर दूं कांग्रेस ने २० साल राज्य किया पर इतने लम्बे अरसे में इनको विश्वास नहीं हो पाया कि हम हमारे विभाग को सम्हालने में सक्षम हैं । हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया । आज हम कहते हैं डाइरेक्टर समाज कल्याण हमारा होना चाहिये । इसके अलावा सारे का सारा प्रबन्ध हमारा हमारे हाथों में होना चाहिए ।

गांधीजी ने एक बार अम्बेडकर साहब से पूछा कि अम्बेडकर साहब आप नाराज क्यों होते हैं । हम तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं । हमने आज तक आप के लिए यह किया वह किया । इतना किया । इस पर अम्बेडकर साहब ने इतना निवेदन किया कि आप हमें दया और भीख देते हैं । इसके अलावा जितना पैसा आप हमारे नाम पर खर्च करते हैं उसका आधे 'से' ज्यादा बरबाद कर देते हैं । लोगों को आप यह पैसा उनकी अपनी दुकानें चलाने के लिए

(श्री जसराज)

देते हैं। जितना रुपया आपने खर्च किया उतना अगर हमें खर्च करने को देते तो जितना थोड़ा बहुत लाभ अब तक हुआ है उससे दस गुना ज्यादा फायदा करके हम रख देते।

हरिजनों के नाम से, आदिवासियों के नाम से, पिछड़े दलितवर्ग के नाम से कांग्रेस ने अपकी दुकानें लगा रखी हैं। इस दुकानदारी के अलावा हमारे साथ दिली कोई उनकी हमदर्दी नहीं है। हम आपकी दया और भीख नहीं मांगते, हम स्वाभिमान चाहते हैं। स्वाभिमान से खड़े होना और जीना चाहते हैं। आप इसके लिए उचित कार्य करिए।

आपका एक हरिजन वेलफेयर बोर्ड भी है। पर आज इतने दिन हो गये पर उस बोर्ड का गठन आपने नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि जब तक हम सोते हैं तब तक इस दुकानदारी को चलाते रहें यह सब इसलिए कि आपकी हमारे प्रति वफादारी नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके अलावा निवेदन करूँ, और भी निवेदन करना चाहता था पर समयाभाव के कारण मैं आगे कट मोशन पर निवेदन करूँगा।

इसके साथ ही साथ अर्ज करूँ कि ऑडिट रिपोर्ट सन् १९६४-६५ की पेश हुई है। इसमें स्पष्ट जाहिर किया है कि कितने रुपये बकाया हैं आपके भिन्न २ संस्थाओं में। आप पैसा देते हैं, पर उनकी रसीदें प्राप्त नहीं होतीं, यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होते। शिक्षण संस्थाएं हैं, अन्य संस्थायें हैं, पैसा उनके लिए दिया पर उसका उपयोग प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः निवेदन करता हूं कि आपका यह आय-व्यय का लेखा गलत है। गलत सिद्धान्तों पर आधारित है। आपके ये टैक्सेशन के नियम, कानून कायदे इन सब का भी इसमें पूर्णतया हनन हुआ है। खर्चा कर रहे हैं पर नियमानुसार नहीं है। इसलिए ऐसे कामों की कटौती कीजिएगा, जहां जरूरी है एवं नॉन रेवेन्यू आय में वृद्धि की जिसमें असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। रेवेन्यू में तीन से पांच बीघा तक की छूट देने की घोषणा कर चुकने के बाद इनकी क्या जरूरत रहती है? कलेक्टर सब कर सकता है। एस० डी० ओ० की भी आवश्यकता नहीं। यह कटौती करियेगा।

इसके अलावा शिक्षा के लिये कुछ नहीं कहा। आज बीस साल हो गये बहुत बड़े दुख की बात है शिक्षा के तरीकों में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सके। आज भी वही एम. ए. बी. ए. पढ़कर लड़के लड़कियां निकलती हैं जिनको आप पूरी तरह रोजगार नहीं दे सकते। आप शिक्षा की इस पद्धति में परिवर्तन करियेगा और उनको इस देश की आवश्यकताओं के अनुकूल ढालियेगा ताकि तथाकथित शिक्षितों की बेकारी कम हो सके, दूर हो सके। नहीं तो एक समय ऐसा आ जावेगा कि देश बिल्कुल तबाह हो जावेगा। इस तबाही से बचाइयेगा। गरीबों को भुखमरी से बचाइयेगा।

यह आपकी टैक्सेशन की नीति और रेवेन्यू के तरीके भी गलत हैं। यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

Page No.69

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री विट्ठल प्रसाद ।

श्री विट्ठलप्रसाद (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्तमन्त्री महोदय का भाषण आद्योपान्त पढ़ा और सुना और उसका मनन करने के बाद ऐसा लगा कि उस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वथा उपेक्षा की गई है।

एक तरफ यह कांग्रेस की सरकार के लोग कहते हैं कि हम गांधीवादी विचार-धारा के आदमी हैं, नेहरू के सामाजवाद में विश्वास करते हैं, पर दूसरी ओर इनके कारनामे इनसे उलटे हैं ।

गांधीजी कहते थे कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है, वहां से गरीबी, अज्ञान और अन्धकार मिटाना हैं। पर सरकार के इस बजट में जो गांवों की उपेक्षा की गई है वह विचारणीय है ।

गांधीजी का हत्यारा नाथूराम गोड़से था पर उसने गांधीजी के नश्वर शरीर की हत्या की थी, लेकिन ये गांधी के भक्त और उपासक उनकी आत्मा की, उनके सिद्धान्तों की कदम कदम पर हत्या कर रहे हैं ।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूं कि एक ओर जहां लाखों करोड़ों रुपये यूनिवर्सिटियों और कालेजों के नाम पर शहरों में खर्च कर रहे हैं वहां ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियों को आपने स्कूलें सौंप कर आर्थिक सहायता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली है ।

एक एक पंचायत समिति के बजट में दो ढाई हजार से ज्यादा रकम नहीं होती और उस बजट में अध्यापकों का वेतन भी पूरा नहीं पड़ता । तो एक तरफ पंचायत समितियों की लगभग सौ स्कूलों के लिये दो ढाई हजार खर्च करते हैं दूसरी ओर शहरों में कालेजों, यूनिवर्सिटी आदि पर लाखों करोड़ों खर्च करते हैं । फिर गांवों में इतनी सी रकम से दरी और पट्टियां बैठने को नहीं मिल पातीं, लाइट नहीं मिल पाती और बच्चों को बुलाने के लिये घण्टी का खर्चा नहीं पूरा हो सकता । इसलिये जरूरी है कि पंचायत समितियों को आप अधिक से अधिक पैसा दें ।

विकास अधिकारी वगैरह की पोस्टें आपने समाप्त कीं अब भी बहुत से अना-वश्यक विभाग हैं जिनको कम किया जा सकता है । जैसे हर जिले में आपके जिला सांख्यिकी अधिकारी हैं । यह निरर्थक है । इसी तरह पी० आर० ओ० हैं । उनको जीपें दे रक्खी हैं । वे जीपों को केवल अपने बीबी बच्चों को घुमाने में उपयोग करते हैं । इनको रोकें ।

एक ओर देहातों को शिक्षा के लिये देने को आपके पास पैसा नहीं, दूसरी ओर अपने रिटायर लोगों को ओब्लाईज करने के लिये नई नई नियुक्तियों पर उनको लगाते हैं । एक घटना मेरे सामने आई है । उदयपुर में जो राजस्थान के डिप्टी डाइ-रेक्टर थे शम्भू दादा वे रिटायर हो गये । एक हजार महीना पेन्शन मिलती है और उनको एडल्ट एजूकेशन का डाइरेक्टर बना दिया । यह कितना बड़ा भ्रष्टाचार है जनता के साथ में । क्या कोई नया आदमी इसके लिये नहीं मिल रहा था? पर आप तो पोलिटिकली किसी को ओब्लाइज करना चाहते हैं ।

(श्री विट्ठलप्रसाद)

अंग्रेज जिस समय देश से गये और राजस्थान में देशी रियासतों का विलय हुआ तो इस सरकार को करोड़ों की सम्पत्ति विरासत में मिली थी। पर केवल इन अपने शासन के बीस वर्षों में इस कांग्रेसी कुशासन ने वह करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट कर दी, यही नहीं, करोड़ों के टैक्स लगाकर उगाही गई जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई की रकम खराब कर दी और आज वित्त मन्त्रीजी बताते हैं कि हम पर ४३१ करोड़ की कर्जदारी है जिसको हमारी औलाद और उनकी औलाद भी ब्याज समेत नहीं चुका सकेगी। यह राजस्थान का नकशा पिछले बीस सालों के अपने शासन के बाद इस कांग्रेसी सरकार ने दिया है। एक ओर आप उनको नई नई पोस्टें देते जाते हैं और पंचायत समितियों की उपेक्षा करते जाते हैं।

मैं आपको एक नजीर दूं। डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, राजस्थान ने एक आर्डर जारी किया कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की मई में शिक्षा समाप्त हो जावेगी। प्रशिक्षण से मुक्त होने के समय के पश्चात् समस्त ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापक जो प्रशिक्षण ले रहे हैं ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् उपस्थित हो सकते हैं। सेवारत अध्यापक जो प्रशिक्षण ले रहे हैं..........

श्री उपाध्यक्ष : आप इस प्रकार से रिटन स्पीच नहीं पढ़ सकते उसमें से आप कुछ उद्धरण दे सकते हैं।

श्री विट्ठलप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो अध्यापक पंचायत समितियों में तीन-तीन या चार-चार साल से कार्य कर रहे हैं उनको ग्रीष्म अवकाश का वेतन नहीं दिया जायगा। जो पंचायत समिति में अध्यापक पिछले तीन साल से काम कर रहे हैं उनको पिछले तीन साल का ग्रीष्म अवकाश वेतन न दिया जाय। ग्रीष्म अवकाश में उनको नियुक्ति नहीं दी जायगी इस तरह से उनके हित पर कुठाराघात करने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं वे शिक्षा विभाग के संचालक महोदय के आफिस से निकले हुए आर्डर को निरस्त करवायें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, जरा हमारी तरफ भी नजर रखिये हमें भी समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा !

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है मेरे ख्याल से इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले दोनों ने ही उस पर उग्र व्यग्रता प्रगट की है। दोनों तरफ से इस ६७-६८ के बजट पर एक ही प्रकार का रुख रखा गया है। इस पर उग्र चिन्ता व्यक्त की गई है इसमें कोई सन्देह नहीं है। बजट भाषण जो दिया गया वह बहुत अच्छा सुन्दर और विरोधाभास से तर्कयुक्त था। इसमें दो राय नहीं कि इस क्रियान्वयन में जो वर्ग अन्नदाता किसान है, श्रमिक हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन पर ज्यादा कर का भार आ पड़ा है।

दूसरी तरफ समाजवाद का नाम लेने वाली सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा

Page No.71

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

पहुँचाया है। इससे इसको न आशावादी कह सकते हैं और न प्रगतिवादी कह सकते हैं बल्कि यह बजट इस तरह का है, जिसने हमारे सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे न कोई अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं और न इसमें हमारी योजनाओं द्वारा उत्पादन ही बढ़ सकता है। न कर्जे में कुछ दे सकते हैं। जहां रियासत में वार्षिक आमदनी बढ़ती है वहां कर्जे में ही ज्यादा आय के खर्च हो जाने से हम कोई योजना को सम्मिलित नहीं कर सकते। दूसरे देशों में बीस वर्ष में तो हर देश अपने आप में स्वावलम्बी हो गया है लेकिन यहां हमारा भारतवर्ष इन कांग्रेसी शासन के बीस साल में भी स्वावलम्बी नहीं हो पाया है। दुनियां भर का इतिहास देख लीजिये यह हमारा दुर्भाग्य है कि बीस वर्ष के बाद भी हम वैसे के वैसे ही रह गये हैं। ऐसा कहने वालों का हम यह कह कर पीछा छुड़ाते हैं कि हम क्या करें हमारे यहां तो निरन्तर तीन साल से अकाल पड़ता आ रहा है। मेरा इस बारे में निवेदन है कि जितनी भी योजनाएं आप बना रहे हैं आखिर वे किसके लिए बना रहे हैं? यदि प्रकृति साथ देती है तो फिर योजना बनाने से क्या मतलब? योजनाएं तो जब प्रकृति साथ नहीं देती है, तब भी उन योजनाओं के द्वारा हम भूखे न मरें तो वह योजना कहलाती है। तीन योजनाओं के बाद भी आज हमारी यह स्थिति है कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, आवास के लिये मकान नहीं। आज एक व्यक्ति के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है अन्न, पानी और आवास इन तीनों की समुचित व्यवस्था आप नहीं दे पा रहे हैं आप इन तीनों के विषय में बिल्कुल असहाय अनुभव कर रहे हैं। मैं यह मानकर चलता हूँ कि दरअसल में जो कुछ किया जाता है वह राजनैतिक दृष्टिकोण से किया जाता है। राजनैतिक दृष्टिकोण से ही हम अकाल सहायता के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। जब किसी देश के विकास के साथ राजनैतिक दृष्टिकोण घुस जाता है तो उस देश का उत्थान नहीं हो सकता तब जाकर भ्रष्टाचार, तब जाकर पक्षपात पनपता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर अपने भावों को व्यक्त करते हुए थोड़ी सी पंक्तियां जो मैंने कविता के रूप में लिखी हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ—

सुन्दर शैली तर्क युक्त,
भाषा परिपूर्ण बजट भाषण।
किन्तु राज्य में यही बनेगा,
जनता के शोषण का कारण।।
रोया दलित किसान श्रमिक तक,
मध्यम वर्ग असहाय खड़ा।
लूटा उसी वर्ग को तुमने,
पूंजी से जो सदा अड़ा।।
साम्यवाद क्या यही जगत में,
ऐसी ही समता लाओगे।
इसी भरोसे बना योजना।
हमको कब तक बहलाओगे?
बीस बरस तो निकल गये हैं,
बिना अन्न पानी और घर के।
कह देते हो ईश्वर रूठा,
जीओ छाती पत्थर धर के।।
किन्तु देश में ऐसे भी हैं,
जिन्हें हजम होता नहीं दाना।
बड़े प्रवासों में रहते हैं,
नल से नित पानी बरसाना।।

Page No.72

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

तुम उदार उन्हीं पर तो हो,
शासन का वे एक सहारा।
उन्हीं के बल चलते चलते,
केन्द्र तन्त्र भी उनसे हारा ।।
बजटों से होगा नहीं कुछ भी,
न ये समता ला पायेंगे।
बड़े कठिन जो कर्जा मिलता,
उसको यों ही खा जायेंगे ।।
लोक नीति अरु न्याय शब्द तो,
इनकी शिक्षा से है बाहर।
यह कारवां यों ही चलेगा,
जब तक बहुमत इनका अन्दर ।।
तीन योजना पूर्ण हुई फिर,
"भाग्य भरोसे" क्यों कहते हो ?
विधि विधान ही आश्रय था,
तो मार करों का क्यों लदते हो ?
कितना ही तुम खर्च करो औ,
कर भी खूब लगा डालो।
मूलभूत जब गलती है,
आशा समृद्धि तज डालो ।।
करते समता की बात,
किन्तु ये महा विषमता फैलाते।
मेवाड़ मरुस्थल मारवाड़ के,
नारे से गोदी भर लाते ।।
बालकृष्ण भी क्रीड़ा कर,
अब बृज में खूब विचरते हैं।
श्री माथुर मथुरा जाना है,
तो कई वर्ष निकलते हैं ।।
तो सारा बजट बदल डालो,
उन गांधी जी को याद करो।
समता समाज में लाने को,
तब तक तो कुछ काम करो।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब पण्डितजी ने कविता पढ़नी शुरू की तो मेरे विचार में निराशा में तो कवि को नहीं देखना चाहिए और कवि अगर निराशा में ही देखता है तो आने वाले जमाने में हम कैसे जी सकेंगे। मुझे भी कुछ लाइनें याद आगयीं

बीते जमाने के सौ सौ कड़वे मीठे अनुभव,
आने वाले जमाने के सौ सौ हीरे मोती के सपने...............

(अश्रव्य)

उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान की हालत को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रक्खा है और जो राजस्थान में लोक व्यवस्था का प्रदर्शन किया है उन्होंने बताया कि जो कुछ भी हालात है उनमें हम कैसे जी सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी भाई जो बोलते हैं और जो बातें कहते हैं अगर उसी समय हमें अवसर दिया जाये तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान की जो प्रगति हुई है और राजस्थान की जो आर्थिक प्रगति हुई है उस बाबत में आप २० साल के लम्बे अरसे को देखें तो मालूम होगा कि राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। हम यह मानने लगे हैं कि राजस्थान में सभी जगहों पर प्रगति हुई है और सभी दिशा में प्रगति हुई है। हमारे विरोधी पक्ष के भाई मानने लगे हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं हुआ है। यह इस प्रकार की जो निराशाजनक बातें हैं मेरा ख्याल है जब धरती सूख गयी है तो इनका मन भी सूख गया है। इनके मन इतने सूख गये हैं कि इनमें निराशा ही निराशा छाई हुई है। और इसके कारण यह नहीं हो जाये कि उनमें साहस, हिम्मत और जो दूसरे गुण हैं वह भी सब गुण नष्ट हो जायें। मैं

Page No.73

(श्री मूलचन्द डागा)

बतलाना चहता हूं कि हम ई सालों के बाद जब अकाल का प्रकोप है या प्रकृति का प्रकोप है, बारिश नहीं आती है, नदियों में पानी नहीं है, कुएं सूखे पड़े हैं, हमारी खेती की उपज कम हो गयी है, लगान नहीं मिलता है और उसके कारण सारे रोजगार ठप्प हो जाते हैं। उस हालत के अन्दर हिदुस्तान का और राजस्थान का एक भी आदमी भूख से नहीं मरा और उसके लिए सदन में प्रश्न हो। उपाध्यक्ष महोदय, एक हमारे यहां के बैठने वाले व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था कि उस बूढ़ी औरत की मृत्यु किस कारण हुई.........

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्ति ने नहीं माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था ऐसा कहिये आप।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न किया था कि किस प्रकार से एक औरत की मृत्यु हुई। मैं समझता हूं कि राजस्थान की असेम्बली का जो कीमती समय था वह इस लिए रखा गया कि हम जांच करें कि वास्तव में जीवन का मूल्य क्या है। इतना भयंकर दुष्काल होने के बाद जिस दुष्काल में लाखों रुपये खर्च किये गये और करोड़ों रुपये खर्च किये गये तो आपने मानवता के प्रश्न को सुला दिया कि वहां पर ज्यादा खर्च किया और वहां पर कम खर्च किया। प्रश्न यह नहीं है। मान लें कि फलां जिले में अकाल के कुछ गांव घोषित किए गए उसमें कहीं कहीं पर तो मजदूर ही नहीं आते हैं कहीं पर मजदूरों की संख्या कम होती है तो कहीं ज्यादा होती है उस प्रश्न को लेकर आपने एक बवन्डर पैदा किया। बाड़मेर की आबादी के साथ में प्रश्न को जोड़ा पाली जिले की आबादी के साथ में उसको जोड़ा प्रश्न यह नहीं था। सवाल यह था कि अकाल के समय में किसी इलाके में ज्यादा काम बढ़ा दिया और कितनी ज्यादा संख्या में लोग आते थे उनको राहत पहुंचाने के लिए अकाल के दिनों में धन खर्च किया गया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विरोधी दल के लोग इस बात का दोषारोपण करते हैं कि केवल उदयपुर में ही धनराशि खर्च की गयी, यह उचित नहीं है। सवाल यह पैदा हुआ कि अकाल के समय काम करने वालों की संख्या किस जगह ज्यादा थी। कई जगह देखा है कि मजदूर नहीं मिले हैं। अकाल के नियम बने हुए हैं उन नियमों के कारण ५-५ मील के क्षेत्र से लोग आये.......

एक माननीय सदस्य : मैं माननीय सदस्य से यह अर्ज करूंगा कि क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि जालौर में कितने मजदूर आते थे और कितने वापिस गये ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी आंकड़े शायद नहीं बता सकेंगे कि ......

एक माननीय सदस्य: आंकड़े मेरे पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप मंत्री महोदय से पूछें वह बतला सकेंगे। माननीय सदस्य के पास आंकड़े कहां से आये ?

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : यहां गलत बातें कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा: आप अकाल की बात कर रहे हैं और आपके चेहरे से हंसी छूट रही है। मालूम होता है जैसे वहां अकाल ही नहीं था। विरोधी दल करिश्मा बता सकता है। सवाल यह है कि हिन्दुस्तान में राजस्थान की सरकार ने अकाल के समय में इतनी धनराशि खर्च करके अकाल राहत के कार्यों को किया या नहीं? प्रश्न यह है। प्रश्न यह नहीं था कि कहां कम हुआ और कहां ज्यादा हुआ। सवाल यह था कि राजस्थान में कई सालों से अकाल पड़ने के बावजूद एक भी आदमी भूख से नहीं मरा—यह प्रश्न था।

श्री विजयसिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि अजमेर जिले में अकाल राहत कार्यों के लिए २१ लाख की मन्जूरी हुई इसमें से ११ लाख ८१ हजार रुपये सिर्फ अकेले नसीराबाद में खर्च हुए और बाकी सारा पैसा पूरे जिले में खर्च हुआ। यही है आपका वितरण?

श्री मूलचन्द डागा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। मैंने यह बताने की कोशिश की कि हमारा जो बजट है उसके अन्दर जो हमने धनराशि पिछले सालों में ११ करोड़ १३ करोड़ रुपये खर्च किये हैं, जो दुर्भिक्ष पड़ा उसके लिए यह पैसे खर्च किये हैं। आप राजनैतिक दृष्टिकोण से बातें करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): राजस्थान की जनता के खिलाफ षड़यंत्र कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा: सवाल यह था कि राजस्थान में जो धनराशि अकाल के समय में खर्च हुई हम कहना चाहते थे कि इस राशि का दुरुपयोग किस प्रकार से हुआ यह आप नहीं बता सके। आपने तो यह बताने की कोशिश की कि उदयपुर में ज्यादा खर्चा किया और दूसरी जगह कम किया। यह क्षेत्रीय भावना हमारे अन्दर पैदा करने की आपने कोशिश की। हम क्षेत्रीय भावनाओं के ऊपर हैं और आप न तो ऊपर हैं और न नीचे हैं......

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): बीच में हैं।

श्री मूलचन्द डागा: इसलिए मेरा यह कहना है कि आज के पहले जब हमारा राज्य नहीं था और ब्रिटिश की हुकूमत थी उस समय कलकत्ता में अकाल के कारण ऐसे भयंकर दुष्काल के समय ३० लाख आदमियों की मौतें हुईं और सड़कों पर हुईं। राजस्थान में कई वर्षों के अकाल के होने के बाद भी एक आदमी आज तक मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य कहते हैं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब है। आप अगर राजस्थान की आर्थिक स्थिति के आंकड़े देखें और जब विश्व बैंक के अध्यक्ष यहां पर भारत में आये थे तो उन्होंने भारत के सारे नक्शे को देखा था और जांच की थी तो उन्होंने बताया था कि निराशाजनक कोई वस्तु नहीं है। यह तो पिछले दो सालों से अकाल के पड़ने के कारण, प्रकृति के प्रकोप के कारण जो धनराशि हमें खर्च करनी पड़ी उसके कारण उद्योगों पर असर पड़ा, खेती पर असर पड़ा और बिजली

(श्री मूलचन्द डागा)

के ऊपर असर पड़ा तो सारा कारण जो प्रकृति का है इसका दोषारोपण राज्य सरकार के ऊपर डाला जाय और सोचा जाये कि सारा का सारा दोष राज्य का है मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। आज के जमाने में और पहले के जमाने में अन्तर यही है कि जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक प्रकोपों के कारण घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के कारण जो कुछ भी धन राशि खर्च करनी पड़ती है जो कि लोकतांत्रिक समाजवाद के लिये आवश्यक है, जब हम लोकतांत्रिक समाजवाद की मांग को स्वीकार कर देते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं हिन्दुस्तान को कांग्रेस की यही देन है और वह देन है लोकतांत्रिक समाजवाद। और इसी लोकतांत्रिक समाजवाद का परिणाम है कि आज इतना रुपया खर्च किया जाता है।

अभी आप लोगों ने बड़े अच्छे सुन्दर भाषण में कहा कि यहां का किसान करों के बोझ से दब रहा है। मैं समझ नहीं सका कि उन्होंने यह किस प्रकार से कहा। मैं समझता हूं कि करों के बोझ से किसान दब रहा है या आप की बातों का, आपकी आवाज का मेरे खयाल से किसानों के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज का किसान राजस्थान में जो कुछ पैदा कर रहा है, कर वृद्धि का मूल साधन यही है कि जो किसान आज पैदा करने के बाद खर्चा कर रहा है उस पैसे का किसी तरह से उपयोग किया जाय। जो क्रय शक्ति जनता में पैदा हो रही है उस क्रय शक्ति पर अगर अंकुश नहीं लगा सके तो जिस प्रकार का हिन्दुस्तान हम बनाना चाहते हैं वह नहीं बना सकेंगे। आप देखें कि अभी थोड़े दिनों पहले राजस्थान में कितनी शादियां हुई। मेरे ख्याल में हजारों शादियां हमारे यहां राजस्थान में हुईं और हमने देखा कि छोटे २ घरों की शादियों में और बड़े घरों की शादियों पर कितना खर्चा किया जाता है। इसका एक उत्तर यह भी है कि यह बतलाता है कि काश्तकार की क्रय शक्ति बढ़ी है। किसान की खर्च करने की ताकत बढ़ी है और वह खर्चा जो केवल उपयोगी वस्तुओं पर न किया जाता हो और दूसरी वस्तुओं पर किया जा रहा हो उस पैसे को राजस्थान सरकार टैक्स के रूप में लेकर फिर सिंचाई के साधनों को बढ़ा कर, भूमि का सुधार कर उत्पादन बढ़ाने के कामों में खर्च करना चाहती है। तो जो वक्ता महोदय ने कहा कि करों की यह प्रणाली बिलकुल सुरक्षित है। राज्य की सम्पत्ति बढ़ाने के दो ही रास्ते हैं, या तो कर्ज लिया जाय अथवा करों में वृद्धि की जाय। कर्जों से भी देश की सम्पत्ति बढ़ाई जाती है और उस सम्पत्ति से भी देश का विकास हो सकता है। लेकिन ऋण लेने के अन्दर हमें दो प्रकार के नुकसान हैं। एक तो ऋण की किश्तें चुकानी पड़ती हैं और दूसरा ब्याज चुकाना पड़ता है। करों की एक प्रणाली है और वह प्रणाली यह है कि जितनी भोग की चीजें हैं, विलासिता की चीजें हैं उन पर रोक लगाना और जिनमें कर देने की ताकत है उनसे कर वसूल करना।

आज राजस्थान सरकार जब राजा और महाराजाओं पर जो बिजली और पानी के रूप में तीन लाख रुपया खर्च किया जाता है उसको लेना चाहती है तो कहने लगे कि यह सरकार हमें धोखे में डाल रही है। जब गवर्नमेन्ट कोई कदम उठाती है तो उसे धोखा बतायेंगे। जब कर बढ़ाते हैं और राज्य की पूंजी बढ़ाते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं तो उसको आप कहते हैं कि किसान की कमर टूट रही है। जो साधारण जनता नहीं है बल्कि जिसके पास ७५ बीघा तक जमीन है उसको छोड़ कर उससे अधिक जमीन पर जो उपज करता है उस पर यह कर लगाया जाता है तो कहते हैं कि इससे देश का किसान बर्बाद हो जायगा, देश की पैदावार घट जायेगी। जो कर लगाये गए हैं वे कर की प्रणाली के अनुसार ही लगाये गये हैं और इस तरह से देश आगे बढ़ता है। आप समझते हैं कि करों से हमारी कमर टूट जायगी। मैं मानता हूँ कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो मोटे २ काम करते हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिये। इसी तरह से यह जो बजट है उसको मैं इस रूप में कह सकता हूँ कि यह बजट बिल्कुल इस प्रकार का है कि जहां पर जरूरत होती है वहीं पर ये बादल जाकर बरसते हैं, यह नहीं कि बादल बने, उड़े और कहीं पर भी टकरा कर बरस गये। इसलिये मैं कहता हूं कि जो आलोचना की जा रही है उस आलोचना में कोई तथ्य नहीं है। करों का लगाना आवश्यक है। और देशों ने भी जिन्होंने उन्नति की है कृषि पर कर लगाए हैं। रूस के अन्दर भी भूमि पर कर लगाया गया था। जापान ने भारी कर लगा कर कृषि की उन्नति की थी। चीन के अन्दर तो ६० प्रतिशत तक भूमि पर कर लगाया गया था और इस तरह से चीन देश आगे बढ़ा था। क्योंकि हमारा देश भी एक कृषि प्रधान देश है और विकास के जो काम हमारे यहां पर चल रहे हैं उन विकास के कामों से जो किसान लाभ उठा रहे हैं उन किसानों से कर लेना देश को आगे बढ़ाना ही है। यह हमारा सिद्धान्त हो सकता है कि जो पूंजी हम किसानों के हित के लिये खर्च कर रहे हैं उस पूंजी को कर्जे के रूप में ही इकट्ठा किया जाय और उस कर्जे के रुपये से पूंजी पैदा की जाय। राजस्थान के अन्दर भी पूंजी का निर्माण हुआ है और हमारी ४१३ करोड़ की पूंजी मौजूद है। तो उस हालत में जो इसको दिवालिया कहते हैं, जो कहते हैं कि राज्य दिवालिया हो गया है, उनका यह कहना उचित नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम लोगों ने जो राजस्थान की सेवाओं के अन्दर कटौती की है, उसके बारे में भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि हम लोग सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह चाहते हैं कि यहां पर ऐसा एक्ट पास होना चाहिये जिससे राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों में इन्सेंटिव पैदा हो। मैं समझता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी कमी जो है वह यह है कि काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और जो नहीं काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको एक ही मापदण्ड से हांका जाता है। इसके लिए अमेरिका के अन्दर सबसे पहले एक एक्ट पास किया गया। गवर्नमेंट एम्पलांईज इन्सेंटिव अवार्ड्स एक्ट। इस एक्ट के तहत उन काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं हटाया जाय लेकिन जो काम करने वाले नहीं हैं उनको निकाल बाहर किया जाय। राजस्थान में जो ५५ साल के बाद भी ५८ की उम्र तक कर्मचारियों को रखा जाता है यह अनुचित है और हम चाहते हैं कि ५५ वर्ष की उम्र के बाद के लोगों को स्टेच्यू सर्किल की सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाय। जो आदमी ५५ वर्ष के बाद नए तरीके से सोचने की ताकत नहीं रखते, किसी प्रकार की नई बात नहीं कर सकते, नए तरीके से

(श्री मूलचन्द डागा)
सोच नहीं सकते, उनको निकाल बाहर किया जाय और जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को तरक्की दी जाय।

इसके सिवाय जो मेरा ख्याल है कि हमकों, चाहे इधर की तरफ बैठने वाले हों, चाहे उधर की तरफ बैठने वाले हों, उपाध्यक्ष महोदय, आपके दाईं ओर बैठने वाले हों या बाईं ओर बैठने वाले हों, दोनों ओर के ही सदस्य और विधान सभा के जो भी लोग हैं, हम लोग बराबर बात करते हैं कि देश की उन्नति के कार्य होने चाहिए, विकास से लाभ जनता को मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रेस भी अगर चाहे तो प्रेस भी इसमें ज्यादा काम कर सकता है। प्रेस के लोग भी अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति जागरूक रह सकते हैं और निकम्मे और अयोग्य कर्मचारी हैं उनकी आलोचना करके प्रेस बहुत ज्यादा लाभ पहुँचा सकता है और देश के अन्दर नई बात पैदा कर सकता है। आज जो लोग काम करने वाले हैं उनको कोई विशेष मौका नहीं मिलता और जो लोग काम करने वाले नहीं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है तो इस हालत में राजस्थान में इस बात की हमें व्यवस्था करनी चाहिए कि जो कर्मचारी काम कर सकते हैं उन लोगों को मौका दिया जाय।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग मजदूरों को बोनस देते हैं, उन मिल मालिकों के लिए जो बोनस देते हैं उनके लिए यह होना चाहिए कि इन मिलों के अन्दर गवर्नमेंट के चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स होने चाहिए, ताकि वे सही हिसाब जांच करके बता सकें और मजदूरों को पूरा बोनस मिल सके। बोनस के मामले में उनकी खुद की जांच होगी तो उससे मजदूरों को जितना बोनस मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है।

इसके अलावा मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि आज जो सबसे बड़ा जरूरी काम है समाजवाद लाने के लिए और जिस समाजवाद की हमारी इच्छा और अभिलाषा है और जो हम सोच रहे हैं, जिसकी ओर हमारे कदम बढ़ चुके हैं, उसके लिए यह आवश्यक है कि होस्पिटल्स में जो काटेज वार्ड्स हैं वह नहीं होने चाहिए। वहां पर एक ही वार्ड होना चाहिए, जहां पर समान रूप से समान बीमारी का इलाज किया जाय। वहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए और सबका एक समान इलाज होना चाहिए।

इसी के साथ जो भत्ते वगैरह दिए जाते हैं, एक ऑफिसर टूर पर जाता है तो मेरे खयाल में उसको आठ रुपया, दस रुपया या पन्द्रह रुपया मिलता है और उसी के साथ जब एक नौकर जाता है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जाता है तो उसे डेढ़ रुपया या दो रुपया मिलता है। यह मेरे खयाल से हम जैसे और बातों में समाजवाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं इसी तरह से इन बातों की ओर भी हमें सोचना चाहिए। समाजवाद लाने के जो तरीके राजस्थान के वित्त मंत्रालय ने अपनाए हैं, आपने कुछ बातों की ओर देखा होगा और जिस बात पर आपकी आलोचना भी होती है, एक ने कहा कि तीन बड़े पैराग्राफ हरिजनों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लिख दिए।.........

श्री विजयसिंह रावत : एक ने नहीं, एक माननीय सदस्य ने कहा।

श्री मूलचन्द डागा: हां, एक माननीय सदस्य ने कहा, श्रीमान् आपके एक विरोधी दल के नेता ने कहा और यह कहा कि तीन बड़े सैन्टेंन्स, वाक्य वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में दिए हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : श्रीमान् श्री जी हुजूर एक हजार आठ श्री कह दो।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि राजस्थान में आज जो भाई अनुसूचित जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति के हैं उनसे आप पूछें कि राजस्थान के जितने कानून बने हैं, आप किसी कानून को ले लीजिए, उन कानूनों में जमीन अलाटमेंट का कानून ही ले लीजिए, अगर किसी को जमीन अलॉट की जाती है सबसे पहले इनको जमीन दी जाती है, अगर किसी को नौकरी दी जाती है तो उसमें पहले नौकरी में इनको प्रिफरेन्स दिया जाता है, इसी प्रकार आगे बढ़ने का उनको मौका दिया जाय। छात्रवृत्तियां बढ़ाई गई। दो लाख रुपयेसे ६ लाख रु० बढ़ाये गये। मैं कहता हूं कि ये बोर्डिंग हाउस, होस्टल्स जहां पर लड़कों को मुफ्त पढ़ाया जाता है, जहां लड़के पढ़ कर होशियार बनते हैं। इस प्रकार से ये कहते हैं कि एक दिन में दुनियां में ताजमहल बन जाय। ताजमहल खड़ा करते हैं तो उसके लिए कई बातें चाहिए। इसका कारण है कि विरोधी दल के नेता आज इस प्रकार की बातें करते हैं जबकि उन्होंने २० रुपये से ४० रुपये छात्रवृत्ति कर दी। जब उन्होंने होस्टल्स के खर्चे का सवाल उठाया तो उसको बढ़ा दिया। ७५० रु० में मकान बनाते थे उसको १ हजार का कर दिया। आप अनुसूचित जन जाति के लोगों को भुलावे में डालते हैं। गांधीजी का जो स्वप्न था उसके लिए हम लोग यह चाहते हैं कि वह पूरा हो इसलिए जो पिछड़ा वर्ग है उनको आगे लाना चाहते हैं, और यही कारण है कि वे आगे आरहे हैं। आगे आने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज वे चुनौती देते हैं गलत कामों के लिए।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि राजस्थान सरकार गारन्टी पर शराब बेचती है।

श्री मूलचन्द डागा : शराब के लिए मना करती है कि शराब न पी जाय। शराब पीने की आदत तो आप जैसे उन लोगों ने बिगाड़ी है जो राजमहलों में रहते हैं। हमारी कोशिश तो यह है कि सिगरेट भी न पीयें। मुरारजी ने सिगरेट की मुनादी की है। राजस्थान सरकार ने बिलकुल ऐलान कर दिया है कि शराब कम की जाय। मैं कहूंगा कि यह एक प्रगतिशील कदम है, क्योंकि इससे शराब की बिक्री कम होगी और जो लोग शराब के पीने के आदी हैं उनको कम पीने को मिलेगी। इस प्रकार से हमारा कदम जो है वह सराहनीय है।

एक बात और है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम लोग इस बात को चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूं कि हमारी जो पूंजी है, जो हमारी दौलत है उसका पूरी तरह से अंकन हो जो नहीं किया गया है। मैं वित्त-मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि हमारे आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कानून बड़े बड़े तो आपने बनाये हैं, कानून चुस्ती के साथ बनते गये, लेकिन उनकी पालना सुस्ती के साथ हुई है। हमने स्मोकिंग के बारे में कानून बनाया है कि राजस्थान में नाबालिग या बच्चे हैं वे स्मोकिंग नहीं कर सकते। उस कानून का पालन नहीं हुआ और आज कल

(श्री मूलचन्द डागा)

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता आरही है उसका एक उपाय है कि उनको अनुशासन के बारे में नम्बर दिये जायें। सारे साल में जो काम करता है उसी हिसाब से अनुशासन के नम्बर उनको मिलने चाहियें। हम यह चाहते हैं कि गांव या शहरों के हिस्से उन विद्यार्थियों को सौंपे जायं, और जब तक विद्यार्थी श्रमदान नहीं करें खाद के गड्ढे तैयार नहीं कर दें, अपने श्रमदान से उस गांव को सुन्दर नहीं बना दें तब तक उन्हें आगे प्रमोट नहीं किया जाय।

हरियाणा का एक उदाहरण है जहां काम करने वाले २-३ कार्यकर्त्ताओं ने गांव की आवश्यकताओं को अपने हाथों और पैरों की ताकत के बल पर पूरा कर दिया। यह जो भावना है श्रमदान की यह कालेजेज में पैदा की जानी चाहिए, और सारे विद्यार्थियों के परीक्षा-फल के साथ २ जब तक कि उनका श्रमदान किया हुआ साबित नहीं हो तब तक उनको सर्टीफिकेट नहीं दिये जायें। इस प्रकार हम शक्ति को बढ़ा सकते हैं।

मैंने एक बात देखी है हम लोगों के अन्दर कई लोग जो इधर बैठने वाले हैं कोई यह कहने को तैयार हैं कि हमारी जो आमदनी है उस आमदनी का क्या करें ? बड़ी २ बातें करने को तैयार हैं। कांग्रेस पर कीचड़ उछालने को तैयार हैं, ताने कसने को तैयार हैं, थपकियां देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जो काम करने की शक्ति है उसको काम में लें तो देश की उन्नति हो सकती है।

मंत्री महोदय के भाषण में कहा गया कि हम आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आशा और विश्वास के बजाय आपका कोआॅपरेशन तक नहीं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग पढ़े-लिखे हैं उनमें कई लोग ऐसा समझते हैं कि हर दिन महीने का फर्स्ट एप्रिल होता है। तो ताश खेलने वालों को जो पैसों से ताश खेलते हैं उनको गैम्बलिंग एक्ट में ले लिया जाय। कितनी शक्ति आज उनकी इस काम में अपव्यय होती है। दिन-रात ताश खेलते हैं और पैसे से खेलते हैं। उनको गैम्बलिंग एक्ट में लाया जाय। ये शराबी लोग जो अपना समय अपव्यय करते हैं वे देश को नुकसान पहुँचाते हैं। जो शक्तियां काम नहीं कर रही हैं उन शक्तियों को अपव्यय होने से रोकिये, क्योंकि मैंने देखा है कि वे हर दिन को फर्स्ट एप्रिल समझते हैं। हर दिन फर्स्ट एप्रिल नहीं होता है। काम करने के घण्टों में काम कराया जाय, और टैक्स उन लोगों पर डाला जाय और इतना डाला जाय कि जिससे उनकी क्रय शक्ति न बढ़ जाय और वे आराम की वस्तुओं पर ज्यादा न जायें।

राजस्थान के वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी सराहना मैं इस बात से करता हूं कि वह एक संतुलित बजट है। वित्त मंत्री ने बतलाया है कि संतुलित बजट के द्वारा देश आगे बढ़ सकता है और वह देश को आगे बढ़ाने का तरीका है और काम करने का एक तरीका है। हमें सिंचाई का काम करना है उसमें हम प्रगति कर सकते हैं। हमारी कृषि-नीति है जिसके आधार पर बी० डी० ओज० को खत्म करके एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर को सब कुछ कर दिया है। इस प्रकार यह बजट एक संतुलित बजट

(श्री मूलचन्द डागा)

है। लेकिन जिसकी जैसी भावना है वैसी ही मूरत देखता है—"जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"। मैं समझता हूं कि इस बजट से आगे हम आशा और विश्वास के साथ काम करें तो राजस्थान आगे बढ़ सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय जब मैंने बजट पर बड़ी २ बातें सुनी तो मुझे एक किस्सा याद आगया। एक आदमी को नौकरी की जरूरत थी और एक महाजन को नौकर रखना था और एक किसान को भी नौकर रखना था, लेकिन नौकर रहने वाले की एक शर्त थी कि जो उसको खीर खिलायेगा उसके यहां नौकर रहेगा। किसान सीधा और सरल होता है तो उसने कह दिया कि हर शनिश्चर को खीर खिला देगा। जब वह महाजन के पास पहुंचा तो उसने कहा आई दिवाली खिलाई खीर, आई दिवाली खिलाई खीर इस तरह से सौ दफा जल्दी जल्दी बोल गया तो वह समझा कि दिवाली जल्दी जल्दी आती है तो ठीक है, लेकिन दिवाली तो साल में एक ही दफा आने को थी। उन्होंने बड़ा सुन्दर सुन्दर मिसालें दीं कि लगान माफ कर दिया, छोटी छोटी बातों पर, पापड़ पर टैक्स नहीं बढ़ाया है और राजा-महाराजाओं के ऊपर टैक्स तीन लाख पानी बिजली का लगा दिया, हमने दाख, बादाम, काजू व सूखे मेवों पर टैक्स लगा दिया। देखने वाले को ऐसा लगता है कि वाकई प्रगति की बात है, लेकिन इसमें एक भी मामला प्रगति का नहीं है।

पहले मैं जमीन पर लगान नहीं लेने के बारे में कहता हूं कि जमीन का लगान बन्द करके आपने शत्रुता का कार्य किया है। लेकिन इस वाक्य से मेरी हालत वैसी नहीं जो उस राम-भक्त की हुई थी। एक निकासी हो रही थी और बरात जाने को थी और बींद ने घोड़े पर पैर रखा तो बरातियों ने कहा कि राम-नाम सत्य है, तो एक भक्त ने कहा कि राम नाम तो सत्य है और बिल्कुल सत्य है लेकिन इतना होते हुए भी इस समय व्यावहारिक नहीं है इस वक्त बोलना। आपने लगान को बन्द किया है जिस टैक्स को आसानी से जनता ने पचा रखा है, जिसको वे आसानी से दे रहे हैं। वे इस बात की चिन्ता नहीं करते हैं कि आप लगान कितना लेते हैं। वे तो यह चाहते हैं कि हमारे यहां पर काम हो। जब आप से कहा जाता है कि आप बान्ध बनाओ तो आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। कहीं से मांग आती है कि डाक्टर भेजो। जीवित आदमियों के लिए डाक्टर न भेजो तो मत भेजो लेकिन जो एक्सीडेन्ट से मर जाते हैं उनके लिए तो भेजो। मेरे अपने क्षेत्र में ६ अस्पताल हैं वहां पर एक भी डाक्टर नहीं है। एक्सीडेन्ट से कोई मर जाता है तो पोस्टमार्टम के लिए ६०-६२ मील ले जाना पड़ता है। उससे जिन्दा आदमी तकलीफ में हो जाते हैं, क्योंकि गांवों में अभी भी मानवता है। गांव में कोई मर जाता है तो जब तक उसका दाह-संस्कार नहीं हो जाता है वे खाना नहीं खाते हैं दो-दो दिन तक भूखे रहते हैं। यह तो स्थिति है। इसके उपरान्त आप यह और कह रहे हैं कि हम लगान बन्द कर रहे हैं। एक तरफ तो आप लगान बन्द कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बैटरमेंट लेवी लगा रहे हैं और पिलाई की दर बढ़ा रहे हैं। तो यह तो वैसे ही हुआ कि एक भाई साहब अपनी बहिन के यहां बीरबस्सी के त्यौहार पर गये और साथ में हंसिया यानी दांतली भी लेते

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

गये। बहिन के यहां पर पहुंचे तो वहां पर घी की बाटकी, शक्कर और भात खाने को परोसा गया। जब वह वापिस वहां से आये तो हंसिया तो वहां पर छोड़ आये और कस्सी साथ ले आये जिसका मूल्य अधिक होता है।

बीरो आयो वीर बसी
लायो दांतली
ले गयो कस्सी

तो यह हालत आज हो रही है। एक तरफ तो यह बताया जारहा है कि हम लगान बन्द कर रहे हैं और दूसरी तरफ बैटरमेंट लेवी और पिलाई की दर बढ़ा रहे हैं। एक तरफ यह बता रहे हैं कि हम पापड़ पर टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से टैक्स बढ़ा रहे हैं। हम जब पैदा हुए थे उस समय देश गुलाम था। लेकिन हमारे बाद में जो हमारे बच्चे पैदा हुए आज गर्व के साथ में कहते हैं कि हम आजाद मुल्क में पैदा हुए। लेकिन आज हम से पूछते हैं कि पिताजी आप कहा करते थे कि जब आपकी आंख दूखती थी तो आप घी शक्कर खाया करते थे लेकिन घी शक्कर हमें कब खाने को मिलेगा? वास्तव में आज आपके यहां ऐसी स्थिति हो गई है कि उससे बाध्य होकर कहना पड़ता है—

"मोट्यारों नालो मती घी शक्कर री बाट।
दुर्लभ कर दी आज ये जौ मक्की की घाट।।

आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जौ-मक्की की घाट भी दुर्लभ हो गई है। आज घी और शक्कर की बात तो बिल्कुल ही दुर्लभ हो गई है।

हमारे यहां जो औरतें जो पापड़ बनाती हैं वह अपने दोनों हाथों से काम करती हैं, एक हाथ तो प्रतीक है ग्रामोद्योग का और दूसरा खेती का। खेती के काम के अन्दर ग्रामोद्योग राम हैं तो खेती और गऊ पालन सीता हैं। जब तक राम और सीता साथ २ नहीं होंगे तब तक काम कैसे चलेगा? आपने आज गांवों के घर-घर में जो ग्रामोद्योग थे उनको तो खत्म कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : बिजली आ गई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप महरबानी करके मुझे बोलने दीजिये। आप इस सब की चिन्ता मत कीजिये।

वैसे आज राम और सीता दोनों हैं लेकिन आप करते क्या हैं। एक तरफ आपने घाणी को सबसीडी दी है और दूसरी तरफ आपने खादी वालों को सबसीडी दी है। एक तरफ आपने घाणी वालों को सबसीडी दी है तो साथ में तेल के लिऐ एक्सपैलर भी लगा दिये हैं इससे घाणी वाले मर गये, दूसरी तरफ आपने खादी वालों को सबसीडी दी और साथ में कपड़े की मिल दी तो वह भी मर गये। आपने किसी को भी नहीं छोड़ा है। इसलिये आप महरबानी करके ऐसी योजनाएं बनाइये, जिसकी वजह से ग्रामोद्योग और खेती दोनों ही चल सकें। किसी कवि ने कहा है—

एक मूंडा के साथ में हाथ दिया हरि दोय।
काम देवण्यां होय तो भूखो रहे न कोय।।

मैं कहता हूं कि कोई भी भूखा नहीं रह सकता है, आप काम तो दें।

अब आपने विकास अधिकारियों को तोड़ने की योजना बनाई है। मुझे खुशी है, और मैं आपको इसके लिये बधाई देता हूं

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

कि आपने शुरुआत तो की है विकास खण्डों को तोड़ने की। वैसे आपने पहले ग्राम काकियों की पोस्ट तोड़ी थी, अब इनका नम्बर आया है। तो कृपा करके आप इनको तोड़ दें तो अच्छा ही होगा। यही नहीं है, आखिर हर साल जो आप पद तोड़ रहे हैं तो ये लोग जायेंगे कहां। इसलिए आपको शिक्षा की पद्धति को बदलना होगा। हर साल हजारों लड़के परीक्षा पास करके आते हैं। वैसे ईश्वर को मंजूर कुछ और ही है। कंस को यह कहा गया था कि देवकी के जो आठवां पुत्र होगा, उसका तुम वध कर देना नहीं तो वह तुम्हें मार देगा। लेकिन नारद ने उसको ऐसी सलाह दी जिससे उसके पाप का घड़ा भर जाय उन्होंने कहा कि तुम किस चक्कर में पड़ते हो, कौनसा आठवां और कौनसा सातवां। तुम हर बच्चे को मार देना। इसी तरह से आज किसान जो हैं वह तो क्रांति नहीं कर सकते हैं, वह तो तकलीफ को सहते रहते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, वह ज्यादा से ज्यादा बेकार होंगे तो वह निश्चित रूप से कुछ सोचने वाले हैं और फिर कोई न कोई क्रांति आयेगी। इसलिये आप यह सब कर रहे हैं।

अब आपने कहा कि शराब पर आपने टैक्स बढ़ाया है। इससे कुछ लोगों को खुशी हुई होगी। लेकिन आपने जो टैक्स शराब पर बढ़ाया है उससे मेरे सामने एक दूसरा ही दृश्य आता है। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। उस समय क्या दृश्य था कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोण भी देखते रहे। अगर वे दोनों बैठ कर देखते नहीं रहते तो महाभारत युद्ध नहीं होता। लेकिन उस समय तो केवल एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ। लेकिन आपके राज्य में लाखों द्रौपदियों का चीर हरण होता है। वह इस तरह कि जो व्यक्ति शराब पीता है, उसके बच्चे बिलबिलाते रहते हैं और औरतें फटे कपड़े में रहती हैं। अगर आप शराब पर टैक्स लगाते हैं और सोचते हैं कि इससे शराब के पीने में कमी हो सकती है। मैं कहता हूँ कि यह गलत है क्योंकि शराब पर कितना ही टैक्स हो, लेकिन उससे शराबी शराब पाने में कमी नहीं कर सकता। अगर वह कोई कमी कर सकता है तो दूसरी २ चीजों में। अगर टैक्स के द्वारा शराब की खपत में कमी कर सकते तो महात्मा गांधी को यह कभी नहीं कहना पड़ता कि "चाहे सुधारक कितनी भी कोशिश करें लेकिन जब तक राज्य शराबी को शराब पीने की इजाजत और सुविधा देते रहेंगे, सुधारकों को कभी सफलता नहीं मिल सकती।" इस शराब में तो वैसे ही इतना टेम्पटेशन होता है। फिर ज्योंही ठेकेदार गारन्टी सिस्टम के कारण घर पर शराब लेकर पहुंचता है तो चाहे कितनी ही कीमत बढ़ी हुई हो, शराबी शराब पिये बिना नहीं रह सकता। वह शराब पीयेगा जरूर और अगर कटौती करेगा तो बाल बच्चों की रूखी सूखी रोटी में। औरत जो फटी धोती पहनती है, उसके बिल्कुल फटने पर वह दूसरी नहीं ला सकेगा। इसमें वह जरूर कमी करेगा। मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार शराब की आमदनी को लेकर चलती है तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हमारे यहां कहा गया है—

जैसा खाये अन्न वैसा होये मन।
जैसा पीये पानी वैसी बोले वाणी।।

कोई नाव भरी हुई जा रही है, और उसमें

Page No.83

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

से कोई मान लो डूब जाय। तो क्या कहा जाता है? कोई न कोई पापी था और अगर कोई तर जाय तो कहा जाता है कोई न कोई धर्मात्मा था। हमारे यहां जो आप कमाई करते हैं उसमें किसी सेठ ने कितना ही धन लगा दिया हो लेकिन श्रमिक लोग जो दिन भर की पसीने की कमाई में से कुछ दे देता है तो लगता है कि काम शुभ होगा। इसलिये किसान जो रात दिन मेहनत करता है। उसका पैसा वह सरकार को टैक्स में देता है तो उससे क्या होता है कि काम अच्छा चलता है, लोगों में सद्बुद्धि पैदा होती है। और अगर शराब से हुई कमाई का पैसा काम में आता है तो रास्ता गलत होता जाता है। इसलिए इस आय को आप छोड़िये। मैं कांग्रेस के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि शराबबन्दी के लिए उन्होंने योग दिया है। वह यह भी चाहते हैं कि गारन्टी सिस्टम बन्द हो। उनको राज्य से कहना चाहिए कि इस शराब के टैक्स के चक्कर में मत फंसिये।

अब आप टैक्स लगाने में भी सुधार की दुहाई देते हैं तो दुख: होता है अभी शराब की बिक्री पर पंचायतों को दो परसेंट टैक्स दिया गया है। दो परसेंट टैक्स की बात को सुन कर मैं रो उठा। एक जिला प्रमुख हैं, भावनाशील और सच्चे आदमी हैं। उन्होंने सच्चे हृदय से मुझे लिखा कि ऐसा लगता है कि चूंकि अब आप राजा महाराजाओं के साथ हो गये हैं इसलिए आप टैक्स का जो शराब की बिक्री पर मिल रहा है विरोध कर रहे हैं। मैंने उनको समझाया और बताया कि इससे होगा क्या आखिर। जब हमारे यहां एक्साइज डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी तो इसलिए हुई थी कि शराबबन्दी करनी है। लेकिन जैसे जैसे आमदनी बढ़ती गई, वैसे वैसे लोभ में सरकार पड़ती गई। फिर तो येन केन प्रकारेण कई सिस्टम ढूंढ लिये गारन्टी सिस्टम ढूंढ लिया। यह गारन्टी सिस्टम राजस्थान के भाल पर एक कलंक का टीका लगाने वाला है। यह एक ऐसा टैक्स है, जो राजस्थान के मुंह पर कलंक का टीका है। और यह कलंक का टीका, यह न भाषणों से मिटेगा और न नारों से। इसके लिए तो हमें बलिदान देना होगा। जगह जगह से पंचायत के लोग शराबबन्दी का प्रस्ताव कर रहे हैं, इसलिये दो प्रतिशत देकर आपने उनको भी एक रोटी का टुकड़ा फेंक दिया है। अभी तो आपने दो प्रतिशत टैक्स से शुरूआत की है लेकिन आगे जाकर वह २५ प्रतिशत तक भी बढ़ सकता है। आज जैसे हम राज्य सरकार को कहते हैं दारू बन्द कराओ। तो वह कहती है कि दारू बन्दी कर देंगे तो हम पैसा कहां से लायेंगे? कल यही स्थिति पंचायतों की भी हो सकती है। कल को पंचायत भी यही कहने वाली है अरे यह क्या कर रहे हो। दारू बन्दी हो जायगी तो हमें पैसा कहां से मिलेगा? इस तरह से आप सारे राजस्थान को कलाल बना रहे हैं, सारे राजस्थान को पतित कर रहे हैं। कलाल सरकार, कलाल जनता, ऊपर से नीचे तक सब कलाल हो जायेंगे। अभी यह कहा जाता है कि हम अंगूर की शराब बनायेंगे और विदेशों में भेजेंगे। मैं अपको कहता हूं कि पहले मीरा की भक्ति विदेश भेजते थे और प्रताप की शक्ति विदेश जाती थी, लेकिन अब आप कलाल बनेंगे और मदिराफरोश बनेंगे।

यह भी कहा जाता है कि हम जो योजनायें बना रहे हैं उनसे देश में तरक्की हो

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

रही है। आप देखियेगा कि किस तरह से देश में तरक्की हो रही है। जैसे मेरी दादी के वक्त में कुल्हड़ से घी डाला जाता था, और जब मां का वक्त आया तो कुल्हड़ की जगह में घिलोड़ी में डाल कर डाला जाने लगा। और अब जब बहू का समय आया है तो घिलोड़ी में एक चिथड़ा रख कर, फूम्बा रख कर उससे चुपड़ा जाने लगा

"दादी घृत कुल्हड़ पकड़, मायड़ भरियो लेर।
आज जीमावे है बहु कदीयक फूम्बो फेर ।।"

यह हालत आपने कर दी है। लेकिन आप अब समझिये कि जनता अब सहने वाली नहीं है। हम तो आपको यह समझाना चाहते हैं। विरोधी होने पर भी यदि कोई अच्छी और सच्ची बात कांग्रेस की तरफ से आयेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे चाहे कोई भी उसका विरोध करे। लेकिन जो बात गलत होगी उसका हम विरोध करना चाहेंगे। भाषण तो कांग्रेस के कई लोगों ने बहुत अच्छे दिये हैं विरोधी लोगों से भी अच्छे, विरोधी लोग भी इतना नहीं बोल सकते जितना आपने विरोध किया है। लेकिन आप अपने शब्दों में और तरीके में सामान्जस्य बिठायें। आपने भाषण तो अच्छे दिये हैं लेकिन जब वोट देने का मौका आयेगा तब आप वोट नहीं देंगे। भीष्म पितामह से जब कहा गया कि न्याय किसकी तरफ है तो उन्होंने कहा कि न्याय तो पाण्डवों की तरफ है लेकिन वह खुद लड़े कौरवों की तरफ से। तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि हिन्दुस्तान को नीचे गिराया। अब इसी तरह हम लोग भले ही ८५ या ८८ हों लेकिन आप लोगों में से आठ आदमी भी कह दें कि आप शराबबन्दी नहीं करोगे तो हम तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं

(३ म. प.)

तो जिन ८८ का असर नहीं होने वाला है उनसे ज्यादा उन ९ का असर होने वाला है। आप एक दफे इसकी परीक्षा करके देखें। मैं आपको कहना चाहता हूं मेहरबानी करके आप एक बात को ध्यान में रखें कि:—

"जनता अब नी सह सके मंहगाई की चोट,
संभलों नीतर होवसी देश मांहि विस्फोट"

अगर आप इस अवसर पर नहीं संभलेंगे तो देश में बड़ा भारी विस्फोट होगा। आप शराब को बन्द करिये और अपने दूसरे खर्चों में कमी करिये। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पर खर्च कम करिये। पब्लिक को टैक्स देने में कमी भी एतराज नहीं है यदि वह अच्छे कामों में खर्च हो।

कृपा करके पंचायतों से शिक्षा को हटा दीजिये। आज प्राइमरी स्कूलों की ऐसी दशा है जैसी कि भेड़िये के सामने बच्चे को डालने की स्थिति होती है। इसलिये इसको वापिस शिक्षा विभाग को दे दीजिये वरना उसका यही हाल होगा जैसे भेड़िया के पास बच्चे को डालने से होता है।

"आज राज देखो करी दे कर कतरी भून।
अणमणियां रा हाथ में गांवांरा इस्कूल ।।"

बच्चों को पढ़ाने के लिये अच्छे आदमी चाहिये। मगर आज हम देखते हैं कि वहां के मास्टर सरपंचों के इशारे पर चलते हैं बच्चों की पढ़ाई नहीं होती और जैसे कंजरों की हाजरी थानेदार लेता है उसी तरह से हाजरी लिखी जाती है जो यह उचित नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन

Page No.85

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

करूंगा कि प्राईमरी स्कूलों को वापिस शिक्षा विभाग के पास भेज दीजिये । कोओपरेटिव वालों को कोओपरेटिव और एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन वालों को एग्रीकल्चर के साथ कर दीजिए और इन ब्लॉकों को खत्म करिये । आप इस ओर बढ़ रहे हैं इसलिये इसकी मैं प्रशंसा करता हूं ।

इसके बाद मैं करों के बारे में कहना चाहता हूं :

मैलो कर कर कर करे खर्च आंखियां मींच ।
जीसू सब के कर करे आज आंखियां बीच ।।

अगर आप कर इकट्ठा करके अच्छे कामों में खर्च करें तो जनता कभी उसे बुरा नहीं मानेगी । मगर देखते हैं कि लोग आज नाराज क्यों हैं । लोग देखते हैं कि जिनके पास पहले कुछ नहीं था आज तीन तीन कारें खड़ी हों, बंगले हों और जिनकी औरतें सोने से पीली हों तो लोगों को बुरा लगता है कि वे क्या करते हैं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप महात्मा गांधी का रास्ता अख्तियार करिये । मैं केवल आपको ही नहीं बल्कि अपने साथियों को भी यही कहता हूं । आपने राजा महाराजाओं के बिजली आदि के लिये कहा, मैं कहना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार एम० एल० ए०, मिनिस्टरों के बंगलों और गवर्नर पर भी पानी बिजली पर कर लगाते तो कोई बात थी मगर इस तरह से लोगों को भुलावे में डालने से कोई काम नहीं चलेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि शराब पर आपने टैक्स बढाया है इससे शराब कभी बन्द नहीं होगी इससे ज्यादा बढ़ेगी और इलिसिट डिस्टिलेशन ज्यादा होगा । आज-आप प्रिवेन्टिव फोर्स और असिस्टेन्ट एक्साइज कमिश्नर को तोड़ रहे हैं । हो सकता है कि आप इसमें ऐसे आदमी लगावें कि जो शराब नहीं पीता हो । इसलिये मैं कहूंगा कि आप इस पोस्ट को नहीं तोड़ें । और प्रिवेन्टिव फोर्स से इलिसिट डिस्टिलेशन बन्द कराने में मदद लें ।

आपने छोटे व्यापारियों को सहूलियतें दी हैं इसमें कर बीस हजार से बढ़ा कर चालीस हजार करदें शराब के टैक्स से मुक्त करिये और गारन्टी सिस्टम को बन्द करिये छोटे व्यापारियों के लिये आपने कुछ सुविधाएं और छूट दी हैं और आपमें खेती करने व छोटी जाति वालों के लिये बहुत रहम है तो आपको चाहिये कि उनको सहूलियतें दें तो ज्यादा उत्पादन होगा । लोगों को लगान देने में कोई दिक्कत नहीं है । आज कल तीन घोबे निकालने पड़ते हैं । वे तीन घोबे भी निकाल देंगे और उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होगी । और वे १० मन के बजाय १५ मन पैदा कर देंगे । इतनी बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर फतेहसिंह !

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बे अर्से के बाद मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है इसलिये मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, गीता में भगवान् कहते हैं :

परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे ।।

अर्थात् धर्म संस्थापनार्थय साधु पुरुषों की रक्षा के लिये और दूषित कर्म करने वालों के विनाश करने और धर्म को पुनः स्थापित

(मेजर श्री फतेहसिंह)

करने के लिये मैं समय समय पर अवतरित होता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, राजा अथवा शासन को भी भगवान् का दूसरा रूप माना गया है । ऐसे हमारे शास्त्रों, वेदों और गीता में मानते आये हैं । शासन का भी लक्ष्य है कि साधु पुरुषों की रक्षा करे, दुष्टों का संहार करे और जनता से धर्म का आचरण कराये । लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति में हमारा राजस्थान का शासन असफल रहा है । हमारा राजस्थान का शासन दोष पूर्ण है । और इसमें सुधार की आवश्यकता है लेकिन दुर्भाग्य से हमारे सदस्य नेतागण इस सुधार में बाधक हैं । सत्तारूढ दल के नेता शासन में प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करते हैं जिसके फलस्वरूप पक्षपात, अन्याय और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शासकों को अपने चरित्रों को बदलना होगा और अगर मैं यह बात कहूं तो कोई एतराज नहीं होगा कि जनता में यह आम धारणा है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे कांग्रेस के सम्बन्धित लोगों ने येन केन प्रकारेण अपने पदों का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार के साधनों को अपना कर धन उपार्जित किया है लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार की तरफ से और राज्य की ओर से कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई । सही बात है जैसा टेनीसन ने कहा हैं: Sin seems less, the sinner seeming great. अर्थात् अगर पाप या अपराध करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके पाप और अपराध दूसरे लोगों की दृष्टि में छोटे नजर पड़ते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सादड़ी के सोना कांड की बात कई बार गाई गई थी और जो जांच कराने को है उसकी गाथा सैन्ट्रल पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है और उसकी गाथा चुनावों के दिनों में राजस्थान के प्रत्येक शहर और गांवों में पहुंच चुकी है । ये बड़े गम्भीर आरोप हैं उनकी जांच होनी चाहिये थी । मगर इसकी जांच नहीं कराई गई इससे शासन के प्रति जनता में इस प्रकार की धारणा पैदा हो गई और जनता सोचने लगी कि अवश्य दाल में कुछ न कुछ काला होगा । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज शासन में बहुत बड़ा दोष है और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा दोष है और उसको किस तरह से दूर किया जावे उसके लिये मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं ।

मेरा पहला सुझाव यह है कि एक न्यायिक कमीशन की नियुक्ति की जावे जिसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह मंत्रियों और विधान सभा के सदस्यों और बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसकी जांच करेगा । उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह ज्ञात होगा और कई माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि फर्स्ट मार्च ६७ को राजस्थान के विपक्षी दल के सदस्यों ने मिल कर संयुक्त दल का निर्माण किया और एक १७ सूत्री कार्य-क्रम बनाया था और उसमें एक न्यायिक कमीशन के द्वारा जांच कराने की व्यवस्था रखी थी ।

(३.०६ म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

इसी तरह यह सरकार जुडिशियल कमीशन नियुक्त करें । मैं समझता हूं कि अगर संयुक्त दल की सरकार बनती तो आज

(मेजर श्री फतेहसिंह)

इधर बैठने वालों को उधर बैठने का अवसर प्राप्त होता और इस प्रकार के कमीशन की नियुक्ति करते। (चीयर्स) अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत बड़े बड़े नेता जो आज नजर आते हैं। इस तरह दुनियां में घूमते हुए नजर नहीं आते और उनके स्थान पर कोई दूसरी जगह जेलों में होते।

मेरा दूसरा सुझाव भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और है, वह यह है कि राज्य सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक विधान सभाई, प्रत्येक मंत्री और प्रत्येक अधिकारी अपनी चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सरकार को दे, ताकि समय आने पर मालूम किया जा सके कि आया उस विधान सभाई ने, उस मंत्री ने या उस अधिकारी ने भ्रष्टाचार के साधनों को अपना कर जनता के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं किया है। इस सुझाव पर भी मैं चाहता हूँ कि सरकार ध्यान देगी।

मेरा तीसरा सुझाव है कि प्रत्येक विधान सभाई क्षेत्र में ऑफिशियल्स और नोन ओफिशियल्स की विजिलेंस कमेटी का निर्माण होना चाहिए और विजीलेंस कमेटी का कर्त्तव्य होगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार का भ्रष्टाचार को दूर करने में सहयोग करे और कोई भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो जनता से सहयोग करे।

इन सुझावों पर सरकार ध्यान देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।

श्रीमन्, मैं खाद्य समस्या के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस सदन में खाद्य समस्या पर विचार हो चुका है पर जो सरकार की ओर से जवाब दिया गया उससे मुझे सन्तोष नहीं है। राजस्थान कृषि प्रधान देश है, इसमें ८० प्रतिशत जनता कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करती है हमारी सरकार ने करोड़ों रुपया कृषि उन्नति के लिए पिछले वर्षों में खर्च किया है करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी, इतनी योजनाएं बनाने के बाद भी राजस्थान भूखा का भूखा है और खाद्यान्नों का हमारे यहां अभाव है। खाद्यान्नों के अभाव को दूर करने के लिए और खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मेरा सुझाव है, मैं चाहता हूँ सरकार जरूर इस ओर ध्यान देगी।

पहला सुझाव यह है कि विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाय, जब तक कि खाद्यान्नों के अभाव को दूर नहीं कर देते हैं, छोटी-छोटी योजनाएं हाथ में ली जायं। नए कुए खुदवाना, पुराने कुओं को गहरा करवाना, छोटे छोटे तालाब, रपटें बनाना जो कि सिंचाई के साधनों को बढ़ायें, ऐसे कामों को हाथ में लिया जाय। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कुए खुदवाए नहीं जा रहे हैं कुए गहरे नहीं करवाए जा रहे हैं। कुए खुदवाए जा रहे हैं, गहरे करवाए जा रहे हैं, पर जो सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है वह कुओं को खुदवाने या कुओं को गहरा करवाने में काम में नहीं आती। मुझे इस बात की जानकारी है कि कुओं को खुदवाने के लिए तकावी मिली, आर्थिक सहायता सरकार से मिली, जो कुओं को गहरा कराने के लिए जनता को, किसानों को सहयोग सरकार से प्राप्त हुआ पर वह पैसा कुए गहरे करवाने में, कुए खुदवाने में

(मेजर श्री फते सिंह)

नहीं लगा वह पैसा किसानों ने मौसर करने में, अपने बाल बच्चों की शादी करने में लगा दिया ।

तो सरकार को इस तरह की सावधानी बरतनी है कि जिस काम के लिए पैसा देते हैं उसी काम में वह पैसा लगे इससे हमारा विकास होगा । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि कुए को गहरा करने के लिए अनुदान या ऋण मिला है तो हमारा कर्त्तव्य है कि जिस समय हम ऋण देते हैं उस समय देखें कि कुआ कितना गहरा है और वह धन खर्च हो जाता है कुआ गहरा करने में तो देखें कि वह कुआ वास्तव में गहरा हुआ है या नहीं ।

मेरा एक सुझाव खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में यह भी है कि किसानों को सस्ता बीज और सस्ता खाद उपलब्ध कराया जाय । यह अब भी मिल रहा होगा पर मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो मुफ्त में खाद और बीज देनें की सरकार व्यवस्था करे ।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में जमीन अभी भी फालतू पड़ी हुई है जो कृषि योग्य बनाई जा सकती है । मेरा सुझाव है कि सारी पड़त भूमि को कृषि के काम में लाया जाय और यह उन किसानों में वितरित की जाय जिनके पास कृषि के लिए कम भूमि है । मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि ऐसी भूमि का वितरण ऐसे लोगों में किया जाय जिनके पास भूमि नहीं है । इसका कारण है । भूमि का अलाटमेंट किसी चर्मकार को, किसी लोहार को, किसी खाती को, या किसी जुलाहे को करते हैं जो किसान नहीं है जो यह नहीं जानता कि हल कैसे चलाया जाता है तो वह जमीन पर किसी दूसरे से ही काम करवाएगा । तो इससे तो यह उत्तम होगा कि जमीन उन्हीं को अलौट करें जो पेशेवर किसान हैं पर उनके पास जमीन कम है कृषि करने के लिए ।

सभापति महोदय, आजकल किसानों की प्रवृति कैश क्रोप्स बोने में अधिक लगी हुई है, मेरा सुझाव है कि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक खाद्यान्नों के अभाव को दूर नहीं कर लेते हैं तब तक कैश क्रोप्स पर सरकार की तरफ से प्रतिबन्ध लगे ।

इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगे कि किसी के पास ५ बीघा जमीन है और उस ५ बीघा जमीन में वह टमाटर और गोभी बोता है, तो गोभी और टमाटर के बिना हम रह सकते हैं पर मक्का, ज्वार, गेहूँ आदि खाद्यान्नों के बिना हम नहीं रह सकते, तो सरकार सोचे कि इस तरह की कैश क्रोप्स के बोने पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

सभापति महोदय, बाजार में ओपन मार्केट में खाद्यान्न मिलते हैं और मैं समझता हूँ खाद्यान्नों का हमारे यहां अभाव नहीं हैं । खाद्यान्न कुछ ऐसे लोगों के कब्जे में पहुंच चुके हैं जो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं और उनके कोठों से वे खाद्यान्नों को बाजारों में भेजते हैं और ओपन मार्केट में उनकी प्राइस इतनी ऊंची है कि आम जनता, गरीब जनता उसको खरीद नहीं सकती ।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने आज कहा था और कई माननीय सदस्य इसका जिक्र कर चुके हैं, हमें ऐसी व्यवस्था करनी

(मेजर श्री फतेहसिंह)

होगी जिसके अन्तर्गत हम प्राइस के ऊपर कन्ट्रोल करें। सरकार से मैं कहूंगा, मदेरणाजी को कहूंगा कि आप रफी अहमद किदवई बनिये और प्राइसेज को कन्ट्रोल कीजिये, बढ़ते हुए खाद्यान्नों के भावों को कन्ट्रोल कीजिये, जनता आपको याद करेगी।

बाहर से आये हुए अनाज पर राशनिंग है, जो हमारे देश में पैदा हुआ है, उस अनाज पर कोई राशनिंग नहीं है, मेरा कहना है कि ओपन मार्केट में जो अनाज मिलता है वह मंहगा मिलता है, उसे हर एक गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि राशन का अनाज केवल उन्हीं नागरिकों को मिले जिनकी आमदनी प्रति माह कम है, कम आय वालों को ही राशन का अनाज मिलना चाहिये, दूसरों को नहीं। कम आय वाले कौन हैं? ३००-३५० रुपया प्रतिमाह आय वाले नागरिकों को मैं कम आय वाले व्यक्ति समझता हूं। इसके ऊपर सरकार विचार कर सकती है कि इस तरह से यह प्रतिबन्ध लगाने पर क्या असर होगा। कम आय वाले व्यक्ति को राशन का अनाज पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा और आज जो ओपन मार्केट में अनाज मिलता है उस पर प्रेशर कम आयगा क्योंकि ये छोटी आय वाले व्यक्ति ओपन मार्केट में अनाज खरीदने के लिए नहीं जायेंगे। यह तो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जब खरीदने वाले कम होते हैं तो फिर चीज सस्ती मिलेगी और ओपन मार्केट में भी भाव नीचे जायेंगे। तो इस प्रकार के प्रावधान से कुछ सहायता मिलेगी।

मेरा अंतिम सुझाव है खाद्य समस्या को हल करने के बारे में। ये जो संग्रह करने वाले हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं चोर बाजारी करने वाले हैं, उन पर सरकार दृढ़ता से कदम उठाए। अब तक ऐसा नहीं हो पाया जैसा कि माननीय बिरधीचंदजी ने जिक्र किया था आज संग्रह करने वालों के बारे में सरकार को मालूम है, राज्य कर्मचारियों को मालूम है कि फलाने व्यक्ति ने संग्रह कर रखा है लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

एक महीना पहले की घटना है। मेरे क्षेत्र में जवाजा गांव है वहां एक सेठ के यहां से ५३ बोरी गेहूं की प्राप्त हुई। यह एन्फोर्समेंट वालों की जानकारी में है, पुलिस की जानकारी में है। लेकिन उस सेठ के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। उनके पास अनाज बेचने का लाइसेन्स नहीं है लेकिन उसके पास एक बड़ा लाइसेन्स है वह यह कि वह एक नेता का रिश्तेदार है, बहुत नजदीकी रिश्तेदार है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस संबंध में मैं कुछ प्रसंग से बाहर हो रहा हूं लेकिन एक और घटना का जिक्र करना चाहता हूं। पिछले दो वर्षों से ब्यावर के कुछ नागरिकों और व्यापारियों के खिलाफ मोठ के आयात करने के मुकदमे चल रहे हैं और जिन दिनों चुनाव हो रहा था, उन दिनों तक ये मुकदमे चल रहे थे। मुख्यमंत्रीजी श्री सुखाड़िया वहां पधारे। उन्होंने व्यापारियों को बुलाया और उनसे कहा भाई कांग्रेस को वोट दो तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमे हटा लिये जायेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? व्यापारियों ने कांग्रेस की सहायता की लेकिन इधर क्या हो रहा है। सचिवालय में सुखाड़ियाजी खुद ऐसी बातों पर एक्शन नहीं लेते, वह नीचे

(मेजर श्री फतेहसिंह)

से काम कराते हैं, नीचे के अधिकारियों से काम कराते हैं लेकिन जब यह बात सचिवालय में सचिव के पास पहुंची तो मैं उस सेक्रेट्री का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने उन मुकदमों को विदड्रा करने के लिए अपनी सिफारिश करने से इन्कार कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वे मुकदमे बाद में भी अदालत में चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि अपने छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार और नेतागण किस तरह नीचे गिर सकते हैं।

बेरोजगारी के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैंने राज्यपाल का अभिभाषण भी पढ़ा, वित्त मंत्री महोदय का भाषण भी पढ़ा लेकिन दोनों भाषणों में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं किया गया कि आज प्रदेश में जो बेरोजगारी है विशेषकर शिक्षित वर्ग के लोगों में, उसका समाधान करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस कदम है या नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जो हमारे सर्विस रूल्स हैं वे पहले के बने हुए हैं, वे बहुत पुराने हो गए और वर्तमान जमाने में बहुत पुराने हो गए, आउट ऑफ डेट हो गए। राज्य सरकार को उस पर विचार करना चाहिए

(१.२५ म.प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा सुझाव है कि किसी राज्य कर्मचारी को ऐक्सटेन्शन नहीं दिया जाय। ५० वर्ष की आयु के प्रत्येक राज्य कर्मचारी को रिटायर किया जाय। ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि इस तरह से जो स्थान रिक्त होंगे, उन पर हमारे नौजवानों को रखा जाय जो स्कूलों व कॉलेजों में है, तो उनकी बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो जायगी। मैं अधिक विस्तार से इस विषय पर उस समय बोलूंगा जब कोई सम्बन्धित मांग सदन के सामने आएगा और मेरे कटौती के प्रस्ताव सदन के सामने आएंगे।

अकाल सहायता कार्यों को लेकर इस सदन में काफी वाद-विवाद हुआ है और यह आरोप लगाया है कि अकाल सहायता काय भी सरकार की ओर से दलगत राजनीति के आधार पर चलाए जा रहे हैं। मैं अपने अजमेर जिले के प्रश्न को लेकर ही बात करना चाहूंगा। मैं कह देना चाहता हूं कि राजस्थान के २१ जिलों में दुर्भिक्ष है। वहां राहत कार्य चलने चाहिये, उनको सहायता मिले लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ जिलों में मिले और कुछ के साथ अन्याय किया जाय। जब चुनाव हो रहे थे, उन दिनों राहत कार्य चुनाव को दृष्टि में रखकर किए गए, उसका मेरे पास प्रमाण है। हमें अकाल सहायता विभाग द्वारा यह कार्यवाही संक्षेप रूप में मिली है। उसमें कहा गया है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में कितना गेहूं अजमेर जिले को दिया गया और कितने श्रमिक अजमेर जिले में काम कर रहे थे।

जनवरी के माह में अजमेर जिले में २,८०६ टन अनाज उपलब्ध किया गया सरकार की ओर से जबकि फरवरी में ३,०५० टन उपलब्ध हुआ जब कि मार्च में जाकर १८५१ टन ही रह गया। इतना क्यों गिर गया ? इसी तरह से जनवरी के महीने में अजमेर जिले में ८,००० श्रमिक राहत कार्यों में काम कर रहे थे, फरवरी में १७,७०० और मार्च में एकदम ११,३०० !

Page No.91

(मेजर श्री फतहसिंह)

८,००० से १७,७०० और १७,७०० से एकदम ११,३०० होजाना, स्पष्ट इस बात का संकेत है, प्रमाण है कि राजस्थान सरकार के दिमाग में चुनाव था' और जब चुनाव फरवरी में खतम हो जाता है तब एकदम ६,००० श्रमिकों की संख्या घट जाना उसकी ओर संकेत करता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। ब्यावर क्षेत्र में करीब ६० गांव दुर्भिक्ष से पीड़ित हैं लेकिन ४-५ दिन पहले तक, मार्च, अप्रेल, मई महीने में वहां पर कोई अकाल सहायता कार्य नहीं चला। इस समय ब्यावर क्षेत्र में केवल बस्सी के तालाब का एक ही काम चल रहा है। इस लिए दलगत बिचारों से ऊपर उठकर, हयूमेंनिटेरियन ग्राउंड्स के आधार पर आपको इस पर अवश्य अमल करना चाहिए और इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

मैंने अपने वक्तव्य के आरम्भ में कहा था कि सरकार का कर्त्तव्य है कि जनता को धर्म का आचरण कराए और मैंने यह भी कहा कि इस बात में हमारी राज्य सरकार असफल रही है। श्रीमान्, जिस ढंग से हमारी वर्तमान सरकार ने शासन को हाथ में लिया, वह धर्म के आचरण के प्रतिकूल है। आपको मालूम है कि राजस्थान के ४१.४४ प्रतिशत मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया और ५८.५६ प्रतिशत ने कांग्रेस का विरोध किया। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में जनता ने विश्वास व्यक्त नहीं किया कि आगे आने वाले ५ वर्षों के लिए कांग्रेस के हाथ में राजस्थान का शासन सौंपा जाय। फिर भी अनैतिक साधनों को अपना कर, प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों का हनन करके कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाने में सफल हुई। कुछ माननीय सदस्यों ने इस ओर से उस ओर जाकर दल का परिवर्तन किया। मैं उन माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूं इस बात के लिये कि जिस प्रकार से उन्होंने अनैतिक आचरण किया है इस कारण वे जनता की निगाह से गिर गये हैं।

(घन्टी)

दो मिनिट और।

श्री अध्यक्ष : This is not relevant.

मेजर श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने वक्तव्य शुरू किया था तो बताया था कि सरकार का कर्त्तव्य यह है कि जनता में अच्छे आचरण को पैदा करे। लेकिन जो सरकार के अन्दर हैं और वे ही इस प्रकार के दूषित आचरण करते हैं तो प्रशासन से वे किस प्रकार भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं ? अंग्रेजी के एक कवि लोंगफैलो ने कहा है :

श्री अध्यक्ष : "It is not growing like tree".... ?

मेजर श्री फतेहसिंह : I could not follow you, Sir.

श्री अध्यक्ष : लोंगफैला की कविता बता रहा हूं।

मेजर श्री फतेहसिंह : "Lives of great men all remind us, we can make our lives sublime;

And, parting, leave behind us footprints on sands of time."

ऐसा अंग्रेजों के कवि लोंगफैलो ने कहा था।

और यही बात भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन युद्ध से मुंह मोड़ रहे थे तब कही:

जो कार्य करते श्रेष्ठ जन करते वही और भी।
उनके प्रमाणित पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी।।

मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय आचरण करें और ऐसे काम करें जो आदर्श रूप में हों। जिन माननीय सदस्यों ने दल परिवर्तन किया है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दें और पुनः कांग्रेस दल से चुनाव लड़कर यहां उपस्थित हों जिस प्रकार हरियाणा के श्री हरद्वारीलाल ने किया था ताकि आपके इस प्रकार के अनैतिक आचरण के द्वारा अधिक दूषित वातावरण न बने और इससे जनता पर भी एक अच्छा आदर्श उपस्थित होगा।

श्री अध्यक्ष: ओर्डर। ओर्डर!

मेजर श्री फतेहसिंह: इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

Thank you.

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री महोदय!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस बजट का आज की परिस्थिति के अन्दर स्वागत किया गया और कुछ माननीय सदस्यों ने राजनैतिक कारणों से या अपने स्वयं की विचारधाराओं की वजह से इसका विरोध किया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष के बजट को हमें इस भूमिका में देखना होगा कि जो राजस्थान में पिछले वर्षों से अकाल पड़ता रहा है और उस अकाल की वजह से राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर, आम जनता के जीवन स्तर पर जो कुछ असर पड़ता है उसको हम आंख से ओझल करके नहीं चल सकते। साथ साथ, माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को भी हमें विचार करके चलना होगा कि आया हम अपनी प्रगति को आगे बढ़ाना चाहते हैं—प्रगति से मेरा मतलब विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं—या हम यह मान कर चलते हैं कि आज देश में जो मुश्किल पैदा हुई है, राजस्थान के अन्दर भी जो मुश्किल पैदा हुई है, उन सब को देखते हुए हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए विकास के कार्य-क्रम को बन्द कर दें। मैं ऐसा समझता हूं कि आज की परिस्थितियों पर जो कुछ हालात हैं उन पर गहराई से विचार करने के बाद भी सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि हम अपनी प्रगति को रोक नहीं सकते। साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम घाटे का बजट प्रस्तुत करके और उस घाटे के बजट का मतलब भारत सरकार से यह अपेक्षा करना कि हमारे ओवर-ड्राफ्ट के लिए रिजर्व बैंक के जरिये वह आवश्यक हमको धनराशि दे वह आज की परिस्थिति के अन्दर उचित नहीं होगा।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भारत के वित्त मंत्री जी ने एक नीति निर्धारित की है और वह यह है कि डेफिसिट फाइनेन्सिग को रोका जाय खास तौर से इसकी वजह से कि जो देश में मूल्य बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं उन कीमतों को रोकने के लिए हमारे देश में डेफिसिट फाइनेन्सिग न हो। उस डेफिसिट फाइनेन्सिग का मतलब न केवल भारत सरकार से सम्बन्ध रखता है बल्कि हर स्टेट से ताल्लुक रखता है और इस बात से भी ताल्लुक रखता है कि न सिर्फ हमारे यहां रिजर्व बैंक का ओवर-ड्राफ्ट न हो, सच बात तो यह है कि रिजर्व में भी देख कर चलना पड़ता है। उस भूमिका में इस बजट को प्रस्तुत करने की बात आयी। विकास कार्य भी चले, डेफिसिट फाइनेन्सिग भी न हो और जीवन के माप दण्ड को ऊंचा करने में आज की परिस्थिति में कुछ न कुछ करें।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने इस बजट पर निगाह डाली होगी तो देखा होगा कि इस साल का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें विकास के कार्य के लिए ३९ करोड़ की व्यवस्था की गई है। ३९ करोड़ रुपये तो सेन्ट्रल असिस्टेन्स के तौर पर हमारे विकास क्रम में इसमें दिखाये गये हैं। ३९ करोड़ के अलावा २ करोड़ रुपयों का इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए और २ करोड़ रुपये वाटर वर्क्स के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इस प्रकार ४३ करोड़ के करीब भारत सरकार का असिस्टैन्स एल. आई. सी. का लोन उससे मिला कर हमारे पास प्रावधान होता है। वित्त मंत्री जी ने आपके सामने एक तस्वीर पेश की। ११ करोड़ के करीब की योजनायें हैं जिनमें कन्टीन्यूड स्कीम हैं और कुछ नये आइटम्स को प्रोवाइड करने के लिए प्रयत्न किया है। आज हमारे सामने बहुत स्पष्ट स्थिति है और कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात भी यहां पर कही है कि जो आंकड़े हमने बजट में प्रस्तुत किये हैं आमदनी के लिये कि इतनी इतनी आमदनी हमारी होगी कुछ माननीय सदस्यों का ख्याल है कि कुछ मदों में शायद हम उतनी पूर्ति नहीं कर पाये और कुछ मदों में शायद अन्डर एस्टीमेट हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों के बजट पर भी निगाह डाली जाय तो कैपीटल साइड में जहां तक हमारी सेल ऑफ लैंड से आमदनी का सवाल है उन आंकड़ों के अन्दर आयी है। पब्लिक लोन, स्माल सेविंग्स में भी फर्क हुआ है। टेक्सेशन में आमदनी का कुछ फर्क नजर आता है वह अकाल के कारण नजर आता है। जो एरियर्स हैं रियलाइजेशन होना है अकाल की परिस्थिति के कारण हमारे यहां बहुत बा भार पड़ा है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले प्लानिंग कमीशन का एक प्रतिनिधि और वित्त मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिये यहां आए थे तो उनसे बातचीत के दौरान भी हमने इस बात पर जोर दिया था कि राजस्थान की एक विशेष परिस्थिति है। काफी यहां का भू-भाग रेगिस्तानी होने की वजह से और प्रकृति का प्रकोप होने की वजह से पिछले तीन वर्षों में जो हम पर वजन पड़ा है उस वजन से भारत सरकार यह आशा करके चले कि हम उन ओवर ड्राफ्ट्स का चुकारा जल्दी कर सकते हैं तो मुश्किल सवाल है और मुझे आशा है कि उन प्रश्नों पर भारत सरकार भी हमारी मुश्किलात को सामने रखते हुये विचार करेगी। हमने चार करोड़ रुपया, पिछले वर्ष के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सन् १९६६-६७ के बजट के अन्दर ओवर ड्राफ्ट्स के पेमेन्ट के बाद रखा है। राजस्थान पर काफी वजन रहा है विशेष तौर से जब अकाल पड़ जाता है तो आमदनियां कम होती हैं, खर्चा बढ़ जाता है और साथ साथ इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से संचालित इन्डस्ट्री और इन्डस्ट्रीज की वजह से चाहे इन्टर स्टेट टैक्स हो या दूसरी टैक्स की आमदनी हो उसमें फर्क पड़ जाता है। तो वे सारी चीजें हमारे सामने आईं।

इस सदन को, यह भी, माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि जब बजट पार्लियामेन्ट में प्रस्तुत किया गया था तो इसके बाद इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से जितनी शायद ३ करोड़ ७५ लाख की रकम की तहरीर ली गई तो इसलिये कि डेप्रिसियेशन और इन्ट्रेस्ट आदि की उपलब्धियां हो सकेंगी, पर वापिस कुछ दिनों के बाद विस्तार में जाने के बाद हमें उसमें परिवर्तन करना पड़ा। इससे काफी बड़ा गैप पड़ा।

उसकी पूर्ति अगले वर्ष करने के लिये जैसा कहा, केवल प्लान के लिये, तो अभी जो प्रस्ताव हमारे सामने हैं उनको मन्जूर कर लें तो १.५ करोड़ रुपया हम एक तरह से प्लान में कन्ट्रीब्यूट करते हैं वरना सारे का सारा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की असिस्टेन्स से, जिस असिस्टेन्स में से कोई यह कल्पना नहीं करके चल रहा है उसका चालू खर्च में जाकर प्लान का जो खर्चा है एल० आई० सी० से जो रुपया लेना चाहते हैं उसको लेकर दूसरे कामों में खर्च कर देंगे। यह तो सम्भव ही नहीं रहता है।

यह प्रश्न हो सकता है हमारे सामने वह भी नहीं, कि जैसा मैंने निवेदन किया बहुत सा १.५ करोड़ एडीशनल एक्सपेन्डिचर, कुछ माइनर इरिगेशन के लिये भी आवश्यक है। वे खर्चे करने पड़ेंगे। वे एडीशनल आइटमों में रिफ्लेक्ट होते हैं। दूसरी मिनीमम आवश्यकतायें जो हमारे सामने हैं, उनको सामने रखने की कोशिश की गई है।

आज सदन में भी चर्चा हुई। माननीय वित्त मन्त्री जी के जरिये जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें भी जोर दिया है कि हम जो बचत हो सकती है, उसे करने के लिये ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां पर हम प्रयत्न करें।

माननीय अध्यक्षजी, कई बार ऐसा ख्याल बनता है कि शायद राजस्थान के अन्दर प्रशासन पर दूसरी स्टेटों के मुकाबले में हम ज्यादा खर्च करते मालूम होते हैं। ऐसा भ्रम होता है लोगों को। और इस वजह से ये ख्याल उठने लगते हैं कि राजस्थान के अन्दर सेक्रेटेरियट में कटौती ज्यादा क्यों नहीं हो रही है और जगह क्यों नहीं होती। इसके दो पहलू हैं। कुछ मुद्दों में यह सही है माननीय अध्यक्षजी, कि राजस्थान का क्षेत्रफल इतना ज्यादा फैला हुआ होने की वजह से आज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, रेवेन्यू एडमिनस्ट्रेशन पर और कुछ और चीजों पर यहां तक कि एक स्कूल पर, एक विद्यार्थी पर जो खर्चा आज राजस्थान के अन्दर आता है उसके मुकाबले में केरल जैसी जगह हो या ज्यादा आबादी वाली दूसरी जगह हो या ता वहां पर एक स्टूडेन्ट के पीछे खर्चा कम आवेगा व मुकाबले जो राजस्थान में आता है। पर माइल इलेक्ट्रिसिटी लाइन खींचने में यहां ज्यादा खर्चा आता है, सड़कों पर ज्यादा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

खर्चा आता है बनिस्पत दूसरी जगहों के। पर फिर भी निवेदन करूं मैंने इसकी जांच कराने की कोशिश की। राजस्थान के सेक्रेटेरियट पर जो खर्चा होता है वह खर्चा दूसरी स्टेटों के कम्पेरिजन में हमारा खर्चा क्या है ? मैं अध्यक्षजी, आज हमारे समक्ष, आज के विभक्त पंजाब की बात नहीं करता, जो पंजाब ६५-६६ में हरियाणा सहित था दो करोड़ के करीब आबादी का था उस पंजाब में उनके प्रशासन पर सेक्रेटेरियट में जो टोटल उनका खर्चा होता था वह ७९.६ लैक्स था। मध्यप्रदेश में ८०.८२ लाख, गुजरात, जिसकी आबादी राजस्थान के बराबर है वहां पर कुल खर्चा १ करोड़ १९ लाख ४७ हजार, मद्रास में १८६ लाख और राजस्थान के अन्दर ५८ लाख ४९ हजार, था। मैंने यह बात इसलिये प्रस्तुत करना पसन्द किया कि कभी कभी यह खयाल हो सकता है कि कहीं हमने हमारे प्रशासन पर जरूरत से ज्यादा खर्चा बढ़ता हुआ तो नहीं देखा। वक्त वक्त पर देखने की कोशिश की है। वह भी इसलिये जानने की कोशिश की कि मालूम हो सके कि माननीय सदस्यों के समक्ष रख सकें कि वास्तविक स्थिति क्या है।

मैं यह भी निवेदन करूं कि सेक्रेटेरियट की बात छोड़ भी दें। इसके अलावा सारे राजस्थान का जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खर्चे को भी देखा जावे तो भी स्टेटिस्टिक्स जैसे छपे हैं, जो वितरित हुए हैं उसमें राजस्थान का जो खर्चा आता है वहां हम १३ वें नम्बर पर हैं हिन्दुस्तान के अन्दर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा अलग अलग स्टेटों में है उनमें।

इन सब बातों के होते हुए भी हम इस बात पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एफिशियेन्ट हो और आगे के काम काज को गति भी मिलती रहे उन बातों को लक्ष्य में रखते हुए जितनी ज्यादा से ज्यादा इकोनोमी की जा सके, करें।

माननीय अध्यक्षजी, आज हमारे सामने यह भी एक गम्भीर प्रश्न उपस्थित है कि जो कटौती के प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्रीजी की तरफ से प्रस्तुत किये गये हैं और कुछ और सुझाव भी सामने आये हैं उनको करने के बाद अनएम्पलोयमेन्ट का सवाल है, रिट्रेन्चमेन्ट का सवाल है, इनके बारे में आगे क्या स्थिति रहे। यह प्रश्न भी सामने है और हम इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं कि ५५ साल से ऊपर जो हमने ५८ साल की उम्र की पहले बढ़ोतरी की थी उसको फिर से घटाकर ५५ साल पर रिटायर की एज कर दें। इसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों को बेकार न होना पड़े कम से कम। ५५ साल से ऊपर जो हैं उनके लिये रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, पेन्शन है, ग्रेच्युटी है, उनको इनका लाभ मिल जाता है, पर उनके सामने ऐसा प्रश्न नहीं आता जो इस तरह से कार्यरत हैं। उस पर हमारी निगाहें ज्यादा से ज्यादा हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

माननीय अध्यक्षजी, सदन के अन्दर जब चर्चा होती है तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे इन पिछले वर्षों के अन्दर राजस्थान के अन्दर न मालूम क्या लाइबिलिटीज़ हो गई हैं। इतनी लाइबिलि-टीज़ हैं असेट्स क्या हैं। मैं इस सम्बन्ध में सदन को समय समय पर जानकारी देता रहा हूँ कि आज इन पिछले पन्द्रह वर्षों में जिस सरकार को काम करना पड़ रहा है उसके ऊपर सदन में कहा, माननीय सदस्यों ने कई ने कहा कि जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देते हैं उसके बोन्ड्स करके आगे क्यों नहीं बढ़ा देते और क्यों नहीं इस देने को बन्द कर देते पर मैं बताऊं हमारी तरफ से जो हमने कमिटमेंट्स किये हैं उनसे हम मुकरना नहीं चाहते ।

मैं तो यहां तक निवेदन करूँ कि, इलेक्ट्रिसिटी और पानी के लिए भी यूनाइ-टेड फ्रण्ट ने हमारा रास्ता ज्यादा साफ़ कर दिया कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में १७ या १६ सूत्री कार्य-क्रम में प्रिवीलेज को रिमूव करना माना, तो उसमें वे प्रतिनिधि भी मौजूद थे कि जिनके नेता डूंगरपूर महारावल स्वयं हैं. जिसमें जयपुर के भी प्रतिनिधि हैं, और भी हैं, तो हमने यह भी महसूस किया है कि सबकी सहमति है, इस प्रकार का इन्नोसेन्ट प्रस्ताव है सबने कहा है वर्ना तो यूनिलिटरली मैं इसको नहीं चाहता कि जो तै किया है उसको खारिज कर देने वाली बात की जावे तो जो जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देने का फैसला किया उसका बहुत सा वजन इन ३ योजनाओं पर सरकार को उठाना पड़ा है।

चौथी योजना पर जो वजन आ रहा है उस वजन को उठाने के बाद आगे जाकर इसके लिए उतना ज्यादा वजन आगे की सरकार पर नहीं रहने वाला है। ४० करोड़ के करीब जागीरदारों के बोण्ड्स और दूसरी चीजों का खर्चा है उनका भुगतान ज्यादातर इन वर्षों में हुआ है और इन वर्षों में होने के बाद आगे जाकर इसका वजन कम होता है। पर वह भी लाइबिलिटी के तौर पर किया गया है। असेट्स बिल्ड हुए हैं। राजस्थान में जिस जागीरी इलाके पर पहले कब्जा नहीं था, आज जिसका कम्पेन्सेशन पे किया जाता है तो उनके आंकड़ों में गिनते हैं तो कितनी लाइ-बिलिटीज़ हैं और कितने असेट्स हैं तो जागीर रिजम्पशन के बाद जो कम्पेन्सेशन के तौर पर चुकारा किया जा रहा है और जो कैपिटल एक्सपेन्डीचर के तौर पर समझा जाता है. फाइनेन्शियल कमीशन के जरिये और दूसरे जरिये यह समझकर कि जागीरदारी कम्पेन्सेशन चुका कर असेट्स बिल्ड कर रहे हैं उनको रुपया आन पाई में व्यवस्थित करके कभी नहीं बताया कि इन सारी चीजों के खर्चे के बाद या कर्जदारी के बाद कुल असेट्स जाकर कहीं बिल्ड होते हैं। लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए यह असेट्स भी आज राजस्थान के अन्दर बिल्ड हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्षजी, कहा गया कि सिंचाई योजनाओं पर खर्चा हुआ है, दूसरे खर्चे हुए हैं उससे राजस्थान का क्या विकास हुआ? राजस्थान तो पिछड़ गया, न मालूम राजस्थान का क्या होगा। इन १५ बरसों के अन्दर, मैं आपसे निवेदन करूं कि क्या यह सही नहीं है कि १६५०-५१ में, उससे पहले की बात मैं छोड़ देता हूँ, राजस्थान में ५ लाख ३४ हजार एकड़ जमीन पर केवल सिंचाई होती थी और

।श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

उसके बजाय १९६४-६५ की फिगर्स से मैं आपको जाहिर करदूं कि ५५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। इसमें कुओं द्वारा सिंचाई भी आजाती है। नहरी सिंचाई भी बढ़ी है और जो टारगेट्स हमको अचीव करने थे वे अचीव करके राजस्थान की जनता को जो दिया है वह आपके समक्ष है।

एक नोर्मल ईअर में जो राजस्थान के अन्दर फूड प्रोडक्शन होता था, मैं आपसे निवेदन करूं कि १९५२-५३ में ३०.३७ लाख टन फूड प्रोडक्शन हुआ और १९६५-६६ और १९६६-६७ में जब कि अकाल की स्थिति थी, उन अकाल के बरसों में ३७.९४ लाख टन अन्न का उत्पादन १९६५-६६ के अन्दर हुआ है। इसके अलावा दूसरी चीजों में, जैसे गुड़, कपास, तिलहन आदि, इन सभी का उत्पादन बढ़ा है, वह अलग है। लेकिन फूड प्रोडक्शन के अन्दर इन अकाल के बरसों के अन्दर, पहले जो मामूली बरसों में फूड प्रोडक्शन होता था उससे भी अधिक उत्पादन हुआ है। तो आखिर प्रोडक्शन बिल्ड हुआ उसकी वजह से यह हुआ, कई नये तरीके निकाले उसकी वजह से यह हुआ। यह सही है कि पापुलेशन बढ़ गई है, डिमांड्स ज्यादा है लेकिन फिर भी आज भी, माननीय अध्यक्षजी बढ़ते भावों के खिलाफ........

श्री भैरोंसिंह : थर्ड फाइव इअर प्लान के जो टारगैटस आपने फिक्स किये थे इरीगेशन के वे क्या अचीव कर लिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक पोटेन्शल का सवाल है, अचीव किये हैं। टारगेट्स तो, पानी अगर नहीं आये तो नहीं अचीव कर सकते। हमने तालाब बनवाये लेकिन इस साल कई तालाब एसे हैं जिनसे कि करीब ४० हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है, लेकिन अकाल की परिस्थिति का असर उन पर पड़ा है। हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक अमुक टारगेट फिक्स किया लेकिन गांधी सागर में अगर पानी नहीं भरा तो टारगेट्स में फर्क पड़ेगा ही। कुछ चीजों में डिलेज़ भी हुई हैं, मैं यह नहीं कहता कि डिलेज़ नहीं हुई हैं।

आज अध्यक्ष महोदय, यह जो कई बार कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से देश बर्बाद होगया, देश की स्थिति खराब हो गई, मैं कहूंगा कि यह सर्वथा गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि आज जो आबादी बढ़ी है, उस बढ़ी हुई आबादी को देखकर जैसे विकास के काम हुए हैं वे अगर नहीं हुए होते और पुरानी स्थिति ही होती, तो देश को बहुत भयंकर स्थिति से निकलना पड़ता। मैं मानता हूं कि आज भावों की परिस्थिति से सारा हिन्दुस्तान संघर्ष कर रहा है। हमारे सामने कई तरह के परीक्षण आ रहे हैं। कई जगह नान कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनी हैं। पहले पहले जब नान कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनी तो पहले पहले यह समाचार आता था कि भाव गिर गये, कुछ रोज भाव गिरे, लेकिन धीरे धीरे फिर बढ़ गये। आज गेहूं, जो राजस्थान में मामूली बरसों में भी कम रहता है, वह आज की स्थिति में यू. पी., मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
के मुकाबले में कम है। लेकिन बाजरा में, जुवार में और मक्का के अन्दर आज हिन्दुस्तान के अन्दर, इस अकाल की परिस्थिति के अन्दर भी, सारी मुश्किलातों के अन्दर भी, राजस्थान के भाव दूसरी जगहों से कम हैं। आज अलग अलग जगहों पर परीक्षण किये जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, सारे देश में प्रयत्न हो रहे हैं। तो कोई नान कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसा कोई मार्ग बता सके कि उत्पादन बढ़ाने के सिवाय भी कोई भाव गिर सकते हैं तो हम भी देखेंगे। तो इन परिस्थितियों का हमको मुकाबला करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : गंगानगर में लाखों बीघा बंजड़ भूमि को नीलाम किया जाता है, बंजड़ भूमि को लिया जाता है उससे क्या फर्क पड़ने वाला है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! भाषण के बाद में प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको प्रस्तुत करने का लक्ष्य यह सामने रहा है कि इसको किस तरह से बेलेन्स कर सकें। इसका बैलेन्स करने में वजन उन लोगों पर डाला जाय जो इसको सहन कर सकें।

राज्यपाल महोदय ने जैसा अपने भाषण में उल्लेख किया छोटे फ्रेगमेन्टेशन यानी छोटी होल्डिंग जिनके पास हैं ऐसे लोगों पर लगान की कमी की बात कही गई। इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके अन्दर जिन लोगों के पास तीस स्टेन्डर्ड एकड़ से ऊपर जमीन है उन पर लगान की बढ़ोतरी की बात कही गई। इससे मैं समझता हूं जो माननीय सदस्य इधर या उधर दोनों तरफ बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे कि आज की परिस्थिति के अन्दर तीस स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि के ऊपर किनके पास है ? यदि उन पर पचास प्रतिशत सरचार्ज भी पड़ जाता है या साठ परसेन्ट पड़ जाता है तो उन पर वजन पड़ने से किसान वर्ग उस बोझ से नहीं दब जाता, या इससे किसान विरोधी बजट नहीं बन जाता। उन पर असर आना चाहिये और उनसे प्राप्त हुई रकम को गरीबों पर खर्च किया जाना चाहिये यही सामने रखकर इस बजट में चला गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं जो सिंचाई की योजनायें हैं, जिनके जरिये कृषि उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्न के अलावा जो चीजें हैं उसके ऊपर एक सरचार्ज इरिगेशन रेट को बढ़ाया इसमें दोनों परपज़ हैं आमदनी भी है साथ साथ उनका अन्न उत्पादन भी पूरा हो जाता है और उस पर वजन भी ज्यादा न पड़े यह ध्यान में रखा गया है। आज जिस किसान का पानी मिल जाता है नहर के जरिये एक किसान जिसकी जमीन ऊंचाई पर है उसके खेत तक पानी नहीं पहुंचता और एक किसान जिसकी खेत की सतह नीची है और पानी आसानी से मिल जाता है इन दोनों की जिन्दगी में कितना अन्तर है ? अगर जिसके पानी पहुंच जाता है उससे अगर हम पांच रुपया ले लेते हैं तो उस पर क्या

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

असर पड़ने वाला है। इस तरह से दोनों की जिन्दगी में काफी फर्क पड़ जाता है। इस वजह से सोचा गया कि जो किसान कुए से सिंचाई करता है उस पर पर एकड़ खर्च ज्यादा आता है और नहर से जहां सिंचाई होती है उसमें कम खर्च आता है और जो प्रकृति पर ही निर्भर करके चलता है उसका मिलान इनसे नहीं किया जा सकता। अच्छी वारिश होगई तो अच्छा होगया नहीं तो कुछ नहीं उसको एक प्रकार से अनिश्चित स्थिति को सामने रखकर गुजरना पड़ता है। सरचार्ज में जो बात सोची गई इस बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत सारे विचार रखे। उसी प्रकार से केटल के बारे में कहा गया और चीजों के लिए कहा गया उस पर तो वित्त मंत्री जी गौर करेंगे और मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि अपनी तरफ से कुछ कहूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो वजन डालने वाली बात आई है उस वजन को डालने वाली वात को इस बात में लक्ष्य रखने की कोशिश की गयी कि ऐसे व्यक्ति ज्यादा हैं कि जिनके ऊपर वजन डालना चाहेंगे आज की परिस्थितियों में जब कि भावों की इतनी मंहगाई है तो डालने का प्रयत्न किया जाये, उस बात की चेष्टा की गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य से राजस्थान के अन्दर या परिस्थितियों को कहना चाहिए एक ऐसी स्थिति आई कि चुनावों के बाद राष्ट्रपति शासन हुआ, कुछ बीच में उतार चढ़ाव आये। अब उन दिनों में राजस्थान के अन्दर इन अकाल के कामों के संबंध में एक टीम आई। उस टीम के आने के बाद जहां तक काम की प्रायोरिटीज का सवाल था कि प्रोडक्टिव वर्क्स को पहले प्रायोरिटी में लिया जावे उसमें किसी का मतभेद नहीं है। पहले भी राज्य सरकार की तरफ से करीब करीब वही हिदायतें थीं और उनके आने के बाद भी करीब करीब वही बात सामने रही कि इरिगेशन वर्क्स हैं, सोइल कन्जर्वेशन के काम हैं, अफोर्सेटेशन के वर्क्स हैं, इस तरह के वर्क्स को ज्यादा तरजीह दी जायें। लेकिन जो बजट पार्लियामेन्ट में प्रस्तुत किया गया और उसमें पहले जो चर्चायें हुईं, उसमें वित्त मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को यह कम्युनिकेट किया कि राजस्थान में इस वर्ष के लिए ५ करोड़ रुपये की अकाल सहायता के ऊपर सीलिंग होगी। इस ५ करोड़ रुपये की सीलिंग होने का मतलब यह होता कि पिछले वर्ष में जो खर्चा हुआ उसके एडजस्टमेंट में १ या १। करोड़ रु० निकलने के बाद इस सारे अकाल के पीरियड के लिए ३।-३।। करोड़ रुपये के करीब बचत उस लेविल पर काम चला लेने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं था। इसलिए आर्डर्स इश्यू हो गये कि एक एक डिस्ट्रिक्ट की यह सीलिंग होगी और उसके मुताबिक अपने कामकाज को कम करें। इसका कोई चुनावों से ताल्लुक नहीं था। राष्ट्रपति शासन के समय सीलिंग होती है और इन्स्ट्रक्शन्स गये और उसके अन्दर अपने कामकाज को कैसे एडजस्ट किया जावे यह सवाल सामने रहा। जब हमने कार्यभार संभाला उसके कुछ अर्से में केन्द्रीय वित्त मंत्री से मैं मिला और उनसे मैंने कहा कि राजस्थान में क्या परिस्थितियां हैं—कई इलाकों में तीन-तीन साल से अकाल पड़ रहा है। हम आज राजस्थान के अन्दर सर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
ऊंचा करके इस बात को कह सकते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, राजस्थान का आदमी मजदूरी मांगता है लेकिन राजस्थान के अन्दर किसी भी गांव में चले जायें वह यह नहीं कहता कि फ्री किचन्स खाल दें या मुफ्त के अन्दर ढाबा खोलकर उनको खाना खिलाया जाये ....

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने इस बात के लिए नहीं कहा। मैंने तो कहा था कि आप क्या मजदूरी देते हैं और पंजाब में क्या मजदूरी दी जाती है........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके विरोध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण की समाप्ति के बाद ही कहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : पंजाब के अन्दर मजदूर को ३ रुपये और २ रुपये मजदूरी मिलती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : और माननीय सदस्य कहते हैं कि राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर लगे लोगों को मजदूरी कम मिलती है और पड़ौस के अन्दर बहुत ज्यादा मिल रही है लेकिन मुझे यही निवेदन करना है कि कम मजदूरी में भी लाखों लोग काम करने आ रहे हैं। आपको पहले भी निवेदन किया है कि हमें राजस्थान को समझना होगा कि पिछले २० सालों के सारे एनैलेसिस को करें तो मालूम होगा कि राजस्थान में अकाल पड़ता है तो भीलों के इलाकों के अन्दर जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ पाकेट्स हैं उदयपुर का सारा जिला भी नहीं है मैं आपसे कहूं कि उदयपुर जिले के मावली में अकाल होगा या वल्लभनगर में अकाल होगा तो उतने लोग नहीं आयेंगे। भीलवाड़ा के लोग हर क्षेत्र के अन्दर काम करने नहीं आयेंगे लेकिन बदनौर और कुछ इलाकों में जहां रावतों की आबादी ज्यादा होगी भीलों की आबादी ज्यादा होगी, हरिजनों की ज्यादा आबादी होगी, लेबर वहां पर ज्यादा काम करने आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा तो राजस्थान में कोई भी जिला नहीं है जिसमें भील और हरिजन नहीं मिलें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर कई बार इसको कहा गया। मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मैंने जानने की कोशिश की कि आमतौर से रिलीफ वर्क्स पर काम करने कौन लोग ज्यादा आते हैं। कुछ परसेन्टेज कामन समझ लें लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा से ज्यादा यह मानना चाहिये कि लेबर का नम्बर आता है काम करने के लिए। उन लोगों में से ज्यादा से ज्यादा आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने डूंगरपुर से बाड़मेर को कम्पेयर करके समझने की कोशिश की कि दोनों जगह अकाल है और क्या तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन डूंगरपुर में है.... ...

श्री भैरोंसिंह : यह कोई कम्पेरीजन नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आप मेरी बात सुन लें। शिड्यूल्ड कास्ट को भी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

शरीक कर रहा हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों को शरीक करें फिर भी उसमें नम्बर बाकी रह सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की टोटल पापुलेशन बाड़मेर में १ लाख २५ हजार है और दूसरी तरफ डूंगरपुर जिसमें मैंने बताया कि भीलों की स्थिति दूसरी किस्म की होती है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन २ लाख ६३ हजार है उस २ लाख ६३ हजार के इलाके में और दूसरी जगह जहां कि इन कम्यूनिटी की आबादी कम है जो टर्न आउट होगा उसमें अन्तर होगा....

श्री भैरोंसिंह : यह मानकर चलें कि बाड़मेर जिले के अन्दर आपको लेबरर्स नहीं मिल रहे हैं और यह आपकी शिकायत है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं यह नहीं कहता कि लेबर नहीं मिल रही है। वहां पर जो बोर्डर रोड्स के काम को लिया गया उस पर लगाए गए। बीच में सीलिंग वाली बात हुई और प्रोडक्टिव वाली बात और इन्सट्रक्शन्स देने से नागौर में भी कमी हो गई, भीलवाड़ा में कमी हो गई, अजमेर में कमी हो गई सब तरफ से यह बात आई कि जो लेबरर्स काम पर आ रहे हैं उन को कम काम मिल रहा है तो जो भारत सरकार के प्रतिनिधि हमसे बात करने के लिए पिछली २ तारीख को आए थे—मुझे खुशी है कि उनके साथ जो बातचीत हुई उसमें हमने कहा कि ५ लाख की सीलिंग में अगर चलने की बात तय की जाएगी तो राजस्थान के अन्दर कई जगह भुखमरी के उदाहरण पेश होंगे। आज मैं कह सकता हूँ कि सराड़ा की बात कही गई और उसकी विस्तृत जानकारी मैंने भी की और मुझे मालूम हुआ कि वह महिला दो रोज पहिले ही २० किलो अनाज लेकर गयी है और वह भूख से मरने वाली बात गलत है। चाहे इस तरफ से कही जाए या उस तरफ से कही जाए यह बात गलत है।

तो जो टीम आई उससे हमने कहा कि कुछ रुपये ज्यादा खर्च हो जायें उस बात की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को काम दे सकें। मुझे खुशी है कि उन्होंने इसको माना है और इसको स्वीकार किया है। ५ करोड़ के बजाय सीलिंग वाली बात को हटाकर अगर ज्यादा भी खर्च करना पड़ेगा तो उस खर्च के अन्दर भी भारत सरकार की तरफ से आवश्यक सहायता मिलेगी और इसके इन्सट्रक्शन्स सब जगह जारी कर दिए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, विकास के कार्यक्रमों के बारे में और लोगों के पर कैपिटा के बारे में और दूसरी कई चीजों के बारे में यहां पर कहा जाता है कि इस शासन के अन्दर परेशानियां हैं, इसमें लोग पिछड़ गए, गरीब हो गए और चारों तरफ परेशानियों ही परेशानियों की बात की जाती है मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सब जगह की बात जाने दीजिए क्या यह सत्य नहीं है कि मैंने जयपुर को सन् १९४४ में देखा, १९४६ में भी देखा और १९५१ में भी देखा और सन् १९५१ से तो यहां काफी काम करने का अवसर मिला है और वह जमाना भी देखा है कि जयपुर से बाहर सिविल लाइन्स और बनीपार्क की तरफ जाते तो क्या वीरान हालत थी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और गांधीनगर में कांग्रेस का जलसा हुआ तो रेत के अन्दर भी चलने की नौबत आई और आज यहां सब जगह क्या हालत है। आज दूसरे इलाकों में भी तबदीलियां हुईं, शहरों में तबदीलियां हुईं, कई इलाकों के अन्दर आज चम्बल की तरफ चले जायें, कोटा की तरफ चले जायें—कई बार कहा जाता है कि शाहू जैन की जेबों में है, कोई कहता है कि बिड़ला की जेबों में है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस किसी भी पूंजीपति की जेब में नहीं है। सहायता देने वाले देते हैं, स्वागत है, नहीं दें तो उसके मुकाबिले में हम लड़कर आते हैं। इस सदन के अन्दर १५ वर्षों तक हमको बिड़ला जी का एजेन्ट कहा जाता था लेकिन इस साल उनके खिलाफ लड़ने की नौबत हो गई तो वह भी किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बिड़ला जी की चित्तौड़ की इन्डस्ट्री को हमने सस्ती बिजली देने का फैसला कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपति शासन के वक्त में फैसला हुआ मैं उस फैसले के विपरीत नहीं हूँ। मैं कोई डाक्टर के० एल० राव को या दूसरों को कन्डेम करके अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उसको कन्डेम नहीं करना चाहता हूँ........

उन्होंने इस बात को लक्ष्य में रखते हुए किया है कि जिनको बिजली दी जाय तो उससे राज्य को भी घाटा न हो और उनको भी समुचित रूप से बिजली मिल सके। इसमें किसी के द्वारा भी अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रश्न नहीं है।

यहां पर यह भी कहा गया कि तीन राजाओं की बिजली और पानी बन्द कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि सदन इस बात से अवगत हो चुका होगा कि बिजली और पानी की सहूलियत राजाओं के अन्दर सिर्फ तीन प्रिंसेज को ही थी दूसरे रूलर्स को नहीं थी। एक विशेष प्रकार का अधिकार तीनों को ही था और तीनों तक ही सीमित था इसलिए तीनों तक ही समाप्त किया गया है, सब का अधिकार समाप्त होने का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: एक एक लाख का प्रोविजन तीनों राजाओं के लिए रखा गया है, यह क्या है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आज इसके अन्दर प्रोविजन किस के आधार पर रखा गया है यह चीज मैं माथुर साहब के नोटिस में ले आया हूं वे देखकर कल आपको बतायेंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब राजाओं के लिए कहा गया है तो तीनों के लिए ही कहा गया है ...

श्री भैरोंसिंह: इसमें बचत क्या हुई? इस हाथ से लेकर इस हाथ से दे दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: देने की बात नहीं है। जो प्रस्ताव रखा गया है वह तीनों के लिए है और इस बारे में एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जयपुर के बारे में पहले लिमिट फिक्स नहीं थी और लिमिट फिक्स नहीं होने के कारण बराबर डिस्प्यूट रहता था। पिछले वर्ष ही एक लाख की लिमिट फिक्स हुई थी, वह कहीं बजट पेपर में आई दिखती है, इसको वित्त मन्त्रीजी देखकर स्पष्ट कर देंगे वरना इसमें कोई गम नहीं है।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले ने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह कहा कि हमारे यहां पर उदयपुर के महाराणा साहब के पिताजी की जागीर का कोई मामला है और चुनाव के पहले उस जागीर के मामले को ठीक किया गया चुनाव की दृष्टि से। मैं इतना निवेदन कर दूं और सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि उदयपुर के महाराणा साहब ने कभी भी इतने वर्षों में उनके पिता के जागीर के केस की चर्चा तक मुझ से नहीं की। दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार उस केस का फैसला आज की तारीख तक नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आर्डर्स हो गए हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके आर्डर्स भी नहीं हुए हैं और फैसला भी नहीं हुआ है। महाराणा साहब वोट देने आते हैं तो शिष्टाचार का तकाजा है कि मैं इस मौके पर उपस्थित होऊं और एक चुनाव ही नहीं तीनों चुनावों में, उदयपुर के हर चुनाव के मौके पर मैं वहां पर गया हूं उनका वहां पर स्वागत करने के लिए, भाषण एक जगह पर भी नहीं दिलवाया है, एक मोहल्ले में भी प्रचार के लिए नहीं बुलाया है। केवल उनका स्वागत करने के लिए मैं वहां पर गया हूं और अगर भैरोंसिंहजी भी वहां पर वोट देने के लिए आयेंगे तो उनका स्वागत करने के लिए भी जाऊंगा।

मेरे वहां पर स्वागत करने के लिए जाने के अलावा और कोई सवाल नहीं रह जाता है। इसके पीछे कोई और दूसरी बात नहीं है कि जिसको लेकर हम चलें।

यहां, अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई कि जो बहुत से हमारे पब्लिक स्टेट एण्टरप्राइजेज चलते हैं...

श्री भैरोंसिंह : सिरोही के लिए क्या कहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सिरोही की डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं हैं। कल माथुरसाहब बोलेंगे तब वे आपको कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां इस सदन में पब्लिक स्टेट एन्टरप्राइजेज़ के लॉस के बारे में जिक्र किया गया है। हम नहीं चाहते कि जो स्टेट एण्टरप्राइजेज़ गवर्नमेंट चलाए उसके अन्दर घाटा हो। हम चाहते हैं कि स्टेट एण्टरप्राइजेज़ एफिशियेंटली चलें और उनमें कुछ कमियां ही हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न भी रहा है और जो फिगर्स आज जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिए हैं उसकी विस्तार से जो परिस्थिति है उसके बारे में कल वित्त मंत्रीजी जो स्वयं स्टेट एण्टरप्राइजेज़ के मिनिस्टर भी हैं, अपनी तरफ से सारी स्थिति आपके सामने रखेंगे।

मुझे और ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करना है माननीय सदस्यों से कि जो बजट को बैलेंस करने का प्रश्न, आगे प्रगति और प्लान चलते रहें इसका प्रश्न और हमारे राजस्थान के अन्दर मामूली व्यक्ति पर वजन ज्यादा न आए उसका भी सवाल न रख कर यह बजट प्रस्ताव रखे हैं। फिर भी जो बहस सामने आई है उसके बारे में अन्तिम रूप से कल वित्त मन्त्री जी जब जवाब देंगे, उसके बाद मुझे आशा है यह सदन जो प्रस्ताव सामने रखे गये हैं उसका पूरी तौर से समर्थन करेगा।

Page No.104

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न नहीं। श्री बद्रीप्रसाद।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कल बोलूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष : (श्री बद्रीप्रसाद की ओर मुखापेक्ष) : आप प्रारम्भ करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कल बोलूंगा साहब।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नहीं है, एक क्लेरीफिकेशन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के विषय में बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि बजट का जो निर्माण होता है वह आम जनता के लिए होता है। जनता की स्थिति अच्छी हो, जनता की हालत सुधरे, इसलिए बजट बनाया जाता है। जो निम्न स्तर की जनता है, जिसका स्तर, लिविंग लेवल, लिविंग स्टेंडर्ड नीचा है, उसका लेवल ऊंचा हो, इस दृष्टि से बजट बनाया जाता है। अगर इस आधार पर कोई बजट होता है तो वह बजट ठीक है और अगर वह इस आधार पर खड़ा नहीं है, उस आधार पर नहीं बनाया गया है तो वह बजट गड़बड़ है या उसमें कमी है।

सारे निर्माण के काम भारतवर्ष में हमारे सामने चलते हैं और वास्तविक निर्माण का मतलब तो आदमी को ऊंचा उठाना है। परन्तु मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि इतने वर्षों में आदमी का जो सच्चाई का स्तर है वह नीचे गिरा है। और बहुतसी ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं कि आदमी के रहन-सहन का और खासतौर से सोचने का स्तर है वह बहुत नीचे गिरा है। इस प्रकार अगर बजट व्यक्ति को गिराता है या अगर हमारे देश की परिस्थिति व्यक्ति को गिराती है तो वह राष्ट्र ऊंचा नहीं उठ सकता है। राष्ट्र का मतलब दीवारों का नहीं है, राष्ट्र का मतलब मकानों से नहीं है बल्कि राष्ट्र का मतलब व्यक्तियों से है। व्यक्ति ही राष्ट्र है और अगर व्यक्ति नीचे गिरता है तो राष्ट्र नीचे गिरता है। अगर सारे निर्माण के होते हुए भी व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है, व्यक्ति के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और व्यक्ति के निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं रहता है तो सारी बातों के होते हुए भी राष्ट्र ऊंचा नहीं उठ सकता, राष्ट्र नीचे गिरता है। इसलिए मैं आपका ध्यान और आपके द्वारा सारे सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में आज जो स्थिति है वह अविश्वास की स्थिति है। कोई भी व्यक्ति बाजार में कोई भी माल लेने जाता है, हम किसी भी प्रकार की कोई चीज लेने बाजार में जाते हैं, हमें वह शुद्ध नहीं मिलेगी। चाहे घी लेने जाय, चाहे कोई और वस्तु लेने जावें, दूध लेने जावें, सोना लेने जावें, कोई भी वस्तु जब कभी हम खरीदने को जाते हैं तो वह शुद्ध मिलेगी इसकी गुंजाइश कम ही रह गई है। एक बात तो यहां तक हुई थी और जिसकी चर्चा हिन्दुस्तान की लोक-सभा में भी हुई थी कि एक आदमी जहर

(श्री फूलचन्द बाफना)

खाकर सो गया और प्रतीक्षा करता रहा कि उसको मौत आए लेकिन उसकी मौत नहीं हुई क्योंकि जहर में भी मिलावट थी। इसलिए मिलावट यहां तो जहर के मामले में तो फायदा कर गई परन्तु और तमाम चीजों के अन्दर जो मिलावट होती है इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। दिन-ब-दिन इस तरह की मिलावट बढ़ती जा रही है। मैं यह मानता हूं कि आज किसी का विश्वास किसी में भी किसी प्रकार से नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज तो इस चुनाव के मौके पर आदमी को भी गिराया जाता है। आप यह जानते होंगे कि चुनाव में जो हमारे क़ानून बनते हैं, चुनाव का जो क़ानून बना हुआ है कि छः हजार से अधिक खर्चा एक एम.एल.ए. नहीं कर सकता और २५ हजार से अधिक एक एम० पी० खर्चा नहीं कर सकता परन्तु मैं ऐसा मानता हूं कि इस क़ानून का पालन नहीं होता और हम ईश्वर की सौगंध खाकर, बड़ी ईमानदारी से कहते हैं कि हमने खर्चा बराबर किया है और इतना पैसा चुनावों में खर्चा किया है। क्या इस तरह की बातें करके आदमी नहीं गिरा है। तो क्या आदमी गिरकर देश को ऊंचा उठा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर व्यक्ति के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं है, सारे बजट के अन्दर व्यक्ति के निर्माण के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है।

भौतिक तरक्की के लिए बात है, भौतिक तरक्की के लिए बात की जाती है, लेकिन व्यक्ति को ऊंचा बढ़ाने के लिए एक भी बात नहीं रखी गई इस बजट में कि व्यक्ति को ऊंचा बढ़ाया जायगा मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं और यह मानता हूं कि आजकल तो व्यक्ति के खिलाफ यह हुआ है कि एम० एल० ए० की भी कीमत है, एम० एल० ए० भी मोल बिकते हैं। यदि राष्ट्र का भाग्य-विधाता मोल बिक जाय तो राष्ट्र का भाग्य तो मोल बिकेगा ही, इसमें सन्देह की बात नहीं है कि सारा राष्ट्र नीचे गिर रहा है। उधर जब ऐशो आराम करने की स्थिति भी पैदा होती है तो मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान की भौतिक तरक्की होते हुए भी राष्ट्र गिरेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब राजस्थान बना था उस समय के शास्त्री मंत्री-मण्डल का उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि वह मुझे मालूम है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिजली का खर्चा हरेक मंत्री के लिए मुकर्रर था कि ३५ रुपये तक की बिजली खर्च करे और उससे अगर ज्यादा करें तो तनख्वाह से कटवायें। इसी प्रकार से पानी का था उससे ज्यादा खर्च हो तो अपनी तनख्वाह से कटवायें। दवाओं के लिए मामूली बजट था कि इतना हो तो खर्च किया जाय। इस प्रकार के प्रतिबन्ध थे। परन्तु वे सारे प्रतिबन्ध धीरे-धीरे समाप्त हो गये और आज तो इतनी स्वतन्त्रता है कि मर्जी आये उतना खर्च करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विदेश में कोई मंत्री दवा कराने के लिए जाय उसके लिए ४५ हजार या लाख तक की रकम मन्जूर हो यहां तक अब खर्चा कर सकता है। यह आज के कानून में है। यह ठीक है कि आज इस तरह का नियम है इस प्रकार खर्च करने की छूट दे रखी है तो हम तरक्की की ओर नहीं जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वह भौतिक तरक्की है आदमी की तरक्की नहीं है और अगर व्यक्ति की तरक्की नहीं होती है तो राष्ट्र नीचे गिरेगा।

(श्री फूलचन्द बाफना)

हमारे दफ्तरों में इतना सारा खर्चा होते हुए भी काम में बड़ी शिथिलता है। काम जल्दी से जल्दी होना चाहिये परन्तु गवर्नमेंट के दफतरों के बारे में कहा गया है "अफसर करे न अफसरी दफतर, करे न वर्क, दास मलूका कह गये सब के काका क्लर्क" इस तरह से शासन का काम चल रहा है तो कहां राहत मिलती है। एक एक काम के लिए कितना समय लगता है, कितना खर्च होता है। इस प्रकार से न्याय भी नहीं मिल पाता है।

इसी प्रकार से योजनाओं के लिए है। योजना आदमी को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। अगर आदमी ऊंचा नहीं बढ़ता है और नीचे गिरता है तो यह किस तरह से योजना चल सकेगी। योजनाओं के लिए आजकल यह कहा जाता है योजना के तीन काम नक्शा, मीटिंग और सलाम। इस प्रकार योजना चलती है आदमी को गिराकर तो राष्ट्र को वे ऊंचा नहीं करेंगी चाहे कुछ भौतिक तरक्की हो भी जावे।

एक बात और बता देना चाहता हूं कि यह चुनावों में तो आदमी गिरता ही है, परन्तु सिनेमाओं, रेडियो पर गाने के कार्यक्रमों हमेशा इस तरह की बातें होती हैं, और इस प्रकार के गाने गाये जाते हैं कि उस वजह से आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता है। इसी प्रकार से सारी बातें हो रही हैं इसी प्रकार से परिवार नियोजन का भी है। उस पर कोई चेकिंग नहीं है। परिवार-नियोजन की जरूरत है, हम भी यह चाहते हैं। परन्तु व्यवस्था में गड़बड़ इतनी है कि कुंआरी लड़कियां और कुंआरे लड़के भी इसका इस्तेमाल करते हैं यह परिवार-नियोजन में इतनी बड़ी त्रुटि है। इसका चेकिंग नहीं किया जाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उसकी है जो कि इसका कार्य-संचालन करते हैं। आदमी को ऊंचा उठाने की बात भूल जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है।

मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका उपाध्यक्ष महोदय, उस ओर कि दुनियां में ऐसा शासन इस पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ जैसा कि राजस्थान में है। दुनियां में कोई उदाहरण नहीं है इसके बारे में। दुनियां के किसी राष्ट्र के इतिहास में नहीं है, पृथ्वी के किसी कौने में नहीं है कोई शासन यह कहता हो कि इतनी शराब बेचनी पड़ेगी। इसका कोई उदाहरण इतिहास में नहीं मिलेगा। तो यह राजस्थान का शासन अद्वितीय है कि वह कहता है कि तुमको इतनी शराब हर हालत में बेचनी पड़ेगी। यह उसकी जबरदस्ती है। आदमी शराब पीता है क्योंकि उसकी आदत खराब है। आदत की बात है वह अलग बात है, परन्तु सरकार इस प्रकार की बात कहदे कि इतनी शराब बेचनी पड़ेगी और शराब विक्रेता द्वारा भोंपू बजाया जाय कि शराब सस्ती करदी गई है तो मुझको यह ख्याल आता है कि अनाज महंगा है और शराब सस्ती हो रही है। इस प्रकार से हमारे देश की परिस्थिति हो रही है, और अगर आदमी गिर रहा है, तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदमी को गिराकर राष्ट्र को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता है चाहे हर व्यक्ति को लखपति बना दिया जाय। अगर एक व्यक्ति गिरता है, अगर व्यक्ति का चरित्र गिरता है तो राष्ट्र ऊंचा नहीं उठ सकता है। इसलिए बजट का आधार व्यक्ति को ऊंचा उठाना हो जिससे व्यक्ति नीचे नहीं गिरे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारे राष्ट्र की हालत इसी तरह की रही जैसा कि इस

(श्री फूलचन्द बाफना)

समय पतन में आगे बढ़ रहे हैं तो चाहे सारी तरक्की हो अर्थात् उसमें खेती के आंकड़े बढ़ें, सिंचाई के बढ़ें और सरकारी कथनानुसार इतने बढ़ रहे हैं कि मुझे ऐसा खयाल होता है कि जैसे जब युद्ध चल रहा था तो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी सरकार की तरफ से ऐसी खबरें आती थीं कि हमने इतनी भूमि पर कब्जा कर लिया और इतने आदमी मारे गये। उस कब्जे की भूमि के क्षेत्रफल को जोड़ा जाय तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सारी दुनियां जीत ली, इसी प्रकार से सरकार के उत्पादन के आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उत्पादन इतना भयंकर बढ़ गया है कि खानेवाले नहीं मिलेंगे, लेकिन हम उसको असलियत से नापते हैं तो नाप दंड यह होगा कि चीजें मंहगी मिलती हैं या सस्ती मिलती हैं। हम पहले जितनी सब्जी खाते थे उतनी आज खाते हैं कि नहीं, पहले हमारे बच्चों को जितना दूध मिलता था आज मिलता है कि नहीं। पहले जितनी आसानी में चीज आ जाती थी उतनी आसानी से आ जाती है कि नहीं। अगर उत्तर अनुकूल नहीं है तो मेरे खयाल में कहीं न कहीं गलती है। आंकड़ों के जोड़-बाकी में कहीं गलती है। वास्तविकता हमारे सामने है कि एक आदमी को जो पहले मिलता था आज उसको उतना नहीं मिलता है। पहले जिस आसानी से चीज मिलती थी आज नहीं मिलती हैं।

अगर आज कोई आदमी बेरोजगार है और धन्धा लेना चाहता है तो राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उसको रोजगार दे। अगर कोई आदमी मजदूरी करने को तैयार है और उसको हम काम नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि काम देने की परिस्थिति हमने पैदा नहीं की। इस लिए जितने आदमी मजदूरी करना चाहें, जितने आदमी धन्धा लेना चाहें उन सब को काम मिलना चाहिए, इसकी गारन्टी हमारी व्यवस्था में हो तो मैं समझता हूं कि चीज बराबर है अन्यथा गडबड़ है।

सारी चीज हमारी खरीद शक्ति पर निर्भर करती है। आज गेहूं का भाव १३० क्विन्टल है परन्तु हमारी जेब में पैसा है और हमारी खरीदने की शक्ति है तो वह मंहगा नहीं मालूम होता है। लेकिन हमारी क्रय शक्ति गिर रही है। मंहगाई और सस्ताई इतनी बड़ी बात नहीं है। चीज मंहगी है या सस्ती इस सम्बन्ध में असर पड़ता है हमारी क्रय शक्ति का। अगर हमारी खरीद शक्ति ठीक है तो मंहगाई असर नहीं करती है। वह मालूम नहीं होती है। हमारी खरीद शक्ति कमजोर होने से यह मंहगाई मालूम होती है। आज भी कुछ वर्ग ऐसा है जिसकी खरीद शक्ति पहले से तेज हुई है, जिनके पास पैसा इकट्ठा हुआ है उनको यह मालूम नहीं पड़ता है, परन्तु बहुत सा ऐसा वर्ग है जिनके पास मजदूरी भी पूरी नहीं। इस लिए हमारी खरीद शक्ति बढ़ी हुई होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोइ ऐसा नियम बना दे, इसको कई लोग दकियानूसी कदम कह सकते हैं, और आज की व्यवस्था में वह एक आश्चर्यजनक बात लगे, वह बात यह है कि वस्तु के बदले में वस्तु मिलेगी और सिक्के का चलन उठ जाय, तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी उत्पादक बनेगा, क्योंकि उसको कपड़ा चाहिए तो कपड़े के बदले में उसको कोई चीज देनी पड़ेगी तो कुछ न कुछ उत्पादन करेगा ही। अगर देश का उत्पादन बढ़ाना है तो मेरी

(श्री फूलचन्द बाफना)

ऐसी मान्यता है कि इस सिक्के की प्रथा को रवाना करना पड़ेगा, क्वाइन को छुट्टी देनी पड़ेगी और वस्तुओं की अदला बदली होगी तो हर आदमी को उत्पादन करना पड़ेगा, नाकाम नहीं रहना पड़ेगा, उसको काम करना ही पड़ेगा। कुछ न कुछ काम आदमी करेगा इस लिए देश का उत्पादन बढ़ेगा और हमारी समस्यायें हल हो जायेंगी। हम रोजगार नहीं दे सकते तो बेकारी भत्ता देना चाहिए। अगर बेकारी भत्ता नहीं देते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि शासन की जिम्मेदारी हम नहीं निभाते हैं। अगर लॉ एण्ड आर्डर की बात है उसकी व्यवस्था रखना है, गड़बड़ हो तो उसका इन्तजाम करना है, इन्तजाम नहीं करेंगे तो रोजगार दें। इसलिए मैने बेकारी के भत्ते का निवेदन किया था। वह चीज जरूर होनी चाहिए जिससे कि सरकार को जांचने का यह मापदन्ड हो जाय कि वह धन्धा दे सकती है या नहीं।

आज अगर मान लें कि कोई आदमी बीमार पड़ गया, गांवों में कई आदमी बीमार पड़ते हैं। कई ऐसे आदमी मेरे सम्पर्क में भी आते हैं जिनकी दवा-दारू का इन्तजाम पूरा नहीं होता है। आज एक गरीब आदमी बीमार पड़ता है और डाक्टर कहता है कि इसको टी० बी० हो गई है। इसको फल खिलाओ, इसको बाहर की शुद्ध हवा खिलाओ, इसको दूध पिलाओ, इसको पौष्टिक वस्तुएं खिलाओ लेकिन इन सारी वस्तुओं की कीमत चुकाने के लिए उसके पास पैसा हो, तभी वह खा सकता है। जब उसके पास पैसा नहीं है तो एक किताब में संविधान मात्र में यह लिख देने से कि सबको समान अधिकार है उस किताब का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। समान अधिकार उसको कहते हैं कि समान अवसर मिले, समान अवसर खरीदने का मिले। अगर समान अवसर नहीं मिलता है तो एक पुस्तक में लिखने से समान अधिकार नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर एक गरीब आदमी बीमार होगया तो वह दवा-दारू करवाना चाहता है तो वह प्रबन्ध है नहीं। एक तरफ तो आदमी ज्यादा खाकर बीमार पड़ता है और एक तरफ आदमी कम खाने से बीमार होता है, यह दोनों तरह की बीमारियां हैं। इसलिए इन बीमारियों को हटाना आवश्यक है। जो आदमी मजदूरी चाहता है उसको मजदूरी मिले। एक आदमी गरीब है और एक अमीर है तो मैं निवेदन कर दूं कि हमारे स्वतन्त्र देश में कि अगर एक आदमी अपने लड़के को डाक्टर बनाना चाहता है, अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता है, तो क्योंकि वह गरीब है इसलिए वह अपने लड़के को इंजीनियर या डाक्टर नहीं बना सकता। इस प्रकार की आज व्यवस्था है कि जिसकी जेब में पैसा है वह अपने लड़के को कुछ भी बना सकता है, होशियार बना सकता है, विद्वान् बना सकता है, टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जिसके पास में पैसा नहीं है वह अपने लड़के को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए इस स्वतन्त्र भारत में लाखों-करोड़ों विद्यार्थी, जिनके माता-पिता गरीब हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको आगे बढ़ाने का कोई इन्तजाम भी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी आज कोई लेने वाला नहीं है, न तो शासन लेना चाहता है और न समाज लेना चाहता है। ऐसा मालूम होता है कि जो आज वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं है।

(श्री फूलचन्द बाफना)

इसी प्रकार न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार माना गया है। लेकिन कचहरियों में जिस तरह से काम चलता है, उससे जिसकी जेब में पैसा नहीं है, वह न तो मुकदमा लड़ सकता है, न वह मुकदमे के लिए वकील मुकर्रर कर सकता है और न गवाहों को लाने ले जाने के लिए पैसा खर्च कर सकता है। जब वह यह नहीं कर सकता तो वह अपना मुकदमा हार जाता है। सत्य तो हार जाता है और झूठ जीत जाता है क्योंकि सत्य के पास में साधन नहीं हैं। मेरा निवेदन यह है कि सबको साधन उपलब्ध होने चाहिए, सबको अवसर उपलब्ध होना चाहिए। संविधान में या किसी किताब में समान अधिकार की बात कह दी जाय तो उससे काम नहीं चल सकता है। आज अगर कोई पैसेवाला आदमी जबर्दस्ती किसको अपने खेत से निकाल देता है, किसी को बेदखल कर देता है तो बेदखल हुआ आदमी भले ही मारा मारा फिरे, वह कोर्ट में नहीं जा सकता है। अपने खेत को वह वापिस नहीं ले सकता है क्योंकि वह खर्च नहीं कर सकता है आज आजाद भारत में भी आदमी गुलाम है। आज स्वराज्य उसकी जेब में है जिसकी जेब में पैसा है। अगर किसी की जेब में पैसा नहीं है तो वह स्वतन्त्र भारत में भी गुलाम है। इसलिए वास्तव में गरीबों की गुलामी को मिटाने के लिए बजट तैयार होना चाहिए। लेकिन इस बजट में इस प्रकार की कोई गारन्टी नहीं है कि हरएक आदमी न्याय प्राप्त करने के लिए मुकदमा लड़ सकेगा। इस बजट में कोई ऐसा उल्लेख या आंकड़ा नहीं मिलता है जिससे यह मालूम हो कि जो मुकदमा नहीं लड़ सकता है उसको शासन की तरफ से सहायता दी जायगी। अगर कोई वकील को मुकर्रर न कर सकने के कारण मुकदमा नहीं लड़ सकेगा तो बजट में उसके लिए प्रावधान होना चाहिये। अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे रोजगार देने के लिये सरकार बाध्य होनी ही चाहिये। अगर किसी के पास में अपना घर नहीं है तो उसके घर का इन्तजाम शासन को करवाना चाहिये। इन सब चीजों को देने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर यह सब होता है तब तो बजट ठीक है, नहीं तो नहीं। क्योंकि बजट का मतलब है कि हर आदमी की जिम्मेदारी, हर आदमी का उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है क्योंकि सरकार ने ला एन्ड आर्डर मानने के लिए हर आदमी को बाध्य किया हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक कथा में मुर्गियों की एक संविधान सभा बनाई गई थी। उसमें मुर्गियों को यह कहा गया कि तुम सबको यह अधिकार दे दिया गया है कि तुम यह निर्णय करो कि तुम्हें कच्चा खायें या पका कर खायें। मुर्गियों ने यह कहा कि हमने यह निर्णय लिया है कि हमें खाया ही नहीं जाय। तो उन्होंने कहा कि भई, तुम्हें यह संविधान के मूलभूत अधिकारों में यह अधिकार नहीं मिला है। तुम यह निर्णय नहीं कर सकतीं कि तुमको खाया नहीं जाय। खाया तो जायगा ही। लेकिन कच्चा खायें या पका कर खायें यह निर्णय तुम करो।

श्री गोकुल चन्द (खैरथल) : कौनसी कक्षा में पढ़ा है ?

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : लाल किताब में।

Page No.110

श्री फूलचन्द बाफना : मैं उन विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता हूं जो किसी कक्षा तक नहीं गये हैं। जो पूरा नहीं समझ सके हैं वह समझ जायें इसलिये यह कह रहा हूं। यह कक्षा की बात नहीं है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिस्थिति के विषय में मैं आपको बतलाऊं कि आज शासन का स्तर तो गिर रहा है लेकिन भ्रष्टाचार की बात ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। उसके लिऐ भारत सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी का नाम सन्थानम कमेटी था। सन्थानम जी एक प्रान्त के गवर्नर रहे हुये हैं और अच्छे कांग्रेसी नेता माने हुए हैं। उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उसमें उन्होंने एक जगह पर इस भावार्थ को लिखा है कि हम दावा कर सकें, हम दावे के साथ कह सकें कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है वह अतिशयोक्ति है परन्तु हम ऐसा दावा करने की स्थिति में नहीं हैं कि हम कह सकें कि शासन में भ्रष्टाचार नहीं है। इस भावार्थ का सन्थानम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। जो आज कथित गांधी भक्तों की सरकार है उसमें हर जगह भ्रष्टाचार घुस गया है। आप उस रिपोर्ट में यह देखें, जो शासन के द्वारा जो सरकार के द्वारा कमेटी मुकर्रर की गई उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है। इसी प्रकार से गांधीजी ने २१ मई, ४७ को चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था कि हमने स्वराज्य लेना सीखा है लेकिन स्वराज्य का रक्षण करना नहीं सीखा है। स्वराज्य तो आ ही रहा है उन्होंने १५ अगस्त के पहले २१ मई को इस भावार्थ को कहा था कि स्वराज्य आ रहा है, लेकिन उसकी रक्षा करना हमने नहीं सीखा है। अंग्रेजों की तरह बन्दूक की गोलियों से राज्य चला तो इसका मतलब होगा कि सेवा करने वाले व्यक्ति मालिक बन गये। ऐसा चलता रहा तो इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं यह कहने की हिम्मत रखता हूं, चेतावनी देता हूं कि एक युग आयेगा जब देश में बलवा हो जायेगा और लोग सफेद टोपी लगाने वाले व्यक्तियों को चुन चुन कर मारेंगे और शासन दूसरों के हाथ में चला जायेगा। हम जिन गांधीजी को राष्ट्रपिता मानते हैं, जिनकी लाईन पर चलने को कहते हैं उनकी चेतावनी की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर उस ऋषि की चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया तो वही होगा जो उन्होंने कहा। आज आप हमारे जीवन स्तर को देखिये। हमारे मंत्रियों का स्तर क्या है, किस ढंग से वह रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या उनका रहन-सहन है क्या खाते पीते हैं। कितना उनके पास में सामान है। मैं तो कहता हूं कि इस देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि एक आदमी के पास इतना सामान रहेगा, १० आदमियों के पास इतना सामान रहेगा। इतना मकान रहेगा और यदि उससे ज्यादा होगा तो वह जब्त कर लिया जायगा। अगर सारे हिन्दुस्तान में ऐसा कानून बना दिया जाय तो मन्त्री लोगों को ठीक तरह से रहना ही पड़ेगा। और जो लोग ऐशो आराम से रहते हैं उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। और जनता में और लोगों में यह भावना होगी कि हमारे लिए शासन चल रहा है, शासन हम सबकी फिक्र कर रहा है, हम सबकी चिन्ता कर रहा है, और शासन हमारा स्तर ऊंचा चढ़ाएगा और देश बराबर ऊंचा चढ़ेगा, नीचे नहीं गिरेगा। किसी को भी इन सब

(श्री फूलचन्द बाफना)
चीजों की चिन्ता नहीं हो। मैं चिन्ताविहीन शासन की मांग करता हूं। शासन के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा होना चाहिए कि किसी को भी किसी की चिन्ता नहीं हो। वह कब होगा, जब हमारे यहां पर व्यक्ति का निर्माण होगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहता हुँ कि व्यक्ति का निर्माण होना चाहिये, व्यक्ति के निर्माण की योजना होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्ति के निर्माण के लिए तो आप शुरु में कह चुके हैं। इसको बार बार कहने की क्या जरूरत है ?

श्री फूलचन्द बाफना: शुरू में कह चुका हूं। लेकिन फिर सारांश कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: दूसरे पाईन्ट के पीछे पहले का सारांश कहना जरूरी है यों ?

श्री फूलचन्द बाफना: बात ठीक है। मैं जिस वस्तु पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं, वह दुबारा कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह नियमों में वर्जित है इसलिए मैंने निवेदन किया।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार शासन व्यवस्था चले। नहीं तो आज बंगाल में एक चीज उठी है, जो घेराव आन्दोलन चल रहा है, यह न मालूम किस वस्तु की वहां पर प्रतिक्रिया है। यदि यह हवा राष्ट्र में फैल गई तो मेरा मानना है कि सत्ता में खलल पड़ जायगी आज भले ही कहते रहें कि हम ठीक कर रहे हैं, ठाक कर रहे हैं। लेकिन यदि आदमी कष्ट में होगा, मंहगाई भोगता रहेगा और दुःखी रहेगा तो ऐसा विस्फोट सारे भारत में हो सकता है। फिर देश में शांति नहीं रहेगी शांति अशांति में बदल जायेगी। अहिंसा हिंसा में बदल जायगी। और आज की चालू भावना नष्ट हो जायगी। आज वस्तु स्थिति यह है कि यदि हिंसा फूट पड़ी राष्ट्र में और खून खराबी हुई राष्ट्र में तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो आज जनता को विश्वास नहीं दे पाते, भरोसा नहीं दे पाते। तो घेराव आन्दोलन आज इस बात का संकेत है (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं यह बता देना चाहता हूं। केवल दो मिनट और मैं लूंगा। मेरा मानना है कि भारतवर्ष में प्रान्तवाद, भाषावाद आदि आदि की जो कट्टरता है उसको हर जगह समाप्त करना है तो प्रान्त के स्तर पर मंत्री मंडल, विधान सभा आदि की सत्ता नहीं रहनी चाहिए। केवल केन्द्र की ओर से दो तीन व्यक्तियों (सलाहकारों) के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार प्रान्त में काम करना चाहिए। इससे एक तरफ लाखों करोडों रुपये का खर्चा समाप्त हो जायगा, करोडों की बर्बादी बच जायगी और देश प्रगति भी करेगा। आज देश के अन्दर पराधीनता बढ़ रही है, इसके साथ ही देश में एक चीज और बढ रही हैं, देश में न्यूसेन्स वेल्यू बढ़ रही है। जो ज्यादा न्यूसेन्स कर सकता है, जो ज्यादा तिकड़म कर सकता है उसकी कीमत आज बढ़ रही है, उसकी पूछ बढ़ रही है। मेरा निवेदन है कि देश में जो न्याय पर है वह कष्ट सहता है वह पीछे रहता है जो न्यूसेन्स और तिकड़म करता है वह आगे बढ़ता है। मेरा निवेदन है कि जो आज भला आदमी है वह पीछे है और वह ऐसा सोचता है कि जो आदमी बदमाशी कर सकता हैं, तिकड़म कर सकता है वही नेता

Page No.112

(श्री फूलचन्द बाफना)

बन सकता है। ये आज नेता की क्वालिफिकेशन्स हैं। तुलसीदास ने भी दुर्जनों से परेशान होकर कहा था।

प्रथमम् वंदौं दुर्जनम् ।
सज्जनम् तदंतरम् ।।

तुलसीदास जी के जमाने में भी ऐसी हालत थी क्योंकि मुसलमानों के जमाने में जुल्म था।

इसी प्रकार विहारी ने कहा है।....—

श्री उपाध्यक्ष: इसका मतलब यह हुआ कि यह चीज बढ़ी नहीं है। पुराने जमाने से चली आ रही है।

श्री फूलचन्द बाफना: आज उसकी अति हो गई है। मेरी तो एक ही बात है कि व्यक्ति का निर्माण होना चाहिये। व्यक्ति का निर्माण जितना कम होगा उतना ही राष्ट्र नीचे जायगा। आप भले ही शासन की कितनी ही तारीफ करते जाइये परन्तु न्यूसेन्स वेल्यू बढ़ने से तो वह नीचे ही गिरेगा। इसको सिर्फ व्यक्ति के निर्माण से ही ठीक कर सकते हैं। यह बात तो ठीक है कि और ज्यादा लोग बोलेंगे, इसलिए मुझे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे यदि हजार बार भी कहने का मौका दिया जाय तो मैं तो यही कहूंगा कि व्यक्ति के निर्माण के बिना राष्ट्र गिरेगा।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने बजट पेश किया है उसकी मैं सराहना करता हूं। इसकी रूप रेखा काफी सुन्दर है और बजट के जरिये हम राजस्थान की दो करोड़ और २८ लाख जनता का भला करने जा रहे हैं। पहले बजट में ६।। करोड़ का घाटा था उसको देखते हुए अब ८ लाख के मुनाफे में इस बजट को छोड़ा है। यह सराहनीय बात है। लेकिन मैं खास मुद्दे की बात यह कहना चाहता हूं कि दो करोड़ २८ लाख जनता जो गांव में रहती है उसकी भलाई के लिये जो बजट में प्रावधान रखा है वह बहुत ही कम है और वह शुन्य के बराबर है। क्योंकि इस बजट के जरिये हम राजस्थान को हरा भरा बनाना चाहते हैं। वह इस टैक्स से बनना मुश्किल है। टैक्स से पैसा आवेगा और पैसों से यह हराभरा नहीं बनेगा। देश हमेशा अपने उत्पादन से आगे बढ़ता है। पैसा तो एक माप दण्ड है पैसे से उत्पादन नहीं बढ़ेगा क्योंकि देश में चार चीजें हैं जो देश का धन है।

(१) जमीन से पैदा होता है वह धन है।

(२) जो जंगलों से पैदा होता है वह धन है।

(३) कृषि धन है जो जमीन से पैदा होता है और उसमें खानें और कृषि आ जाती हैं।

इनको जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक आप दिनों दिन टैक्स लगाते चले जावें देश उन्नति पर नहीं आवेगा। इस लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज गांवों में लोग ८० प्रतिशत रहते हैं उनकी तरफ तवज्जह दी जाये। पिछली साल के बजट को देखते हुए मैं कहूंगा कि ज्यादा ध्यान दिया गया है शहरों पर। मगर इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उत्पादन बढाने के लिये कृषि पर ज्यादा जोर दिया जावे। जितनी देश में कृषि बढ़ेगी उतने ही भावों

(श्री रणजीत सिंह)

में गिरावट आवेगी। इसलिये खेती में सुधार होने चाहिये और किसानों को उसके लिये सुविधाएं उपलब्ध होनी जरूरी हैं। खेती में सुधार के लिये जो तकाबी लोन दिया जाता है वह बडे बड़े लोगों को ही प्राप्त होता है इसलिये इसमें परिवर्तन करना होगा। जितना ऋण तकाबी के लिये दिया जाता है वह किसानों को नहीं मिल पाता और आज तक का अनुभव बताता है कि वह किसानों के हाथों में नहीं जा कर बडे बड़े लोगों के हाथों में गया है। मेरा निजी १०, १२ सालों का तजुर्बा है। मैं प्रधान रहा हूं। मैं जानता हूं कि जहां कहीं भी किसानों ने अपनी तरक्की की है तो अपने हाथों से की है। सरकार की तरफ से यदि किसी को ऋण मिला हो तो बहुत मंहगा मिला है और उसको वार बार घूमना पड़ा है उस ऋण को लेने के लिये। अगर कोई ऑन स्पोट जाकर तकाबी दी गई है तो वहां जरूर उत्पादन बढ़ा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि खेती के लिये किसानों को ऋण दिया जावे और वह पूरी मात्रा में दिया जावे तो इससे उत्पादन बढ़ने की गुंजायश है।

दूसरी बात मैं पशुपालन के बारे में कहना चाहता हूं। जिस इलाके से मैं आया हूं वह राजस्थान का पश्चिमी इलाका है। वहां पशु-पालन पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि अगर वहां वर्षा अच्छी होती है तो एक फसल हो जाती है और नहीं होती तो लोग पशु-पालन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसमें पशुओं की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि पशु-पालन के कारण वहां के लोग बहुत धनाढ्य बन गये हैं इसलिये आपने ५ प्रतिशत बिक्री कर लगाया है। और वित्त मंत्री ने इसी आधार पर यह बिक्री कर लगाया है। आंकड़े जो दिये गये हैं वे पशु-पालन विभाग के बहुत लम्बे चौड़े दिये गये हैं। जितना ऋण दिया आंकड़े जरूर दिये होंगे और उनके आधार पर आपने यह किया होगा। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि किसान अभी तक ऐसा शक्तिशाली नहीं बना है। क्योंकि अगर एक अकाल पड़ जाता है तो वह तीन साल पीछे रह जाता है। उनके पास उस इलाके में मवेशी ज्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा उस इलाके में, आप उसी इलाके में रहने वाले हैं तो जब अकाल पड़ता है तो लोग अपने मवेशियों को लेकर मालवे की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पर उनके पशुओं के पालन का साधन नहीं होता है। आपने उन लोगों को अपने पशुओं के साथ भटकते हुए देखा होगा। अगर वे शक्तिशाली होते तो मालवे नहीं जाते। वे मालवे अपने पशुओं को बचाने के लिये ले जाते हैं। फिर अगर एक साल बाद में अकाल पड़ जाता है जैसा हुआ करता है तो वे फिर पिछड़ जाते हैं। इसलिए आपने जो ५ परसेन्ट का टैक्स लगाया है उसको किसान सहन नहीं कर सकेगा। अगर आप जिसको प्रगतिशील देश कहते हैं, ऐसा टैक्स लगावेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। उनकी यह हालत होगी कि वे इस टैक्स से बचने के लिए चोरी करने के तरीके सीखेंगे जब उनकी मवेशी बिकेगी तो वे छुपाने की कोशिश करेंगे। आज हमेशा हम देखते हैं कि किसान की नियत साफ रहती है। चोरी की व्यवस्था हमेशा शहरों तक सीमित है।

(श्री रणजीतसिंह)

दुकानों पर टैक्स लगता है उससे बचने के लिये अलग अलग तरीके लोग निकालते हैं। गांवों के आदमी जिनके दिल साफ हैं उनको आप चोरी करना सिखावेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मवेशियों पर जो टैक्स लगाया गया है वह वाजिब नहीं है।

और दूसरा मेरा निवेदन है कि पानी पर आये हुए आंकड़ों को देखकर मुझे मालूम हुआ कि शहरों और गांवों में भिन्नता है। गांवों में हम देखते हैं कि १० और १५ मीलों से पानी लोगों को लाना पड़ता है और रात और दिन एक व दो आदमी उनके घर के पानी लाने में ही लगे रहते हैं। उस इलाके में ५०० फुट गहरे कुए हैं। और वहाँ पर भी १०, १५ मील की दूरी से लोगों को पानी लाना पड़ता है। उनके लिये हम १५ वर्षों में भी पानी की व्यवस्था नहीं कर सके और हम कहते हैं कि हम गांवों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। वहां पर आज तक आप पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि पानी की तंगाई है। मैं भी मानता हूं कि पानी की तंगाई होगी। पर आज पानी और बिजली और हवा आपको कितनी आसानी से मिलती है वह गांव वालों को नहीं मिलती और वे लोग १५ मील की दूरी से पानी लाते हैं। जितना फ्लश में पानी डालते हैं उतना पानी पर हैड हमारे इलाकों में दे दें पीने को तो हम समझेंगे कि हम खुशहाल हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसमें आपने पैसा रखा है वह बहुत कम रखा है। पूरे राजस्थान के गांवों में पानी के लिये आपने ८० लाख रुपया रखा है। जब हम शहरों की तरफ देखते हैं तो आपने म्युनिसिपेलिटीज को एक बहुत बड़ी रकम माफ कर दी है और म्युनिसिपेलिटी बिलों का भुगतान नहीं कर सकती तो ११। करोड़ वापिस अदा कर देगें। ऐसा बना रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन करने का मतलब यह था कि गांवों की तरफ भी वित्त मंत्री का ध्यान गया क्या कि जिन लोगों ने तकाबी ली हो और उनके कुओं में पानी कड़वा निकला हो या नहीं निकला हो उनको भी माफ करने का प्रश्न उनके दिमाग में कभी आया क्या? शहरों में सड़कें हैं, शहरों में ज्यादा सुविधाएं हैं और टैक्सों के बोझ का प्रश्न है वह गांव वाले ज्यादा भुगतान करते हैं। आप कहते हैं कि जो बिक्री कर लगता है वह आप पर नहीं लगता है। मैं यह कहूंगा कि वह तो हम पर ही लगता है क्योंकि भुगतान तो देने वाला ही करता है। इसलिये जितने भी टैक्स हैं वह हम देते हैं और शहरों पर ज्यादा खर्च होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और गांवों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सारी योजनाएं कागजों में ही रह जावेंगी। आप आंकड़ों के जरिये बताते रहें, देश आगे बढ़ना नामुमकिन होगा।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि शहरों में छोटे व्यापारियों को छूट दी है, पन्द्रह, बीस हजार के ट्रान्जेक्शन पर छूट दी है। इससे चोरी की भावना बढ़ेगी। दूसरी तरफ गांवों में आपने क्या किया है, टैक्स लगाया है, जो ७५ से ज्यादा बीघोड़ी देता है, उसको आपने सवाया कर दिया है, उसे अब सवाई बीघोड़ी देनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि शहरों में लोग होशियार हैं, वे एक फर्म के तीन, चार रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, बाप के नाम, भाई के नाम, दूसरे भाईयों के नाम, बेटे के नाम अलग

(श्री रणजीतसिंह)

अलग हो जायगा और ये लोग इस तरह से टैक्स से बच जायेंगे। पर गांवों में कई फेमिलीज़ साथ साथ रहती आई हैं, गांवों में कई फेमीलीज आपको ऐसी ऐसी मिल जायेंगी जो कि चार चार, पांच पांच पीढ़ी से शामिल रहती हैं। उन्होंने सेटलमेंट के समय में शामलाती खाते दर्ज करवा दिये और उन फेमिलीज़ के खाते एक ही आदमी के नाम पर दर्ज हो गये। एक कुटुम्ब में पन्द्रह बीस फेमिलीज़ सम्मिलित रूप से साथ रहती हैं तो कागजों के अनुसार एक एक फेमिली के हिस्से में पचास साठ बीघा जमीन आयेगी पर क्योंकि शामलाती खाता है इसलिये उनको बीघोड़ी सवाई देनी पड़ेगी। उनके अलग अलग खाते होते तो एक एक के नाम पांच पांच, छ-छः रुपया पांती आता।

आप कह सकते हैं कि वे लोग जमा-बन्दी करवा लें पर आपको मालूम है कि जमा बन्दी करवाने के लिये उनको एस. डी. एम. के पास जाना पड़ता है और एस. डी. एम. का आफिस उन लोगों के गांवों से बीस-बीस, तीस-तीस मील दूर पड़ता है उनको वहां जाने में मुसीबत होती है और दूसरी कई प्रकार की दिक्कतों का उन गरीबों को सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जब एस. डी. एम. देख ले कि कई फेमिलीज़ शामिल रहती हैं तो उनको सवाई बीघोड़ी से मुक्त कर दें।

इसके अलावा सीमेंट पर जो टैक्स आपने लगाया है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि गांवों में लोग पक्के चेनल्स बनाते हैं, टांके बनाते हैं उनमें सीमेंट लगती है, इसलिये सीमेंट पर टैक्स लगेगा तो इससे किसानों पर, गांवों में रहने वाले गरीबों पर बोझा बढ़ेगा। शहरों में लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स् बनाते हैं, वहां सीमेंट पर टैक्स लगेगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा पर गावों में सीमेंट पर टैक्स लगेगा तो गरीब और गरीब होते जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि सीमेंट पर जो टैक्स लगाया गया है, उस पर फिर से विचार किया जाय।

दवाइयों की व्यवस्था के लिये आपने अच्छा प्रबन्ध रखा ताकि शहरों में रहने वालों के लिये और शहरों में आने वाले गांव वालों को सुविधा मिल सके पर ज्यादा अस्पताल शहरों में हैं, गांवों में नहीं हैं। गावों में कहीं प्राईमरी हैल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, वहां दवाइयों का प्रबन्ध नहीं है। मैं जोधपुर से आया तो मैंने देखा कि वहां अस्पताल में आदमी पड़े पड़े चिल्ला रहे हैं और डाक्टर कोई तवज्जोह नहीं देता। गांव वाले एक मरीज ने डाक्टर को कह दिया कि मुझे दवा दीजिये तो डाक्टर ने उसका खाना बन्द कर दिया। मैं अभी जोधपुर से आया तो मैंने स्वंय ने देखा, मैंने पूछा कि इसका खाना क्यों बन्द कर दिया? खाना बन्द करने की क्या वजह है? तो डाक्टर ने कहा कि यह मेरे सामने बोल गया। मैंने डाक्टर को समझाया कि यह गांव का सीधा आदमी है, यहां खाना खाने के लिये नहीं आया है, यह अपने इलाज के लिये आया है। आज यह बीमार नहीं होता तो आपके यहां इस तरह नहीं पड़ा रहता अपने घर पर ज्यादा आराम से रहता। मैंने उनसे कहा कि इन लोगों के साथ अच्छा बरताव करना चाहिये। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि गांवों से जो लोग शहरों के अस्पतालों में इलाज के लिये आते हैं उनके साथ अच्छा बरताव होना चाहिये, उनके लिये दवाई आदि का अच्छा

(श्री रणजीतसिंह)

प्रबन्ध होना चाहिये और उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिये।

चांदी पर आपने टैक्स लगाया है, चांदी गरीब आदमी ही ज्यादा खरीदते हैं, इस पर टैक्स लगायेंगे तो गांवों में रहने वाले लोगों में यह भावना पैदा होगी कि जो चीज हम लोगों के काम में आती है, जो चीज हम खरीदते हैं, उस पर सरकार टैक्स लगा देती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्रीजी इस पर फिर से विचार करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, वह यह कि खेती के लिये आप सब्सीडाइज करें। किसी किसान ने एक कुआं खुदवाया और वह कुआं अधूरा ही रह गया, उस हालत में आप उससे किश्तें वसूल करते हैं तो वह कहां से किश्त चुकायेगा, जब कि उसका कुआं पूरा ही नहीं हुआ है, उससे वह अपनी जमीन ही सिंचित नहीं कर रहा है ?

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्रीजी इन बातों पर फिर से विचार करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो यह बजट पेश किया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। यह बजट है इसका भार गांवों में रहने वाले किसानों पर ज्यादा पड़ेगा। यह बजट राजस्थान के गरीब नागरिकों पर ऐसा साबित होगा कि जैसे यह बजट नहीं बल्कि बम है। आज गरीबों की हालत ऐसी है कि इस भयंकर अकाल में न तो उन्हें खाने को मिलता है और न पीने को मिलता है। लोग लम्बे लम्बे भाषण देते हैं सरकार की तरफ से। मैं कोलायत तहसील के बारे में बता देना चाहता हूं कि ८४ गांव वहां अकाल ग्रस्त घोषित किये गए हैं, पर बड़े दुख की बात है कि वहां केवल ४ कैम्प खोले गए हैं और ९०० आदमी वहां मजदूरी पर लगाये गये हैं। चुनावों के दिनों में सात-आठ केम्प वहां चलते थे, वे केम्प बन्द कर दिये गए। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा उन टैक्सों का विरोध करता हूं जो टैक्स काश्तकारों पर लगाए गए हैं, लगान के बारे में जो टैक्स लगाया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। काश्तकार इस बात को देखता था कि कब हमारा देश आजाद हो और हम सुख की सांस लें, आजादी को हासिल करने में राजस्थान के किसानों व हिन्दुस्तान के किसानों ने ज्यादा कुर्बानियां कीं और हमारा देश आजाद हुआ। पर किसान जो सपने लेता था वे पूरे नहीं हुए, आप वे दिन भूल गए। जिन लोगों ने आजादी में हिस्सा लिया उनको क्या मिला उल्टे टैक्सों से उनकी कमर तोड़ दी गई है। आज किसान की हिम्मत नहीं कि वह खेती करने की हिम्मत करे, पशु-पालन की हिम्मत करे। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इन टेक्सेज़ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज आजादी के बाद भारत में, राजस्थान में किसान से अगर लगान लिया जाता है, तो वह किसान पर कलंक है।

श्री उपाध्यक्ष : किसान पर या सरकार पर ?

Page No.117

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : दोनों पर है। जो किसान भगतसिंह जैसे वीर आजादी के लिए फांसी पर लटके, इसलिए नहीं कि किसान पर लगान लगे। आप राजाओं के नाम लेते हैं और राजाओं के साथ बैठते हैं और जागीरदारों की मदद करते हैं। अगर राजस्थान में कोई राजा है या महाराजा है या नवाब है तो मन्त्री महोदय ही हैं जो कि आज १५ साल से इस राजस्थान के राजा या नवाब या जागीरदार बनकर बैठे हैं। आज किसान को तकलीफ के लिए सरकार जिम्मेदार है...

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अगर हम राजा हैं तो आप छुटभाई हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं छुटभैया हूं या नहीं हूं इसमें दो राय नहीं लेकिन ये × ×, हैं। ये किसान के नाम पर लंबे भाषण देते हैं। लानत है ऐसी सरकार को। मैं सरकार को चेलेंज करता हूं कि अगर इसी प्रकार किसान से टैक्स लेंगे तो सरकार फेल होगी। मैं आपका और वित्त मन्त्री का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। राजाओं के पानी के बारे में एक लाइन इस भाषण मे रखी गई है कि तीन राज घरानों का पानी बंद कर दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से समय ५ मिनिट और बढ़ाया गया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : खुशी की बात है कि तीन राज्य घरानों का मुफ्त पानी बंद किया। यह राजाओं पर भी कलंक था, उसको भी खुशी होनी चाहिये। वित्त मन्त्री ने उस कलंक को धोया है। इसी प्रकार सरकार पर कलंक है किसान से बीघोड़ी लेने का। वह कलंक भी अगर सरकार धोये तो खुशी होगी। लेकिन दुख की बात है कि सरकार का साथ देने वाले लोग भी ऐसे ही हैं जिनकी एक मिसाल भी बताइये जिन्होंने किसान का खुला पक्ष लिया हो परन्तु हंसराज जी जिनको आज तक मौका नहीं मिला है, न मालूम क्या कहेंगे।

अगर यह लगान का टैक्स जिन गरीब लोगों पर लगा है, वह अगर नहीं दूर हुआ तो सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सरकार को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं :—

(१) अगर राजस्थान में भ्रष्टाचार खतम करना है तो गरीब पटवारियों का वेतन बढ़ाना चाहिए।

(२) पुलिस के छोटे छोटे वर्ग के अधिकारियों के जो वेतन हैं, उसको ज्यादा कर देना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार खतम होगा।

(३) जो क्लर्क हैं उन लोगों के भी वेतन बढ़ने चाहिए जिससे गरीबों को सहायता होगी।

(४) मास्टरों का भी वेतन बढ़ाना चाहिए।

(५) अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों को नाम मात्र मजदूरी मिलती है, उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(६) किसान जो खुदकाश्त करते हैं। उनसे जो सरकार लगान ले रही है वह नाजायज है।

(७) विकास अधिकारियों की जो सरकार ने पोस्ट्स तोड़ी है वह तोड़ने से क्या होगा कि छोटे किसानों के विकास का काम रुक जायगा और इसलिए नहीं तोड़नी चाहिए।

(८) जिला परिषदों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलने चाहिये।

विकास अधिकारी का पद हटने से सीधा असर गांवों के काश्तकारों पर पड़ेगा। आपने सिर्फ एक अधिकारी किसान को दिया है कि वह नई योजना किसान को बताऐगा कि इस नए तरीके से खेती करें। दुःख की बात है कि उस एक अधिकारी को भी आपने वापस ले लिया। आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि जो सेक्रेटेरियट के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको हटा लें। एक अधिकारी हम लोगों का देते हैं, वह तो वहां रहना ही चाहिए।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, एक शब्द × × × का प्रयोग किया गया, उसको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह शब्द अन्पार्लियामेंटरी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह शब्द सदन की कार्यवाही से हटाया जाय। सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५.५ पर मंगलवार दिनांक ६-६-६७ के मध्याह्न पूर्व ११ बजे तक के लिऐ स्थगित हुई।)

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २१८ का उत्तर देखिए)

तहसील किशनगंज एवं शाहबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्गों पर जिस माध्यम से राशि खर्च की गई उसकी सूची

माध्यम जिसके द्वारा राशि खर्च की गई।	५४-५५	५५-५६	५६-५७	५७-५८	५८-५९	५९-६०	६०-६१	६१-६२	६२-६३	६३-६४	६४-६५	६५-६६	६६-६७	कुल योग	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
			कोलोनी के लिए							(यह खर्चा प्रत्यापत्र के आधार पर लिखा गया है)					
जिलाधीश कोटा	—	—	६११४८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	६११४८	कोलोनीज
,, ,,	२२५०	३३३००	५८६७५	१२५००	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१०६८४५	सिचाइ कूप
,, ,,	—	२०००	१५००	—	५००	—	—	—	—	—	—	—	—	४०००	पेय जल कूप
पंचायत समिति	—	—	—	—	—	४५००	२६००	२०२५०	५००	—	२०३५०	९८६७	—	५८३६७	सिंचाई कूप
,, ,,	—	—	—	—	—	६०००	३०८३	१७५०	३५५०	—	—	२७००	—	१७०८३	पेय जल कूप
,, ,,	—	—		—	—	—	६३३	५०५०० / २६५००	२२९४	—	—	—	—	७९८२७	गृह निर्माण
,, ,,	—	—	—	—	—	—	६६२	१०	१०२३	३८८	६७	१६०९	—	३७५९	छात्रवृत्ति
,, ,,	—	—	—	—	—	३०००	१९००	—	—	१६०००	—	२०००	—	२२९००	कृषि बैल क्रय
,, ,,	—	—	—	—	—	३०००	—	—	२०००	—	—	—	—	५०००	कुटीर उद्योग
,, ,,	—	—	—	—	—	१७६	६००	४८९	—	२२	—	—	—	१२८७	समाज शिक्षण केन्द्र
,, ,,	—	—	—	—	—	१२६५	३८०६	६८३९	७००६	३७२८	—	—	—	२२६४४	बेसिक स्कूल
,, ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	२०००	—	—	—	—	२०००	प्रशिक्षण एवं उत्पादन
,, ,,	—	—	—	—	—	—	—	—		—	३०००	—	—	३०००	सड़क निर्माण
,, ,,	—	—	—	—	—	—	—		—	२०००	—	—	—	२०००	तालाब एवं बाँध
स्वयं सेवी संस्था द्वारा	—	—	—	—	—	—	—	—	११९४४	१००३८	१३९४०	२१७९१	२३३३२	८०२३५	आश्रम स्कूल व छात्रवृति
विभाग द्वारा	—	—	—	—	—	—	१३८५०	०१५०	१९२००	१८४००	२४८००	२५८५०	३०३६०	१५२६१०	छात्रावास
,, ,,	—	—	—	—	—	—	—	२४८	५५२२	४०५८	४८०१	३३३८	१६६०	२३६५७	प्रेम मेला

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २३४ का उत्तर देखिये)

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या ६५ सा० नि० मं०

नाम मील	ठेके की तारीख	काम पूरा होने की तारीख
मील ०/० से ५/०	१-८-५५	२१-७-५६
,, ५/० से १०/०	१३-११-५८	१२-५-६०
,, १०/० से १३/१	१३-११-५८	१२-५-६०
,, १३/१ से १६/६	३-१-६१	२-८-६२

परिशिष्ट संख्या ३

(कृपया प्रश्न संख्या २३१ का उत्तर देखिये)

नाम उद्योग	अधिसूचना संख्या व दिनांक जिसके अन्तर्गत छूट दी गई	नाम वस्तु	छूट की अवधि
१	२	३	४
(१) पी० के० सी० फैक्ट्री, कोटा	टैक्स एफ० १४४ (१७) डी० एल० के०/६०, दिनाङ्क ३०-८-६३	साल्ट, लाइमस्टोन, लाइम	३१-१२-१९७० तक
(२) नागपाल कोटिंग मिल्स, कोटा	टैक्स एफ० १४४ (१७) डी० एल० के०/६०, दिनाङ्क ५-३-६४	कच्चा ऊन	३१-१२-१९७० तक
(३) नायलोन फैक्ट्री, कोटा	टैक्स एफ० १४४ (१७) डी एल के/६०, दिनाङ्क ३०-८-६३	केपसेलेक्टम	३१-१२-१९७० तक

१	२	३	४
(४) मल्टी मैटल्स, कोटा	टैक्स एफ० १४४ (१७) डी० एल० के०/६०, दिनाङ्क ३०-८-६३	कोपर, स्टील, जिन्क एलुमिनियम मिश्रित धातु ढले, छड़ एवं सलाखों की शक्ल में	३१-१२-१९७० तक
(५) राजस्थान सोप्स, कोटा	टैक्स एफ० १४४ (१७) डी० एल० के०/६०, दिनाङ्क २६-१-६५	सल्फर, कास्टिक सोडा, क्लोरिन, सल्फरिक एसिड, पेट्रोलियम कोर्क एलम या, एलमुनियम हाइड्रो-क्लाइड लाइम एवं लाइम स्टोन सोडि-यम कारबोनाइट ब्लीचिंग पाउडर, केलशियम क्लोराइट, जिक कारबोनेट, मैगनेशियम हाइड्रो-क्लोरिक एसिड, कारबन बाई सल्फाइड साल्ट।	३१-१२-१९७० तक
(६) राजस्थान स्टोन्स, कोटा	टैक्स एफ०/१४४ (१७) डी० एल० के०/६० दिनांक २३-४-६७	वुड पल्प एंड जिन्क	१-१०-१९७१ तक

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २४४ का उत्तर देखें)

सूची परिशिष्ट 'अ'

क्र० सं०	नाम सहकारी समिति	ऋण दिया गया	ऋण जो बकाया है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१.	बोराज ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	३२,१००.००	७०००.००	अवधि पार नहीं है।

१	२	३	४	५
२.	सेवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	५१,४००.००	१५,६१३.००	यह मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन किया जा चुका है। अभी अवधिपार नहीं है इसलिए वसूली नहीं की गई।
३.	बिचून ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	१६,४००.००	५,२४८.५१	वसूली जारी है एवं नोटिस जारी कर दिये गये हैं।
४.	सारून ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	२८,१००.००	१६,६००.००	अकाल घोषित होने के कारण यह ऋण मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन हो चुका है।
५.	ढाणी बोराज ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	४३,५५०.००	११,८००.००	अवधि पार नहीं है।
६.	बिचून चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	१,५७५.००	१,५७५.००	इस राशि में से केवल ६३०) रु० की ही किश्त तय हुई है जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या २४५ का उत्तर देखिये)

सूची 'अ'

अजमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष ५६-५७ से वर्ष ६६-६७ तक

निम्न प्रकार से राशि मकान सहायतार्थ हुए जिले के निमित्त खर्च की गई धन राशि की सूची:—

क्र० सं०	वर्ष	राशि दी गई
१.	५६-५७	७६,२००
२.	५७-५८	१,०२,०००
३.	५८-५९	१,८६,०५०
४.	५९-६०	८६,३५०
५.	६०-६१	४३,१००
६.	६१-६२	३७,५००
७.	६२-६३	३५,२५०
८.	६३-६४	७६,४००
९.	६४-६५	५७,७५०
१०.	६५-६६	५४,०००
११.	६६-६७	२०,०००

परिशिष्ट ५

अजमेर-जिले की पंचायत समितियों को गृह निर्माण हेतु १९५९-६० से १९६६-६७ तक दी गई धन राशि की तालिका

सूची "ब"

क्र०सं०	वर्ष	अजमेर	पिसांगन	किशनगढ़	मिनाय	योग
१.	१९५९-६०	—	११,७५०	१,०००	२६,७५०	३९,५००.
२.	१९६०-६१	१५,०००	११,७७५	२,२८,५००	२५,५००	८०,७७५
३.	१९६१-६२	३५,२५६	—	७५०	—	३६,०००
४.	१९६२-६३	७५०	७५०	७५०	—	१,५००
५.	१९६३-६४	१३,५००	९००	७५०	७५०	१५,९००
६.	१९६४-६५	१,७५०	१०,२२५	२,५५०	७५०	१५ ४७५
७.	१९६५-६६	१,५००	१२,६००	७५०	७५०	१५,६००
८.	१९६६-६७	—	३,४५०	१,०००	—	४,४५०

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या २२६ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Agriculture (CELL V) Department

No. F. 10 (2) Agr/V/67 Jaipur, dated 20th January, 1967.

The Director of Agriculture,
Rajasthan, Jaipur.

Subject:—Judgment by the Rajasthan High Court on writ petitions filed by the traders against implementation of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act 1961 and Rules made thereunder.

Sir,

I am directed to say that Government have considered the judgment of the Rajasthan High Court pronounced on the 22nd December, 1966 and have decided to constitute a committee to examine full implications of the judgment and to suggest necessary modifications in the Rules etc. Pending receipt of this report and final decision by the Government on it, I am to state that the functioning of the Market Committees may be held in abeyance.

Yours faithfully,
Sd/-
(B. Chakravarty)
Assistant Secretary to Government.

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या २२७ का उत्तर देखिये)

परबतसर महात्मा गांधी छात्रावास को समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये गये अनुदान की सूची (अ)

सन् १९६२-६३	३३७९.५० पैसे
सन् १९६३-६४	४९८३.७९ पैसे
सन् १९६४-६५	५५२०.७० पैसे
सन् १९६५-६६	११,२१४.७५ पैसे
सन् १९६६-६७	१६,५२०.०० पैसे

सूची (क)

परबतसर स्थित अनुसूचित जाति महात्मा गांधी छात्रावास में निर्धारित छात्र संख्या ४० है। सन् १९६६-६७ में ४० छात्रों को प्रवेश दिया गया जिनकी जातिवार सूची निम्न प्रकार है

मेघवाल	१४
मेघवंशी	२
बलाई	५
भांभी	१३
नायक	२
रैगर	४
	४०

सूची (ब)

महात्मा गांधी छात्रावास शाखा परबतसर सिटी
के
सहायक संचालन समिति के सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम	पद	पता
१	२	३	४
१.	श्री जेठमल जी बरबड़	अध्यक्ष	सा० मकराना, जि० नागौर
२.	,, दुलाराम जी राठी	उपाध्यक्ष	सा० रिड ,, ,,

१	२	३	४	
३.	श्री नन्दाराम जी केराया	मंत्री	सा० रोहन्डी	जिला नागोर
४.	,, बिरदाराम जी राजोरा	उप-मंत्री	सा० मकराना	,, ,,
५.	,, हनुमानराम जी नाइनौस्या	खजान्ची	सा० विदादा	,, ,,
६.	,, नारायणराम जी जौधा	सदस्य	सा० मडस्या	,, ,,
७.	,, तुलछाराम जी काटीवाला	,,	सा० लडाणा	,, ,,
८.	,, रामेश्वरराम जी राठौर	,,	सा० बोराबड़	,, ,,
९.	,, गोधाराम जी चित्या	,,	सा० परनादा	,, ,,
१०.	,, अगराराम जी जनागल	,,	सा० किवाध्या	,, ,,
११.	,, पूसाराम जी काबारिया	,,	सा० नादोली चांदात	,,
१२.	,, मंगलारामजी तुणगरना	,,	सा० रोहण्डी	,, ,,
१३.	,, रामदीन जी	,,	सा० मणपुर	,, ,,
१४.	,, चन्द्राराम जी पावना	,,	सा० मागोटा	,, ,,
१५.	,, चतराराम जी दुर्मतिया	,,	सा० ढाढ़ोता	,, ,,
१६.	,, मंगलाराम जी छीतरौल्या	,,	सा० खणिदा	,, ,,
१७.	,, मंगाराम जी राठी	,,	सा० नाणिदा	,, ,,
१८.	,, कानाराम जी बिदस्या	,,	सा० केसरोली	,, ,,
१९.	,, जबीराम जी प्योप्या	,,	सा० खोदपुरा	,, ,,
२०.	,, बलदेव जी मेरला	,,	सा० पीपलाद	,, ,,
२१.	,, छोगाराम जी बिक्कण्या	,,	सा० मेनाद	,, ,,

ह० नन्दाराम केराया,
मंत्री,
महात्मा गांधी छात्रावास शाखा,
परबतसर।

परिशिष्ट ८
(कृपया प्रश्न संख्या २२८ का उत्तर देखिये)
शक्कर वितरण तालिका

क्र० सं०	नाम वितरण कर्ता	~~नाम वितरण~~ सर्किल	निवासी
१	२	३	४
१.	श्री रामचन्द्र पुखराज	निम्बेड़ा कल्ला	निम्बेड़ा कल्ला
२.	ग्राम से० स० समिति, रायपुर	रायपुर	रायपुर

Page No.127

१	२	३	४
३.	श्री दासूराम चुन्नीलाल	रायपुर	रायपुर
४.	,, चम्पालाल सम्पतराज	रायपुर	रायपुर
५.	,, नथमल रामरतन	रायपुर	रायपुर
६.	,, अमोलकचन्द जैन	सिंगला	कुशालपुरा
७.	,, ,,	कुशालपुरा	,,
८.	प्रेमनगर उपभोक्ता, भण्डार	पिपलीया	पिपलीया
९.	ग्राम से० स० समिति, झुंठा	झुंठा	झुंठा
१०.	श्री दासूराम चुन्नीलाल	बांसिया	बांसिया
११.	ग्रा० से० स० समिति मोहररा	मोहररा	मोहररा
१२.	,, ,, करमावास	करमावास	करमावास
१३.	,, ,, बर	बर	बर
१४.	,, ,, लिलाबा		लिलांबा
१५.	श्री चन्दनमल जांगड़ा, पचानपुरा		पचानपुरा
१६.	ग्रा० से० स० समिति, लवाचा	लवाचा	लवाचा
१७.	श्री गोतमचन्द जैन	सबलपुरा	सबलपुरा
१८.	ग्राम से० स० समिति, कापुजा	कापुजा	कापुजा
१९.	श्री लालचन्द विजेराज	बाबरा	रायपुर
२०.	ग्राम से० स०, सेंदड़ा		सेंदड़ा
२१.	श्री नथमल रामरतन		,,
२२.	ग्रा० से० स० समिति बिरांटिया कलां		बिरांटिया कलां
२३.	,, ,, ,, खुर्द		बिरांटिया खुर्द
२४.	श्री बाबूलाल जैन	हाजीवास	हाजीवास
२५.	ग्रा० से० स० समिति	अमरपुरा	अमरपुरा
२६.	श्री गजराज अमरचंद	नानणा	नानणा
२७.	,, ,,	जटिवास	,,
२८.	,, हरनारायण	काठकिराणा	काठकिराणा
२९.	,, लालचन्द बोहरा	कलालिया	कलालिया
३०.	,, नथमल रामरतन	सेमेल	रायपुर
३१.	,, कुन्दनमल भंवरलाल	चांग	चांग
३२.	,, जीवनमल भन्साली	गिरी	गिरी

अनाज वितरण

१.	श्री नथमल रामरतन	सेन्दड़ा	रायपुर
२.	,, नथमल	सुनेल	,,

१	२	३	४
३.	ग्राम से० स० समिति, अमरपुरा	अमरपुरा	अमरपुरा
४.	श्री जसराव अमरचन्द	नानणा	नानणा
५.	,, कुन्दनमल भंवरलाल	चांग	चांग
६.	,, लालचन्द विजयराज	बाबरा	रायपुर
७.	,, चंपालाल संपतराज	कोटकिराणा	,,
८.	,, जीवराज मंसाली	गिरी	गिरी
९.	,, बाबूलाल जैन	हाजीवास	हाजीवास
१०.	,, पनालाल बोहरा	बिरांटिया खुर्द	बर
११.	ग्राम स० स० रायपुर	रायपुर	रायपुर
१२.	श्री दासूराम चूनीलाल	,,	,,
१३.	श्री चंपालाल सम्पतराज	,,	,,
१४.	,, नथमल रामरतन	,,	,,

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या २२६ का उत्तर देखिये)

१९६६-६७ के कोटड़ा रेंज के लकड़ी कोयले के दिये गये
ठेकों की सूची

क्र० सं०	नाम ठेकेदार	नाम जंगल
१	२	३
१.	श्री हसन पिता ईसा नागौरी नि० स्वरूपगंज	लादन १२ ए०
२.	चन्दुलाल अम्बालाल नि० अहमदाबाद	लादन १२ बी०
३.	मोहम्मद सरदार हाजी पीरजी नि० सिरोही रोड	तोरणा पार्ट २ नं० २१ ए०
४.	अमरलाल पिता राजाराम अरोड़ा निवासी सिरोही रोड	लादन १२ डी.
५.	श्री हनीफ पिता इब्राहीम नि० स्वरूपगंज	तोरणा पार्ट २ नं० २१ बी०
६.	श्री हसनमोहम्मद पिता हाजी दाउद नागौरी निवास स्वरूपगंज	तोरणा पार्ट २ नं० २१ सी
७.	श्री कासम पिता मोहम्मद नागौरी निवासी स्वरूपगंज	तोरणा पार्ट २ नं० २१ डी०

१	२	३
८.	श्री गुलाम मुस्तफा पिता हुसन नागौरी निवासी बासनी	तोरणा पार्ट २ नं० २१ ई.
९.	रमजान अली पिता मिसरू भाई निवासी एरनपुरा रोड	क्यारी २० (१)
१०.	इस्माइल पिता सद्दीक मेमण निवासी नाणा	क्यारी २० (२)
११.	हुसेन मोहम्मद पिता अब्दुलगनी निवासी स्वरूपगंज	पीपलमाल नं० १३ बी०
१२.	बद्री प्रसाद पिता रामकिशन दास निवासी स्वरूपगंज	हुर नं० १ ए०

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ५ जून, १९६७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५	१६	कालानीज	कालोनीज़
,,	२१	किया	दिया
६	६ व ११	पैंसे	पैसे
८	नीचे से ११	बाहेड़ा	बोहेड़ा
९	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
१०	४	का	को
,,	५	पसा	पैसा
,,	नीचे से ५	मसेज	मैसेज
१३	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
,,	नीचे से २	बनानें	बनाने
,,	,, ३	छावनी-सरानीखेड़ा	छावनी से रानीखेड़ा
१७	,, ६	रांव	राव
१८	१४	सार्वजनिक	सार्वजनिक
२२	७	क्रुया	कृपा
२२	१५	लामचन्द	लाभचन्द
३०	७	एकजेम्प्ट	एग्जेम्प्ट
३५	३	खरा	खर्रा
३५	नीचे से १२	जनावास्थ्य	जन-स्वास्थ्य
३८	नीचे से १	ग व	राव
४२	१०	मोहदय	महोदय
४२	११	बोगज	बोराज
४५	३	पष्ट	स्पष्ट

१	२	३	४
४८	नीचे से ६	श्री रार्मसिह	श्री रामसिंह
५०	,, ६	उत्थन	उत्थान
५१	शीर्षक	ारांकित	तारांकित
५३	१४	बातवीत	बातचीत
५३	२०	महरावल	महारावल
५४	१	नाराणसिंह	नारायणसिंह
५४	५	महरावल	महारावल
५४	१७	श्री नाराणसिंह	श्री नारायणसिंह
५६	५	खयाल	ख्याल
५६	७	श्रीरार्मसिह	श्री रामसिंह कुडी
६२	१०	काटड़ा	कोटड़ा
६२	नीचे से १	वर्जी	फर्जी
६२	,, २	ममूली	मामूली
६३	शीर्ष	(श्री देवेन्द्रकुमार मीना)	(वनमंत्री)
६३	नीचे से ५	ना।	जी हां।
६५	शीर्षक	अ०स०	अनुपस्थित
६५	शीर्ष	(श्री मूलचन्द कटेवा)	(पंचायत मंत्री)
६८	१४	स्वकायर	स्ववायर
७०	११	नगरपालिका अ	नगरपालिका
७२	१७	सताशचन्द्र	सतीशचन्द्र
१०५	१	डेवलप	डवलप
१०६	अन्तिम से ७	स्था	था
१०६	,, २	टक्स	टैक्स
११४	,, १०	इन्स्ट्री	इन्स्टी-
११६	१५	और डिफेक्टिव थे	....
११६	२०	एसी	ऐसी
१२१	५	खराद	खरीद
१२५	अंतिम से ७	तिना	जितना

१	२	३	४
१२८	१८	ज्यदा	ज्यादा
१२८	नीचे से २	ल	लें
१३०	३ व ५	घर्ती	धरती
१३३	४ व २३	सेहगल	सहगल
१३७	३	श्रो बिठलप्रसाद	श्री विट्ठलप्रसाद
१३७	अंतिम से ४	मोंप	सौंप
१३७	,, १२	अत्मा	आत्मा
१३६	शीर्षक	अग्रत्तर	अग्रेत्तर
१४२	४	दृष्टिक्रोण	दृष्टिकोण
१४५	१	ई	कई
१५८	अंतिम से १	जट	बजट
१५८	,, ६	सिृचाई	सिचाई
१६०	१४	हा	हो
१६०	१६	न ीं	नहीं
१६३	२	वेसे	वैसे
१७६	५	अलौट	अलाट
१७६	१७ व १८	गोबी	गोभी
१७८	६	नहों	नहीं
१८०	५	आएगा	आयेगा
१८०	१०	काय	कार्य
१८३	१०६	अजुन	अर्जुन
१८८	२	एक्सपडि	एक्स्पेंडि-
१८८	७	कोशशि	कोशिश
१८८	नीचे से ५	ता	तो
१६२	,, १६	आन	आने
१६३	,, २	इरीगेशन	इर्रीगेशन
१६६	,, ६	का	को
१६६	,, १४	इरिगेशन	इर्रीगेशन

१	२	३	४
१९९	५	खाल	खोल
२०१	नीचे से ७	वांत	बात
२०३	,, ७	उन्होने	उन्होंने
२१०	,, ७	ि न्यम	नियम
२१०	,, १४	समप्त	समाप्त
२१३	३	सिचाई	सिंचाई
२१४	२१	पांस	पास
२१५	१८	है	हो
२२०	५	हुं	हूं
२२०	२१	ऐ ।	ऐसा
२२१	अंतिम से ४	ठाक	ठीक
२२१	,, १०	ाक	कि
२२२	३	अज	आज
२३४	२	मत्री	मंत्री
२३४	अंतिम से. ११	ड्याढ़ा	ड्योढ़ा
२३५	५	ताड़ी	तोड़ी
२३६	१०	अन्पारलियामेंटरी	अन्पार्लियामेंटरी
२३७	परिशिष्ट ८	ंिचाइ	सिंचाई